(1100/CP/SPR)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आधा मिनट दीजिए। …(व्यवधान) सर, ज्यादा सप्लीमेंट्री एलाऊ कीजिए। …(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): स्पीकर महोदय, डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस से हो गई है। बीमारी बिहार के बाहर भी फैल रही है। सरकार क्या कर रही है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

…(व्यवधान)

MEMBERS SWORN – Contd.

WEST BENGAL – Contd.

Ms. Nusrat Jahan Ruhi (Basirhat)

Ms. Mimi Chakraborty (Jadavpur)

…(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): महोदय, बिहार में हर दिन बच्चों की मौतें हो रही हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कवैश्चन ऑवर।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन-41 - श्री कौशलेन्द्र कुमार।

…(व्यवधान)

(1105/SK/SRG)

(प्रश्न 41)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। आपने मुझे 17वीं लोक सभा में पहला प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैंने आपके माध्यम से मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष सवाल रखा है, उसमें कुछ परेशानियां भी हैं। मैं बिहार में नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं, खास कर हमारे यहां मछली पालन में किसानों ने काफी रुचि ली है। यह माननीय मंत्री जी भी जानते हैं और उन्होंने कई जगहों पर निरीक्षण भी किया था। अब तो वे इस विभाग के मंत्री भी बन गए हैं। मैं मछली पालन के किसानों की परेशानी के बारे में कहना चाहता हूं। आप किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे जिले से लगभग 370 लोगों को बाहर भेजकर ट्रेनिंग दी गई लेकिन जो मजदूर काम करते हैं, वे स्किल्ड नहीं हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। इसके चलते किसानों के लिए लगातार परेशानी बढ़ रही है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि क्या आप किसानों के साथ मजदूरों को भी स्किल देने का प्रयास करेंगे?

श्री गिरिराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन बातों को रखा है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन प्रशिक्षण का काम राज्य सरकार का दायित्व बनता है।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि देश में जब से माननीय मोदी जी की सरकार में नीली क्रांति, ब्लू रेवाल्युशन लाया गया है तब से 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और लगभग 47,0000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है।

प्रशिक्षण के लिए बिहार से जो प्रोजेक्ट आए हैं, उन प्रोजेक्ट में हम निश्चित ही सहायता करेंगे लेकिन संघीय व्यवस्था में हम सीधे किसी जिले को नहीं देते हैं। प्रशिक्षण हमारा कम्पोनेंट है, उस कम्पोनेंट के साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी दे रहे हैं, मार्केटिंग के लिए भी दे रहे हैं। हम फिश कल्चर के लिए सारी सुविधाएं राज्य सरकार के माध्यम से देने का काम करते हैं। नालंदा जिला

सचमुच में अग्रणी जिला है जहां आज 7.7 टन प्रति हेक्टेयर की उपज है। यह अच्छी उपज है, राज्य की उपज में लगभग 3 टन है। निश्चित रूप से नालंदा जिला अग्रणी जिला है। माननीय सदस्य राज्य सरकार के माध्यम से जो भी योजना भेजेंगे, उस पर हम काम करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि ब्याज मुक्त ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी का प्रयास है कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। इसके साथ यह भी प्रश्न जुड़ा है कि आप मछली पालन के किसानों से अगर ब्याज लेना चाहते हैं तो कोई सब्सिडी या जो इसे बाजार ले जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है?

हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कोई बड़ी हैचरी नहीं है। क्या सरकार मत्स्य पालन किसानों के लिए हर जिले में विकसित हैचरी की व्यवस्था करेगी?

श्री गिरिराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हैचरी बिहार में दी है। हैचरी के लिए भी पैसा दिया है, मार्केटिंग के लिए भी पैसा दिया है। मार्केटिंग के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसा दिया है। माननीय सदस्य राज्य सरकार से संपर्क करें, उस जिले को उस मद में जरूर सहायता मिलेगी।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने मात्स्यिकी अलग मंत्रालय बनाया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मात्स्यिकी विभाग को कृषि का दर्जा दिया जाए। महाराष्ट्र और देश के किसी कोने में जब किसान आर्थिक बोझ के कारण आत्महत्या करता है, तब राज्य शासन और केंद्र सरकार द्वारा सही ढंग से मुआवजा दिया जाता है। यदि कोई मछुआरा आर्थिक बोझ के कारण आत्महत्या करता है तो उसे किसी भी तरह से मुआवजा नहीं दिया जाता है।

मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सकें।

(1110/SK/UB)

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, जो मछुआरे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मर जाते हैं, उनको दो लाख रुपये दिए जाते हैं।

जहां तक फिशरीज़ एक्वाकल्चर के किसान हैं, मोदी जी की सरकार ने पिछली बार केसीसी की तर्ज पर तीन लाख रुपये देने का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि यह देश में ब्लु रेवाल्युशन में बहुत बड़ी क्रांति है।

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): The traditional fishermen of India find their livelihood by fishing in seas, rivers and lakes etc. selling fishery products. Approximately 18-21 per cent of the total population of the country depends upon fisheries sector and they are the most deprived population amongst us.

Hon. Speaker, Sir, my question is that whether the Government would take any initiative to introduce new fisheries policy for improving the socio-economic status of the fishermen and allied workers.

श्री गिरिराज सिंह: माननीय सदस्य इसे नजदीक से जानते हैं, उस वर्ग को बहुत करीब से जानते हैं, मैं यह बात जानता हूं। सरकारी की ओर से जो योजनाएं बनी हैं, उसके लिए मार्केटिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। हमने मछुआरों के लिए 918 डीप सी फिशिंग वैसल्स देने का काम किया है। 11.942 ट्रेडिशनल क्राफ्ट मोटराइज करने का काम किया है। 13457 नंबर के सैप्टिक किट भी दी है जो मेरिन फिशरीज़ में है। न्यु फिशिंग हार्बर भी तैयार किया गया है। फिशरीज़ के लिए नीली क्रांति में सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन मेरी भी कुछ लाचारी है क्योंकि हम राज्य सरकार के माध्यम से काम करते हैं। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट का प्रावधान रखा गया है। हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार से मिलकर बात करेंगे तो इसका निदान होगा।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करती हूं। I want to ask whether the Government has any policy on inland fish farming, if so, I would like to know about it.

My second question is that whether any such policy is applicable to fishing in rivers.

My third question is that whether any of the fish found in inland waters or rivers are in the category of Endangered or Critically Endangered.

श्री गिरिराज सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मत्स्य के उत्पादन में मेरिन फिशरी भी है, नदियां भी हैं और इनलैण्ड भी है। इनलैण्ड फिशरी में नए पोण्ड खुदवाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से लीभार्थी को 60-40 रेश्यो में और जिस कैटेगिरी में वे आते हैं, उस कैटेगिरी के अनुसार उन्हें लाभ मिलता है। उनके लिए सभी तरह की योजनाएं बनी हुई हैं। अगर किसी योजना के विषय में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

(इति)

(प्रश्न 42)

श्री राज कुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): मैं फतेहपुर सीकर क्षेत्र से आता हूं। यह पानी की किल्लत के लिए पूरी दुनिया में जगजाहिर है। वर्ष 1571 से 1585 के बीच में यह अकबर की राजधानी रहा है। अकबर पानी की कमी के कारण इसे छोड़कर चले गए थे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आलू की खेती कम पानी में होती है। क्या सरकार की कोई योजना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में आलू का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की है? अगर नहीं है तो कृपया आलू का प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया जाए ताकि किसानों का भला हो सके।

(1115/YSH/KMR)

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न अभी सप्लीमेंट्री प्रश्न के तौर पर पूछा है, प्रोसेसिंग लगाने की मांग जो कर रहे हैं, वह फूड मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। हम फूड मिनिस्ट्री से सम्पर्क करके कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, मगर आपका बेसिक सवाल था कि पानी की किल्लत वाले एरिया में खासकर फतेहपुर सीकरी एरिया में भारत सरकार की ओर से कोई प्रोविजन सरकार ने किए हैं। मैं आपके माध्यम से बहुत नम्रता से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कई योजनाएं इस क्षेत्र के लिए भी हैं, मगर आगरा जिले के लिए, पूरे देश के लिए अभी नहीं बता रहा हूँ। आगरा जिले के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागबानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत जो काम हो रहा है, पी.एम किसान योजना और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में जो काम हो रहा है, वे छ: योजनाएं आगरा जिले में भी काम कर रही है और आगरा के कुछ क्षेत्र में आई.सी.ए.आर. के माध्यम से समेकित खेती के लिए कुछ गांव में दूसरे मॉडल भी बनाए हैं। वहां जाकर आप कम सिंचाई वाले या ड्रॉउट आधारित किस्मों को, उनके प्रयोगों को भी देख सकते हैं।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): हमारे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार की क्या योजना चल रही है? माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' का एक नारा दिया है, जो बहुत चर्चित है। मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर एक योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन किस तरह चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो आगे सरकार इसके लिए क्या करने वाली है, इसमें तेजी कब आएगी?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी का जो नारा है, 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' और उनके अनुसंधान से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से आपके क्षेत्र में और पूरे देश में काम कर रही है, उसीके तहत मैं आपके क्षेत्र के जिले की डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, मैं जिला की डिटेल भी बता सकता हूँ, बाद में डिटेल दे दूंगा। लेकिन पूरे देश के लिए 2015-16 से लेकर 2018-19 तक 11 लाख 58 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज में लाया गया है और 9188 करोड़ रुपये इसमें निर्मुक्त किए गए हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I am aware that agriculture is a State Subject. But I would, through you, like to ask the hon. Minister this question, since in his reply he has mentioned he is doing special cases for water and seeds. The State where I come from is going through an agrarian crisis right now. Yesterday in a reply the hon. Minister in Maharashtra had said that there is a scheme for water for helping agriculture, and this question is on agriculture development, that there is a scheme called Jalyukt Shivar Yojana involving Rs.8,000 crore, and the Government itself has admitted that there has been some misuse of funds. I am aware that this is a State Subject, but there is an agrarian crisis going on. The Government of Maharashtra report says that there are eight suicides every day. This is not my report, this is the official reply of the Government of Maharashtra. So, I would like to ask the hon. Minister, when there is such an agrarian crisis and eight

people are committing suicides every day, when there is a such a big corruption charge admitted by the Government of Maharashtra, what will the Central Government do to save my State and the poor hardworking farmers of my State of Maharashtra?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा और उसमें एक आब्जर्वेशन दिया है। सरकार से वे जानना चाहते हैं कि ये अच्छत और सूखा वाले प्रदेश के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? मैं मानता हूँ कि जब सूखा घोषित होता है तो राज्य की ओर से सेन्ट्रल को उसकी सूचना आती है और उस पर जो कार्यवाही होती है, मेरे हिसाब से उसके बारे में आप भी भली-भांति जानते हैं।

(1120/RPS/SNT)

आपके प्रश्न की इंटेंशन कुछ योजनाओं में करप्शन चार्जेज के बारे में है। वे योजनाएं केन्द्र सरकार से ताल्लुकात नहीं रखती हैं, वे राज्य से संबंधित योजनाएं हैं, हमारे क्षेत्र से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनके बारे में आप राज्य सरकार से पता कर सकती हैं। इस बारे में अगर आपकी ओर से केन्द्र सरकार के सामने कोई दरख्वास्त आएगी तो हम छानबीन जरूर करवाएंगे। मैं इस सदन के माध्यम से, दो चीजों के लिए महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। पानी का बड़ा संकट महाराष्ट्र झेल रहा है, वहां इस प्रकार के जल शिविरों को रोककर, बरसाती पानी को रोकने का यदि किसी राज्य में सबसे अच्छा काम हुआ है तो वह महाराष्ट्र में हुआ है। यह बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि उसी काम में कहीं से किसी ने कुछ किया है तो इसका दोष सरकार पर डालने की बजाय, अगर आप उसकी जांच की बात करें तो वहां तक मैं भी आपके साथ सहमत हूं। सभी प्रान्तों के मेरे सभी साथियों को मेरा आह्वान है कि जल संकट के बारे में अगर हम सिर्फ सरकार की तरफ उंगली दिखाते रहेंगे तो यह संकट हल नहीं होगा। इसमें हम सभी को मिलकर, सभी राज्यों को मिलकर अपने-अपने क्षेत्र में वर्षा जल को संचित करने का काम करना चाहिए।

(इति)

(प्रश्न 43)

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जो भारत सरकार ने चालू की है, उससे किसानों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इस योजना में प्रीमियम पे करना किसानों के लिए अनिवार्य है, इसकी बजाय इसे स्वैच्छिक करना चाहिए। किसानों को जो पानी की सुविधा है, डैम की सुविधा है, बोरवेल की सुविधा है, कुएं की सुविधा है, उसको कभी क्लेम नहीं मिलता है। इसलिए इसे अनिवार्य करने के अलावा स्वैच्छिक करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी है, वह कारपोरेट ऑफिस से चलती है, ग्राउण्ड लेवल पर उसके पास कोई आदमी भी नहीं होता है। पूरा काम और क्रॉप कटिंग राज्य सरकार और भारत सरकार के कर्मचारी मिलकर करते हैं। हरेक राज्य ने, किसी भी राज्य ने योजना चालू करने के लिए पत्र भेजा है या नहीं? यह योजना राज्य सरकार को देने के लिए क्या केन्द्र सरकार कुछ सोच रही है?

श्री परषोत्तम रूपाला: अध्यक्ष महोदय, मोहनभाई मेरे ही राज्य के किसान नेता हैं और उस क्षेत्र से आते हैं, जो आज़ादी के समय सौराष्ट्र राज्य था, जिसकी राजधानी राजकोट हुआ करती थी। वह उसी एरिया से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा इस सदन के सामने उपस्थित किया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 1985 में देश में पहली बार लागू हुई और उस समय उसका उद्देश्य था कि किसान जो ऋण लेते हैं, उस ऋण को इन्श्योर किया जाए। ये सारी चीजें अभी सदन में बोलने का मेरा इरादा नहीं है, मगर वहीं से लेकर, नरेन्द्र भाई मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री बने, उन्होंने प्रधान मंत्री फसल योजना 2016 में इंट्रोड्यूस किया। वहां तक की यात्रा में इस योजना को मोडिफाई करने का सभी सरकारों ने प्रयास किया। 2016 में जब प्रधान मंत्री फसल योजना आई और मोहनभाई ने अभी जो प्रश्न उपस्थित किया है, उनकी मांग यह है कि किसानों का इसमें अल्टरनेटिव देना चाहिए। हम जो कम्पलसरी रूप से ऋण लेने वाले किसानों को

इसकी कवरेज में ले रहे हैं, उसके बारे में सरकार की क्या राय है। मैं बहुत विनम्रता से इस सदन के सामने और मोहनभाई की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में किसान संगठनों ने भी सीधे हमारे सामने डिमाण्ड रखी है, गुजरात किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भी रखी है, कई संसद सदस्यों ने भी रखी है, आपके द्वारा भी एक खत हमें मिला है, कई राज्य सरकारों की ओर से भी हमें सुझाव मिले हैं। इनकी सूची भी मेरे पास है। कई राज्य सरकारों की ओर से भी यह डिमाण्ड हमें मिली है। इन सभी का संज्ञान लेते हुए, कल ही हमारी सरकार की ओर से, हमारे सेक्रेटरी की ओर से सभी राज्य सरकारों को एक खत लिखा गया है। मैं इसका एक पैरा आपकी जानकारी के लिए पढ़ूंगा, ताकि आपके मन में जो विषय है, उसका समाधान हो सके :

> "To Principal Secretary,
>
> … Requests/representations have been received by the Government from various quarters including few State Governments and farmers' organisation to make the scheme voluntary. … optional for all farmers the Government is in the process of examining this request to further review/modify the schemes."

(1125/RAJ/RSG)

यह अपना स्टेटस है और हम ने सभी राज्यों के प्रमुख अधिकारियों और कृषि सचिवों से आग्रह किया है कि वे अपनी राय बता दें ताकि इस अहम मुद्दे पर ठीक तरह से रिव्यू कर सकें। जो आपके मन की बात है, उसी दिशा में हम एग्जामिन कर रहे हैं। हम शीघ्र ही इसका निपटारा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : सप्लिमेंट्री प्रश्न।

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट): अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न वही था कि किसानों के लिए वह अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होना चाहिए। आपने जो पत्र लिखा है, राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से भेज कर, वह अनिवार्य के अलावा स्वैच्छिक करे, ऐसी ही मेरी मांग थी।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रतापराव जाधव जी।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छी 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' बनाई है, मैं उनको किसानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह योजना बनाई गई है और इसमें लिखा है कि किसानों को फसल बीमा देने के लिए पिछले सात सालों में से पांच सालों का एवरेज निकाल कर, उस पर बीमे की रकम निश्चित की जाती है। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र हो या अलग-अलग राज्य हो, वहां सूखे की स्थिति होने से किसानों की एवरेज यील्ड घटती जा रही है। अगर एवरेज यील्ड पर बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा देने के लिए सोचेगी तो किसानों को अच्छा मुआवजा नहीं मिल सकता है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसानों का पिछले पांच सालों में, जिस साल अच्छी बरसात हुई होगी, जिस साल अच्छी उपज हुई होगी, जमीन ने कितनी उपज दी, किसानों ने कितनी मेहनत करके वहां पर उपज निकाली, ज्यादा से ज्यादा जो यील्ड पांच सालों में होगी, उसको नजर के सामने रख कर, उस हिसाब से बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अपने जिले की मालूमात की है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी को किसानों और सरकार की ओर से लगभग 175 करोड़ रुपये का इंस्टॉलमेंट गया है। पिछले तीन सालों से पूरे बुलढाणा जिले में सूखा पड़ा हुआ है। इस साल किसानों को सिर्फ 56 करोड़ रुपये का क्लेम मंजूर हुआ है। यह योजना सिर्फ कंपनियों के लिए चलाई जा रही है या किसानों के लिए चलाई जा रही है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

पहला सवाल था कि इसको ऐच्छिक बनाना चाहिए, कम्पलशन नहीं करना चाहिए।

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है तो स्वैच्छिक वाले प्रश्न का जवाब विस्तार से दे दिया है कि सभी राज्यों से हमारे पास प्रजैंटेशन आए हैं, उसके उपरान्त हम ने प्रोएक्टिव बन कर सभी राज्यों से उनकी राय मांगी है। वह राय आ जाने

के बाद, हम इसके बारे में त्वरित निर्णय लेंगे। अभी खरीफ के सीजन में यही योजना लगेगी और आगे के सीजन के लिए सोचा जाएगा।

आपका सवाल था कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में जो थ्रैशहोल्ड गिना जाता है, वह सबसे अच्छे साल का गिनना चाहिए और यह पिछले साल के आधार पर नहीं गिनना चाहिए। मैं आपकी एवं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसका प्रॉसिजर ही ऐसा है कि जिस साल का बीमा हम मंजूर करने जा रहे हैं, हम उसके पहले के सात सालों का डेटा लेते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद भी आपकी कोई क्वैरी होगी तो हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। उन सात सालों में से वे पांच साल चुने जाएंगे जो सबसे अच्छे हों। उनमें से जो कमजोर होंगे, वे निकाल दिए जाएंगे और उन पांच सालों के सबसे अच्छे डेटा का एवरेज निकाल कर, उसको थ्रैशहोल्ड माना जाता है और उन्हीं के साथ इसी साल का जो प्रोडक्शन होता है, इनको मिला कर गणना की जाती है। हमें किसानों की ओर से इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी, आपका कोई सुझाव है तो आप हमें भेज दें।

(इति)

(1130/RK/IND)

(Q. 44)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, in the brief reply given, the Minister has admitted that the proposal for setting up a Central Agriculture University in Meghalaya will be there. It was initiated in 2009. In spite of the fact that the Meghalaya Government has already handed over 200 acres of land to the Central Government, the University has not come up till now. May I know from the hon. Minister the reason behind the university not coming up there?

कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना सही है कि वर्ष 2009 के समय योजना आयोग की प्लानिंग में मेघालय में सैंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आरम्भ की जाए, ऐसा विषय था। यह विषय प्रमुख रूप से इसलिए खड़ा हुआ था, क्योंकि इम्फाल यूनिवर्सिटी के कार्यक्षेत्र में नागालैंड नहीं आता था। इसलिए नागालैंड मेघालय को मिलाकर अलग से एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, यह बात इसके मद्देनज़र रखते हुए तय हुई थी। लेकिन बाद में वर्ष 2016 में इम्फाल यूनिवर्सिटी का एक्ट संशोधन हुआ और उसमें नागालैंड को जोड़ दिया गया। अब नागालैंड उसमें जुड़ गया है और इम्फाल में स्वाभाविक रूप से पूर्व से ही सैंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसलिए यह सोचा गया कि अब नागालैंड उसमें शामिल हो गया है इस वजह से इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पिछले दिनों मेघालय के मुख्य मंत्री आए थे, उन्होंने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने आग्रह किया था और जो पत्र दिया है, उसकी हम जांच कर रहे हैं।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): The hon. Minister of State for Agriculture came to Meghalaya in 2016 and the Hon. Union Minister for Agriculture came to Meghalaya in July, 2018. When they came to Meghalaya,

they assured the Government of Meghalaya that a university will be set up very soon. Will the hon. Minister assure, through you, the House that the university will come up as per the promises made by the earlier Ministers?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष जी, सदस्य की भावना का मैं आदर करता हूं। सामान्य तौर पर हम सभी जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं। अगर सांसदों से पूछा जाए, तो हर सांसद की इच्छा होती है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे क्षेत्र में हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी सांसदों के क्षेत्र में यह संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने और आईसीएआर ने विचार किया कि जो 15 क्लाइमेट जोन्स हैं, पहले हम उनमें यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अभी तक तीन यूनिवर्सिटियां इस प्रकार की आरंभ की गई हैं, जिनमें इम्फाल भी है और कुछ समय पहले झांसी यूनिवर्सिटी आरम्भ की गई है। जब मंत्री जी गए होंगे, उस समय जमीन मिल गई थी, इसलिए उस समय उन्होंने कहा होगा, लेकिन वहां एग्रीकल्चर कालेज आरम्भ कर दिया गया है। उस कालेज में 18 छात्रों की संख्या है। मैं समझता हूं कि इम्फाल यूनिवर्सिटी से यह एरिया कवर हो सकता है इसलिए उस समय यह सोचा गया था।

(इति)

(प्रश्न 45)

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष जी, नेशनल सैम्पल सर्वे ओर्गेनाइजेशन की असेस्मेंट रिपोर्ट के अनुसार आंशिक तौर पर कुछ चुनौतीपूर्ण कारण हैं, जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अनाज के लिए अपर्याप्त बाजार और संग्रह केंद्रों की कमी, उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और संग्रह सुविधा की कमी, सामाजिक शुद्ध सुरक्षा कार्यक्रम का चावल और गेहूं तक सीमित होना, मूल्य निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में सूचनाएं उपलब्ध न होना आदि।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए चुनौतीपूर्ण कारणों के सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे पूरे देश में किसानों को एक-समान न्यूनतम मूल्य प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो?

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है और वे जानना चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे किसानों को उपलब्ध हो। मुझे बहुत नम्रता के साथ और बहुत गौरव के साथ सदन में बात रखनी है कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होते थे, तो जो कारण माननीय सदस्य ने बताया, उसके अलावा भी कई कारक सीएसीपी द्वारा जांचे परखे जाते हैं और उसी के आधार पर मूल्य तय होते थे। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जब इस विषय को हाथ में लिया, तब पहली बार इसे नीतिगत स्वरूप देते हुए इनकी लागत के ऊपर 50 प्रतिशत का मुनाफा देने के बाद ही उसका मूल्य तय होगा, इसका निर्णय किया।

(1135/VB/PS)

इसके चलते अब किसानों को उनकी लागत के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर ही मूल्य निर्धारित करने की नीति बन गई है, जो देश के किसानों के हित में लिया गया है। मैं मानता हूँ कि यह मेरी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री द्वारा तो लिया ही गया है, लेकिन यह अभी तक की सरकारों में लिए गए कदमों में से श्रेष्ठ कदम है।

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि समय-समय पर प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर यह साबित हो चुका है कि बिचौलिए और सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ के कारण किसानों को अपने उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं होता है और वे इस सांठगांठ का शिकार होते रहते हैं, जबकि सरकार को इस बात की जानकारी भी होती है। लेकिन पता नहीं क्यों, सरकार उच्च अधिकारियों के इस नेक्सस को तोड़ने में असमर्थ है।

अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कदम उठाने का विचार है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके ताकि किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके।

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस प्रकार से खरीद का प्रोग्राम लागू होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अब किसानों के एकाउंट में ही पैसे जाते हैं। अब वह पैसा किसी और एजेंसी के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसमें किसान का बैंक एकाउंट, आधार कार्ड आदि की जानकारी लेने के बाद उसका माल प्रोक्योर होता है और माल प्रोक्योर होने के बाद जब वह गोदाम में पहुँच जाता है, तो उसकी रसीद मिलने के बाद उसके एकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिये जाते हैं। इसलिए अब बिचौलिए वाली बात तो खत्म हो गई है। फिर भी, यदि सांसद महोदय के संज्ञान में किसी विशेष मंडी की या किसी किसान की समस्या है, वे मुझे बताएँगे, तो मैं अवश्य इसकी जाँच करवाऊँगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ क्योंकि पार्ट-सी में इस प्रश्न का जो रिप्लाई दिया गया है, वह कम्प्लीट नहीं है। उसी के ऊपर मेरा प्रश्न आधारित है।

Is the Government considering to operate price support scheme which is now under an umbrella scheme on an automatic basis for the crop decided between the Centre and States, with provision for farmers traceability? Is the

Government aware that insistence for prior approval and restrictions related to qualities reduce the efficacy of PSS? It is not done in the case of paddy and wheat. Prior approval of the Government of India for every season does not lead to credibility to the farmer on procurement of crops under PSS and it does not provide incentives to diversify from paddy or wheat into other cereals, oil seeds and pulses.

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यश्री ने बताया कि हमारे जवाब में उनको कमी मालूम हो रही है। माननीय सदस्यश्री बहुत ही विद्वान सांसद हैं, यह मैं जानता हूँ और उनका एकेडमिक एक्सपीरिएंस भी है। मैं अपने अधिकारियों के साथ बिठाकर इनका मार्गदर्शन प्राप्त कराने की एक व्यवस्था करा दूँगा। मगर अभी जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, उनमें आपको पता है कि क्वालिटी का जो रिस्ट्रिक्शन है, उसे रखना थोड़ा जरूरी भी है। यदि हम इसे नहीं रखेंगे, तो इसमें मालप्रैक्टिस होने की भी संभावनाएँ रहती हैं। इसलिए वे रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे ही। लेकिन किसी भी चीज के प्रोक्योरमेंट के लिए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार की ओर प्रस्ताव आता है, तो हम बिना विलम्ब किये उसकी मंज़ूरी दे देते हैं।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली के किसानों का मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके आपका धन्यवाद।

दिल्ली भारत की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की एक अज़ीब-सी स्थिति है। जैसे आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। पूरे देश में लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। वैसे ही उत्पादन लागत का डेढ़ गुना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वह दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। आज भी दिल्ली के 80 गांवों में खेती होती है। दिल्ली के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए झज्जर मण्डी में जाना पड़ता है। दिल्ली के नज़फगढ़ मण्डी में किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं।

(1140/PC/RC)

लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन लगाए थे कि हम समर्थन मूल्य देंगे, मगर चुनाव खत्म होते ही वे अपनी बात से मुकर गए। ऐसे ही पीएम-किसान योजना में पूरे देश में किसानों को छ: हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को उसकी एक भी किश्त नहीं मिली है। ऐसे ही दिल्ली के किसानों को पेंशन योजना का लाभ, जो प्रधान मंत्री जी ने किसानों को पेंशन योजना दी है, क्या दिल्ली के किसान किसी गिनती में नहीं आते?

अगर दिल्ली की सरकार किसानों को लाभ नहीं देना चाहती, तो हमारी भारत सरकार दिल्ली के एलजी से बात करे। कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए जिससे दिल्ली के किसानों को भी पूरे भारत के किसानों जैसा लाभ मिले। दिल्ली में वर्ष 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म कर दिया था। अभी तक केजरीवाल सरकार ने उसको लागू नहीं किया। अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के किसानों को न्याय मिलेगा?

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठाया, यह बहुत गंभीर नेचर का सवाल है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, आप भली-भांति जानते हैं कि कृषि राज्य का सब्जैक्ट होने के कारण हम जो भी योजनाएं लागू करते हैं, वे राज्यों के माध्यम से ही लागू कर सकते हैं। अभी तक हमारा पिछला अनुभव ऐसा भी रहा है कि कई राज्यों से पीएम-किसान का डेटा सेंट्रल को उपलब्ध नहीं हुआ था। इसके चलते हम इनको बैनिफेट नहीं दे सकते थे, मगर अभी-अभी हमारे पास जानकारी आ रही है कि उसमें जिन राज्यों ने पहली किश्त के समय डेटा नहीं भेजा था - उसका जो भी कारण होगा, मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं - अब उन राज्यों की ओर से डेटा आना शुरू हो गया है।

मैं अपने विभाग की ओर से इन तीनों चीज़ों के लिए - आपके किसानों को मूल्य वर्धित दाम मिले, एमएसपी का लाभ मिले, पीएम-किसान योजना का बैनिफेट मिले और पेंशन की योजनाओं का बैनिफेट भी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे किसानों को कैसे मिल सकता है, उसके बारे में हमारी ओर से क्या हो सकता है, हम निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर आपकी जानकारी में रखेंगे।

(इति)

(प्रश्न 46)

श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं हृदय से आभारी हूं अपने यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, जिनकी कृपा से आज विश्व के इस लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में मुझे खड़े रहने का मौका मिला।

महोदय, आज गाय और गोवंश के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदर्शी माननीय प्रधान मंत्री जी ने पशुपालन को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गाय और गोवंश के संरक्षण हेतु गऊपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को राज्य सहायता देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा? इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और गऊपालन को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, सचमुच में देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आज देश में जितनी हम क्रॉप्स से आमदनी करते हैं, उससे ज़्यादा हम दूध से आमदनी कर रहे हैं। हम गाय का संरक्षण कर रहे हैं। मोदी जी की पिछली सरकार ने गोकुल मिशन लाया, उसमें हमने सारे प्रावधानों को रखा, जैसे नस्लों में सुधार, उनके स्वास्थ्य, उनके संरक्षण और नई-नई टैक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश में संरक्षण कैसे करें।

आज एक बड़ी समस्या है कि जब हमारे यहां मेल बछड़े पैदा हो जाते हैं, तो किसानों को समस्या होती है। अब हम सेक्स्ड सीमन की भी व्यवस्था कर रह हैं, जो किसानों को उपलब्ध होगा और केवल बछिया ही पैदा होगी। महोदय, केवल यही नहीं, हम ईटी - एम्ब्रेयो ट्रांसप्लांट की भी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हमने 30 स्थान चिह्नित किए हैं। इस तरह से हम आईवीएफ टैक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। प्रथम कैबिनेट में पहले प्रधान मंत्री होंगे, जिन्होंने 13,500

करोड़ रुपये केवल पशुधन के रोगों से मुक्त कराने के लिए दिए हैं। इसलिए, मैं माननीय महोदय को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि गायों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाएगी।

(1145/SPS/SNB)

श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, गौ हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा अटल जी कहा था। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गौशालाओं को गौ अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? मेरे प्रश्न का संदर्भ इस बात से है कि हमारे देश में आजकल बाहर की गौ प्रजातियों को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है और स्वदेशी प्रजातियां उपेक्षित हो रही हैं। स्वदेशी प्रजातियां हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हैं। अगर उन्हें प्रोत्साहित न किया जाए तो उनके जेनेटिक पूल नकारात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि इन्हें गौ अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। क्या सरकार की ऐसी योजना है? जैसे आवारा गौवंश को संरक्षित करने के लिए भी सरकार, क्या न्याय पंचायतवार गौ रक्षण केन्द्र पर विचार कर रही है?

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): महोदय, पशुओं को मैं आवारा नहीं कह सकता हूं, बेसहारा कहता हूं। ये बेसहारा पशुओं के संरक्षण का काम राज्य सरकार के द्वारा होता है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसने चार हजार आश्रय केन्द्र खोले, क्योंकि यह राज्य का विषय होता है। उन्होंने लगभग 20,03,703 पशुओं को आश्रय देने का काम किया है। योगी जी की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत सरकार के अन्दर ऐनिमल वेलफेयर बोर्ड है। उसके तहत हम पशुओं को संरक्षित करते हैं, उसके लिए योजना भी है। जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के साथ उनको जोड़ने का काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा और यह पहले भी कहा था, हम कंजर्वेशन को महत्व दे रहे हैं। डे बाई डे जो विदेशी नस्ल के पशु हैं, उनका जर्म प्लाज्म धीरे-धीरे कम हो रहा है। देशी पशुओं को गोकुल मिशन के तहत पांच साल में जो संरक्षित करने का काम किया गया है, आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आने वाले पांच

साल में हमारी भी गायें उस लेवल में आ जायेंगी, जिस लेवल पर विदेशी और दूसरे नस्ल की गाय आती हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनोज तिवारी – उपस्थित नहीं।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker, Sir, thank you very much. The hon. Minister has stated that though cow protection is of course a State subject, yet the scheme of provision of shelter houses for looking after animals in distress is being implemented through the Animal Welfare Board of India. Now, what I wanted to point out is that, as you know, a lot of cow protection committees, *Gau Sangrakshak Samities,* have been unauthorizedly individually set up and mushroomed over the country, many of which have been indulging in wanton acts of violence of lynching, of attacking and goondaism.

I am wondering whether the hon. Minister, the hon. Home Minister is also present here, would consider using the same policy to ensure that only Committees authorised by the Animal Welfare Board of India and recognised by the Government of India are allowed to function. It is because these large numbers of informally constructed committees have proved a law and order menace in the country. Now, I recognise that law and order also is a State subject and belongs to another Minister, but the larger issue is you have the capacity to authorise and clarify who can qualify to be a *Gau Sangrakshak Samiti* and on that basis you can use a policy just as you have done with the provision of shelter houses and do the same to protect the ordinary individuals

by recognising only authorised committees so that in their name random acts of violence and goondaism cannot be perpetrated.

श्री गिरिराज सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है कि ऐनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जो चिह्नित या मान्यता प्राप्त जिन्हें आश्रय भवन कहें या आश्रय देने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके क्या मापदण्ड हैं, इसकी छानबीन की भी प्रक्रिया है। अगर कोई विशेष बात हो, जिस पर इनकी आपत्ति हो, वह उस मापदण्ड पर नहीं उतरता है तो माननीय थरूर साहब बता दें। यदि वह उस मापदण्ड पर नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

(इति)

(1150/KDS/RU)

(प्रश्न 47)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : ऑनरेबल स्पीकर सर, एक जमाना था, जब अरुणाचल, हिमालय स्टेट होने के कारण इस पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में हेड कैरिज का जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ हेड कैरिज इंट्रोड्यूज़ किया गया था, लेकिन एफ.सी.आई. और वहाँ के लोकल कॉंट्रैक्टर्स के करप्शन की वजह से अभी पी.डी.ए. सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट री-इंबर्समेंट नहीं दे रही है। मैं इसका समाधान ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर से चाहता हूँ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए अलग प्रश्न पूछना चाहिए था। उनका मूल प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा फिक्स एरिया चिह्नित है, जहाँ सरकार अनाज पहुँचाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1960 से जो पी.डी.एस. का कानून चल रहा था, जब 2013 में यह कानून बदला और फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं है, सभी राज्यों और संघशासित राज्यों में सरकार ने लोगों को अनाज का सभी तरह कानूनी हक दिया है, इसलिए ऐसा कोई एरिया चिह्नित नहीं है, लेकिन उनकी जो शिकायत है कि पी.डी.एस. के जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से बाकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शेष धनराशि का ऐसा कोई प्रस्ताव देती है, तो हम मुहैया कराएंगे।

श्री रामविलास पासवान: यह मामला पिछली सरकार के समय से लम्बित है और वहाँ के मुख्य मंत्री ने कई बार हमसे मुलाकात भी की थी। यह मामला थोड़ा जटिल है और हम लोगों ने नॉर्म बनाया था कि जो हिल एरियाज़ हैं, जहाँ ट्रक नहीं जा सकता है, बसें नहीं जा सकती हैं, खाना उठाकर ले जाते हैं और वहाँ सरकारें भी बदलती रहती हैं। यह सब सरकार की नॉलेज में है और हम लोग उनके साथ पत्राचार कर रहे हैं और मिलते भी रहते हैं। जो जेनुइन चीज़ होगी उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है और हम स्वयं इसे देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लीगली या फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, तो उसको जब तक डिपार्टमेंट क्लीयर नहीं करता है, तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं।

(इति)

(प्रश्न 48)

माननीय अध्यक्ष : श्रीरंग आप्पा बारणे जी।

श्री रंगअप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कई सारी योजनाओं की घोषणा होती हैं, लेकिन उन पर पूर्णरूप से अमल नहीं हो पाता है। इसके बारे में कई बार मीडिया में खबरें आती रहती हैं। वास्तव में निचले, गरीब लोगों तक यह योजना नहीं पहुँचती है। कई बार ऐसा पता चलता है कि सरकारी बाबू इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते हैं और इस योजना में गड़बड़ी होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार इस योजना को आखिरी गरीब आदमी तक पहुँचाने का क्या उपाय कर रही है? इस योजना में गड़बड़ी के बारे में सरकार के पास कितनी शिकायतें आई हैं और इन शिकायतों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न में यह पूछा गया था कि ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं, जिसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु माननीय सदस्य ने जो जानकारी माँगी है, उस संबंध में मैं बताता हूँ कि मेरे विभाग में 3 दर्जन से अधिक योजनाएँ चल रही है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण के लिए है। भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका हित संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। हम राज्यों के संपर्क में रहते हैं, राज्यों के साथ मीटिंग करते हैं और उन योजनाओं की जानकारी देकर जो योजना कार्यान्वित की जा रही है, उसकी समीक्षा राज्यों के अधिकारियों, एन.जी.ओ. से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से भी करते हैं। समय-समय प्रचार-प्रसार भी करते हैं।

(1155/SJN/NKL)

इन योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंच सकें और जिनके लिए ये बनी हैं, उनको इनका लाभ मिलता रहे। अभी तक हमारे पास इस विषय में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई

है। मुझे यह खुशी है कि हमने इन पांच वर्षों में इस विभाग को जीवंत बनाया है, सक्रिय बनाया है और मेरे विभाग को सात गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं?

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में समुचित रूप से जवाब दिया है। कई नई योजनाएं चालू की हैं। जो योजना चालू करते हैं, उसके बारे में मैंने मंत्री जी से पूछा है। इस योजना में गड़बड़ी जरूर होती है, क्योंकि गैर वित्तीय वर्ष में जितनी धनराशि आबंटित की थी, उससे कहीं ज्यादा मांग इस योजना में थी। आपने कई नई योजनाएं चालू की हैं। मेरा सीधा सवाल है कि आप इतनी योजनाओं को चालू कर देते हैं, लेकिन मंत्रालय से धनराशि की जितनी मांग होती है, उतनी धनराशि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इस बारे में मंत्रालय क्या जवाब देगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, विभाग को पर्याप्त बजट मिला है और जो बजट मिला है, हमने उसका 98 प्रतिशत से भी ज्यादा खर्च कर दिया है। जहां तक सवाल है कि राज्यों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है या खबर नहीं होती है, इसमें सत्यता नहीं है। मैंने पहले भी इस बात का उत्तर दिया है। वह कोई स्पेसिफिक योजना की बात पूछें। अगर इनके पास कोई शिकायत आई हो, तो उसे मेरे पास भेजें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से ब्यौरा रखा है। मेरा सवाल स्कॉलरशिप को लेकर है कि एससी जो स्कॉलरशिप है, वह 100 प्रतिशत है, ट्यूशन और डेवलेपमेंट फीस भी उसके साथ मिलती है। जबकि ओबीसी और एन.टी. को सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाती है और वह भी समय से नहीं पहुंच पा रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गवर्मेंट मेडिकल कालेज है, जिसमें 2016-17 और 2017-18 की जो ओबीसी की स्कॉलरशिप है, वह वर्ष 2018 के अंत में उनको इकट्ठा प्राप्त हुई थी। क्या भारत सरकार राज्य सरकार को कोई कड़े निर्देश देगी की उनकी जो ट्यूशन फीस है, उसको समय पर जमा किया जा सके? क्या इसमें हॉस्टल फीस को इन्क्लूड करने का कोई प्रावधान सरकार ने किया है?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में एक और सवाल पूछना चाहती हूं कि सवर्णों को जो 10 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र सरकार दे रही है, उससे लोगों को एडमिशन तो मिल जाएगा और नौकरियों में भी शायद आरक्षण मिल जाएगा। इनका जो शैक्षणिक शुल्क है, क्या उसका भार उठाने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमने शिक्षा के सशक्तीकरण के लिए छः प्रकार की छात्रवृत्तिमय योजना चालू की हुई हैं। उसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, विदेश जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग, फेलोशिप योजना आदि के माध्यम से हम उनका सशक्तिकरण करते हैं। मूल प्रश्न में जो बात है, वह इससे संबंधित है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का एरियर वर्ष 2013-14 से ही चला आ रहा था। हमें जब सरकार में आने का अवसर मिला तो, साढ़े छः हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा का एरियर था, जो बढ़कर साढ़े सात हजार करोड़ रुपयों का हो गया था। हमने इस साल तक संबंधित राज्यों को और संबंधित छात्रों को उस छात्रवृत्ति की राशि पहुंचाकर उसे पूरा करने का संकल्प लिया है। हम अगले माह तक पूरे एरियर की राशि संपूर्ण रूप से उनको दे देंगे। इसमें एक कठिनाई आ रही थी, जिसमें सुधार करने का प्रयास हमने राज्यों के साथ संपर्क करके किया है। अभी तक जो प्रतिबद्ध देयता थी, वह राज्य/संघ राज्यों की बनती थी। कुछ कमिटेड लाइबिलिटी के कारण बहुत सारे राज्यों को केन्द्र का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता था। अगर उस नियम के हिसाब से चलते, तो हमको राज्यों से लेना पड़ता, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई थी। अभी हम राज्यों के साथ संपर्क करके शेयर सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि राज्य उसमें सहमति देंगे। केन्द्र प्रायोजित योजना होने के बाद भी हम सोचते हैं कि शिक्षा राज्यों का विषय है, इसलिए उनकी भी कुछ हिस्सेदारी हो। हम 75:25 का शेयर राज्यों के साथ संपर्क करके उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जब हो जाएगा, तब जिन राज्यों को अभी पैसा नहीं मिलता है, उनको भी मिलने लगेगा। जहां तक 10 प्रतिशत आरक्षण का जो प्रावधान हमने किया है, वह ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें जो-जो समस्याएं सामने आएंगी, वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मेरे मंत्रालय के माध्यम से उसे हल करने का प्रयास हम करेंगे। (इति)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/GG/KSP)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इसके लिए सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे स्थगन प्रस्ताव को अन्य विषयों पर उठाया जा सकता है। मैं स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं प्रदान करता हूँ।

…(व्यवधान)

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, the Bihar issue is very important. Please allow him. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इसे कल रेज़ करना।

…(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे

श्री जी. किशन रेड्डी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, on behalf of Shri Amit Shah, I beg to lay on the Table a copy of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 199 (E) in Gazette of India dated 7th March, 2019 under Section 49 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे): अध्यक्ष महोदय, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1226 (अ), जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): Sir, on behalf of Shri Kailash Choudhary, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2018-2019.

ELECTION TO COMMITTEE
Rajghat Samadhi Committee

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rajghat Samadhi Committee for the term commencing from the date of notification by the Government, subject to the other provisions of the said Act."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> " कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के लिए अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, the Minister is leaving the House. He is disrespecting the House. This is not correct. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, please sit down.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Hon. Speaker, Sir, I was not leaving the House. I want to tell the hon. Members that an hon. Member had come to me just now. He wanted to discuss something with me. I just stepped aside to tell him and was coming back. I was not leaving the House. …(*Interruptions*)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

…(व्यवधान)

Re: Need to appoint DST INSPIRE faculty

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (DST) ने युवाओं के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग में रिसर्च जैसे विषय के साथ INSPIRE के माध्यम से एक बहुत ही नवीनता से परिपूर्ण योजना बनायी है, जिसके चलते इस माध्यम से एन.आई.टी., आई.आई.टी, IISEs, एन.आई.एस.ई.आर. के साथ युवा टैलेंट को जोड़कर नये साइंटिस्ट्स बनाने तथा ऐसी उच्च स्तरीय इंस्टीट्यूट में अध्यापन व आने वाले नये युवाओं को ट्रेनिंग हेतु यह योजना बनायी गयी है। DST में कुल जमा एप्लीकेशन में से करीब करीब 10 प्रतिशत युवा DST INSPIRE की फेलोशिप के लिए अब तक सेलेक्ट हुए हैं (जब तक का डाटा मिला है)। यह DST INSPIRE की फेलोशिप सेलेक्शन प्रोसेस तीन स्तरीय है, जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकादमी ने बनायी है। यह फेलोशिप के लिए उच्च शिक्षा एवं रिसर्च के लिए इंडिया से बाहर गये हुए बहुत से युवाओं ने अप्लाई किया, ये समझते हुए कि अभी अपने ही देश में इतनी अच्छी रिसर्च फैसिलिटी सरकार उपलब्ध करा रही है। इसलिए उन्होंने विदेशों में पंजीकरण के बावजूद DST INSPIRE के तहत अपना नाम दर्ज किया। अभी तक के उपलब्ध संख्या के अनुसार DST INSPIRE की फेलोशिप 1118 रिसर्च फैकल्टी अवार्ड प्राप्त किए हुए, जिसमें से अब तक केवल करीब 400 फैकल्टीज को स्थायी रूप से पोस्ट इन इंस्टीट्यूट्स में प्राप्त है और 60-70 प्रतिशत फैकल्टीज ऐसे हैं, जिनको स्थायी जॉब अभी तक नहीं मिली है। यू.जी.सी. के अंतर्गत कई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में खाली/ रिक्त हैं, लेकिन यू.जी.सी. इन DST INSPIRE फैकल्टी को असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्ग देने के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर DST INSPIRE फैकल्टी टैलेंट डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी राशि खर्च की है। बिना किसी उपयोग/जॉब के बैठे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन DST INSPIRE फैकल्टी का उपयोग आने वाली पीढ़ी की शिक्षा हेतु देश के प्रीमीयर इंस्टीट्यूट्स जैसे NITS, IITS, IISEs, NISER एवं UGC में इन DST INSPIRE फैकल्टी को पोस्टिंग दी जाये, जिससे यू.जी.सी. और

ऐसे इंस्टीट्यूट्स के रिक्त पोस्ट भी आई.आई.टी., आई.आई.एस.ई, एन.आई.एस.ई.आर. एवं यू.जी.सी. में इन DST INSPIRE फैकल्टी को पोस्टिंग दी जाए, जिससे यू.जी.सी. और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के रिक्त पोस्ट भी कुछ हद तक भरी जा सकती हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस टैलेंट का लाभ मिल सकता है। अगर सरकार इन DST INSPIRE फैकल्टी टैलेंट को 5 साल का नवीनीकरण नहीं कर सकती, तो उन्हें स्थायी रूप से जॉब मिलने तक अगले 5 साल "SERB-Assistant Professor" or "SERB Senior Faculty" जैसे पद निर्माण करके उनका रिसर्च क्षेत्र में योगदान ले और उन्हें राहत दे।

(इति)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Maharajganj district, Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): जनपद महराजगंज, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शर्तों के अनुसार महराजगंज में 6.5 एकड़ निःशुल्क भूमि, अस्थायी संचालन हेतु निःशुल्क जीजीआईसी के 15 कमरे, मार्ग का निर्माण, पृथक शौचालय, उक्त भूमि तक पहुंच मार्ग व विद्युतीकरण की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा करा दी गयी है। प्रस्तावित भमि पर 1.5 मीटर मिट्टी की पटाई का लिखित आश्वासन जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। जनपद महराजगंज भारत-नेपाल सीमा पर बसा है। यहां पर सुरक्षा हेतु सशस्त्र सीमा बल तथा अनेकों केन्द्रीय एजेन्सियां बड़ी संख्या में तैनात हैं। यहां एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः जनहित में जनपद महराजगंज, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना तथा अस्थायी संचालन हेतु जीजीआईसी भवन में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to fill up the vacant posts (Official Language) in Central Secretariat Official Language Service

श्री अजय कुमार (खीरी): केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में उप निदेशकों के 86 में से 82 पद वर्षों से रिक्त हैं और शेष 4 पद भी शीघ्र ही रिक्त होने वाले हैं। इस पद पर पदोन्नति के लिए कोई सहायक निदेशक पात्र नहीं है। कारण यह है कि उन्हें 10-11 वर्षों तक तदर्थ (एड-हॉक) रखने के बाद वर्ष 2015 में नियमित किया गया है। इससे उप निदेशक पद के लिए आवश्यक पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं हो रही है।

वर्तमान स्थिति से वर्ष 2008-09 में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक बना व्यक्ति वर्ष 2021 में उप निदेशक के लिए पात्र होगा। इससे अनुवाद कार्य, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और राजभाषा हिंदी के प्रयोग का प्रसार प्रभावित हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह भी होगा कि वर्ष 2019 से रिक्त होने वाले संयुक्त निदेशक के पद वर्ष 2027 में भरे जा सकेंगे तथा नीचे वरिष्ठ अनुवादक भी आगे सहायक निदेशक पद पर पदोन्नत नहीं हो पायेंगे।

वर्तमान सरकार में हिंदी में कार्य की मात्रा काफी बढ़ी है और हिंदी को देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करने का है।

अतः आपसे निवेदन है कि भर्ती नियमों में सहायक निदेशक से उप निदेशक पद पर पदोन्नति के लिये सहायक निदेशक के पद पर 05 वर्ष की आवश्यक नियमित सेवा के स्थान पर वरिष्ठ अनुवादक पद पर 05 वर्ष व सहायक निदेशक पद पर 03 वर्ष तथा दोनों पदों पर 08 वर्ष की कुल नियमित सेवा को आधार बनाकर उप निदेशक, राजभाषा के रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति करने का कष्ट करें, जिससे राजभाषा संबंधी कार्य का प्रसार सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार किया जा सके।

(इति)

Re: Regarding water shortage in Aurangabad and Gaya districts of Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिला में पीने का पानी का भीषण संकट है। भू-जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण 90 प्रतिशत चापाकल, कुआँ और पानी के स्रोत सूख गए हैं। आदमी-जानवर को पीने का पानी काफी कठिनाई से मिल रहा है। नदियाँ सूख गयी हैं। इस क्षेत्र की जनता को पीने के पानी के लिए करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है। क्षेत्र के नदियों में अवैध ढंग से बालू निकासी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जल संकट की समस्या उत्पन्न हुई है। ।

नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया के तहत गंगा को सोन नदी से जोड़ने और बटाने, अदरी, टिकारी, मदार, केसहर और मोरहर आदि नदी को जोड़ने से जल संकट का समाधान हो सकता है।

आग्रह होगा कि सरकार द्वारा जल संकट के समाधान के लिए तत्कालीन और दीर्घकालीन व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और इस क्षेत्र में चापाकल और कुआँ अधिष्ठापित कराने और वृक्षारोपण कराने की तत्काल व्यवस्था की जाए।

(इति)

Re: Need to accord approval to Eastern Rajasthan Canal Project submitted by Government of Rajasthan

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपूर): अध्यक्ष महोदय,मैं आपका ध्यान राजस्थान की अति महत्वपूर्ण एवं जीवनदायनी पेयजल एवं सिंचाई योजना की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उक्त प्रोजेक्ट नदियों से नदियाँ एवं बांधों को आपस में जोड़कर मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल का प्रावधान किया गया है। यह 38 हजार करोड़ की डीआरआर राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा 2017 -18 में केन्द्र में भेजी जा चुकी है।

अतः मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से समन्वय कर शीघ्र इस योजना को मंजूरी दिलाकर आवश्यक बजट का प्रावधान सुनिश्चित कर कार्य शुरू किया जाए।

(इति)

Re: Need to provide drinking water in Latur parliamentary constituency, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र विगत एक दशक से सूखे की मार झेल रहा है। इस क्षेत्र में पड़ने वाले लातूर शहर तथा उसके 21 सीमावर्ती गांवों में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। लातूर शहर में 10 दिन में एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेंकरों से पेयजल की सप्लाई का प्रयास कर रही है, परन्तु फिर भी वह जनता की पेयजल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल न जाकर पूरे दिन दूर-दराज के क्षेत्रों से घर की जरूरत के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं। प्राइवेट टेंकर से पानी मांगना बहुत ही महंगा होता है जो आम आदमी और गरीबों की पहुंच के बाहर है।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्रों में उज्जनी बांध से पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु एक योजना शीघ्रातिशीघ्र बनाकर कार्यान्वित करें ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके।

(इति)

Re: Need to provide adequate medical facilities to tackle Japanese Encephalitis disease in Muzaffarpur district and its adjoining areas in Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर शहर एवं आसपास के इलाकों में चमकी बुखार यानि जापानी बुखार से पिछले मई महीने से अब तक लगभग सैंकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके में भय एवं आतंक का माहौल है। सरकार इसके रोकथाम की समुचित व्यवस्था कर रही है। इसके बावजूद भी हर रोज बच्चों की मृत्यु इस रोग से हो रही है। अस्पतालों में समुचित बेड एवं चिकित्सा व्यवस्था की कमी पूर्ण उपचार में आड़े आ रही है। यह बीमारी पिछले 10-15 सालों से है और प्रतिवर्ष अप्रैल से जून के महीने में यह भयंकर रूपधारण कर लेती है, जिससे सैंकड़ों मासूमों की जान जा चुकी है लेकिन अभी तक इस रोग का कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। साथ ही सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस रोग के रोकथाम के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की टीम बनाकर इसका अनुसंधान किया जाये और मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में स्थायी तौर पर अलग से वार्ड एवं बेड की व्यवस्था की जाये। साथ ही मुजफ्फरपुर शहर के आसपास के इलाकों में स्थापित प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्रों में हर वर्ष अप्रैल से जून तक समुचित एवं शीघ्र इलाज के मद्देनजर विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये ताकि इस बीमारी का शीघ्र समुचित उपचार हो सके और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाये ताकि लोगों को इस रोग से स्थायी तौर पर निजात मिल सके।

(इति)

Re: Air pollution in Delhi

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): A recent report by India-state level Disease Bureau Initiative highlighted that around 12 lakh deaths in India can be directly attributed to air pollution. Around 76.8 % of India's population is exposed to deadly air pollutant PM 2.5 level which is four times higher than standards prescribed by the World Health Organization. Amongst all, Delhi faces the highest level of air pollution not only in India but in the world. Air pollution is severely damaging the health of people living in Delhi not only by causing lung diseases and cancer but also by damaging blood vessels and therefore leading to strokes and heart-attacks. Given the sensitivity and urgency of the matter, I urge both the Central and state government of Delhi to take up this issue on an urgent basis and take strict measures to save the people of Delhi from deadly air pollution.

(ends)

Re: Need to take necessary measures to deal with water scarcity in Pataliputra parliamentary constituency, Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार के अन्य जिलों के साथ-साथ अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पाटलीपुत्र की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि बारिश समय पर नहीं होने के कारण भयंकर सूखे की स्थिति हो गई है। पानी का जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण सभी हेण्डपम्प बेकार हो गए हैं। कुएं एवं तालाब सूख गये हैं, जिसके कारण पेयजल का घोर अभाव है। सिंचाई नहीं होने से कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से कार्यवाही की जा रही है परन्तु विषम स्थिति को आपदा मानते हुए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अतः सदन के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि तत्काल अपने स्तर से हस्तक्षेप कर अविलम्ब वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Regarding providing better railway services in Misrikh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संडीला-कछोना नगरपालिका/नगर पंचायतें हैं। इन क्षेत्रों से निकलने वाली रेलवे लाईन क्रॉसिंग पर भारी यातायात होने के कारण कई-कई घंटों तक ट्रैफिक अवरुद्ध रहता है, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों की पिछले काफी समय से रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की माँग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी माँग को स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण उनमें भारी रोष व्याप्त है।

मेरा अनुरोध है कि सण्डीला-कछोना नगर पालिका/नगर पंचायत के अंतर्गत रेलवे लाईन क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जाए और यदि ऐसा संभव नहीं है, तो फिर छोटे एवं मध्यम वाहनों के लिए वहाँ पर अंडर पास बनाये जाएं, ताकि ट्रैफिक अवरुद्ध की समस्या से निजात मिल सके।

मेरा यह भी अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सण्डीला रेलवे स्टेशन पर पद्मावत एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस, सहारनपुर एक्सप्रेस तथा बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर टाटा-छपरा एक्सप्रेस, मथुरा-छपरा एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस सहित सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों एवं अरवल मकनपुर स्टेशन पर कानपुर-कासगंज एक्सप्रेस और कालिन्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव भी प्रदान किए जाएं।

(इति)

Re: Need to set up a Bench of Odisha High Court at Sambalpur

SHRI NITESH GANGA DEB (Sambalpur): My parliamentary constituency Sambalpur is located in the Western region of Odisha. It is the educational, cultural, commercial and the industrial hub of the entire Western Odisha region. People of my constituency as well as the Bar Association of Sambalpur have been consistently demanding to set up a Bench of Odisha High Court at Sambalpur as they are facing lots of difficulties to go to Cuttack for their court cases. So I urge the Government to take urgent steps to set up a Bench of Odisha High Court at Sambalpur during current year.

(ends)

Re: Need to amend Press Council Act, 1978

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): भारतीय व्यवस्था का एक अंग प्रेस व्यवस्था भी है और इसीलिए पत्रकारिता लोकतंत्र का न केवल चौथा स्तम्भ है, बल्कि भारतीय संविधान में भी इसको चौथे स्तम्भ के रूप में माना जाता है, जिसे बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। एक प्रकार से पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति माना जाता है। और इसीलिए इस व्यवसाय को चौथे स्तम्भ के रूप में दर्जा प्राप्त है, जो सच्चाई को सामने लाने का कार्य करता है।

इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि प्रेस व्यवस्था जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है और यही कारण है कि प्रेस व्यवस्था को मीडिया कहा जाता है, जो सरकार के क्रियाकलापों को जनता व सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे किसी भी घटना की वास्तविकता का पता चलता है।

पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप ही हासिल नहीं किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है, जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे और सही तथ्य/सामाचार समाज के समक्ष रखे।

लेकिन, प्रायः ये देखने में आया है कि इन कार्यों को करने में भारतीय प्रेस वयवस्था में कई कमियां भी नजर आती हैं तथा कुछेक पत्रकारों का वास्तविक पत्रकारियता से कोई लेना-देना नहीं होता है। जबकि सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाये तथा गलत पत्रकारिता अर्थात् तत्यों को तोड़-मरोड़कर या मिथ्या सामाचार प्रकाशित करके देश की जनता को भ्रमित न किया जाए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में और संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं, ताकि पत्रकार कोई भी समाचार समाज के समक्ष ले जाने से पूर्व अपने प्रति पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लें कि वह समाचार सही है या नहीं।

(इति)

Re: Regarding construction of a dam in Bankura parliamentary constituency, West Bengal

डॉ. सुभाष सरकार (बंकुरा): महोदय, मेरा क्षेत्र बांकुड़ा, जो पश्चिम बंगाल के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा एक जंगल का इलाका भी है। इसमें दो विधान सभा अनुसूचित जनजाति और दो विधान सभा अनुसूचित जाति की हैं। यहां पीने का पानी और सिंचाई के जल का बड़ा अभाव है। क्षेत्र में चार नदी हैं। इसमें दो नदियों के संगम स्थल में एक बांध निर्माण की मांग पिछले 12 वर्षों से चली आ रही है। अनेकों बार इस मांग को संबंधित कार्यालयों तक पहुंचाया गया। इस बजट में इसका निष्पादन के साथ घोषणा हो जाये तो सारे क्षेत्र के लोगों के साथ मैं भी आभारी रहूंगा।

इस क्षेत्र में सात विधान सभाओं के अंतर्गत चार विधान सभाओं में कोई रेल पथ नहीं है। इसके लिए 12 साल पहले शुरू हुई परियोजना छातना से मुकुटमनिपुर रेल पथ का काम फिर से शुरू करवाने का निवेदन करता हूं।

(इति)

Re: Need to establish a Government Girls' College in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है जिस पर आसपास के 15 जिले अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर है जिसमें शिक्षा और विशेषकर स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में एक भी सरकारी महिला महाविद्यालय नहीं है। इससे यहां की छात्राओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में देश की सत्ता संभालते ही बालिकाओं में संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा उनके आगे बढ़ने के महत्व को समझते हुए 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया था। उनकी प्रगति के लिए अनेक योजनाएँ आरंभ की थी। गोरखपुर में महिला महाविद्यालय की स्थापना श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के इस महालक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि गोरखपुर से केन्द्रीय सहायता से एक महिला महाविद्यालय की स्थापना अविलम्ब दी जाय।

(इति)

Re: Need to take flood control measures in Barabanki parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री उपेन्द्र सिंह रावत (बाराबंकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में घाघरा नदी के दोनों ओर तटवर्ती तहसील रामनगर और तहसील सिरौली गौसपुर के तटवर्ती गाँव हेतमापुर, पाण्डेपुरवा, चौधरी पुरवा, पर्वतपुर, अकौना, बल्लौर, अलीनगर, खौना, किन्तुर, कोठी डीहा, बबुरी सहित लगभग 50 गाँव हेमापुर से करौनी तक दोनों तरफ तटबंध की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। तटबंध कमजोर होने के कारण प्रतिवर्ष बरसात में बाढ़ से किसानों के जान-माल, खेत-खलिहान, सड़कें इत्यादि को अत्यधिक नुकसान होता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि घाघरा नदी के तटवर्ती गाँव को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थरों और तार की सोलिंग लगाकर मजबूत तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही केन्द्र सरकार तटबंधों को मजबूत और ऊँचा बनाने के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाये जिससे नदी के किनारे बसे गाँवों को बचाया जा सके।

(इति)

Re: Need to appoint Ayush doctors under Ayushman Bharat Yojana

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा शोध प्रयोगशालाओं में कई नई दवाइयां विकसित की गयी हैं और देशी दवाओं के आधुनिक चिकित्सा मानकों पर परखे जाने और उसमें सफल होने की बावजूद देश में जमीनी स्तर पर उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहाहै।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से आयुर्वेद और जड़ी-बूटियों पर आधारित दवाओं के गहन परीक्षण और मानकीकरण को लेकर करार भी किया है। सी.एस. आई.आर. कई सफल आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाएं बाजार में ला चुका है, परंतु फिर भी ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधायें अपर्याप्त हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि आयुष डॉक्टर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जाये, ताकि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

(इति)

Re: Need to widen Joriya-Pulanwa road in Jammu & Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू की ओर दिलाना चाहता हूं कि जोड़िया से पुलांवा का बार्डर रोड जो कि भारत पाक सीमा पर है और यह रोड बीआरओ के अधीन आता है, पर इस रोड की हालत बहुत ही खस्ता है, जगह-जगह गड्डे हैं, जिसके कारण रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं।

अतः आपके माध्यम से इनसे संबंधित मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि इस रोड को चौड़ीकरण करने के लिए धनराशि आवंटित करें।

(इति)

Re: Modernisation of Trichy International Airport in Tamil Nadu

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALI): Trichy International Airport is the third-largest airport in Tamil Nadu in terms of total passenger traffic next to Chennai and Coimbatore. The airport is served by two Indian and four foreign carriers providing direct connectivity to 3 domestic and S international destinations. This airport is Iso 9001:2008 quality certified and was declared an international airport on 4 October 2012.

At present, Trichy international Airport is connected with just 05 international cities i.e. Kuala Lumpur, Singapore, Dubai, Sharjah, Colombo and 03 domestic cities i.e. Chennai, Bengaluru and Kochi. Only 07 airlines are operating flight services from Trichy International Airport namely Air Asia, Air India Express, Alliance Air, IndiGo Malind6 Air and Sri Lankan Airlines. It is pertinent to mention here that there is no Air India domestic flight service to any domestic destinations in the country. So an Air India domestic flight be operated from Trichy to Delhi via Chennai or via Hyderabad or via Bengaluru.

Trichy has high catchment of passengers for Singapore Malaysia and various Gulf countries. Around 8 lakh people are working in Singapore and Malaysia. More than 10 lakh people from Tamil Nadu are working in Gulf countries. Trichy Pillaiyar Kovil (Vinayaka Temple) built on top of the hill in Trichy is the world famous temple and lots of people from various countries visit this temple every day particularly during the festival season. Further, holy cities of Vailankanni and Nagoor can be reached in just 2 to 3 hours from Trichy by road.

Further, Trichy is situated in the centre of Tamil Nadu and also called educational hub of Tamil Nadu. Further all the Central & State government departments/offices and many public sector undertakings/industries like BHEL, BEL, Railway Coach Factory, Ordinance Factory and lot of small scale industries are there in which thousands of employees are working in Trichy area. So this airport can be connected with more international cities and domestic cities for the convenience of pilgrims, tourists and govt officials. Due to increase in air traffic, Trichy International Airport needs to expand both its flight operations to more foreign destinations as well as expand its present runway to facilitate landing and take off of jumbo jets/flights and also needs to construct a modern Air Traffic Control (ATC) tower in the airport. Hence, I urge upon the Union Govt through this august House to take immediate steps to expand the Trichy International Airport as well as to expand the present runway to facilitate operation of more flights to more foreign destinations and domestic cities.

(ends)

Re : Implementation of river Pampa Protection Plan in Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA)**:** Pampa river is an important part of the cultural and societal heritage of Kerala and specifically central Travancore region, is facing an existential threat due to pollution, erosion of banks and decreased water holding capacity. By viewing the enormity of the situation, I would urge upon the government to implement a Pampa Protection Plan to protect and preserve the river on the lines of Namami Gange model at the earliest in order to develop a holistic model of development of antipollution measures, erosion prevention methods and modern flood control mechanisms. I would also urge the government to seek international technical collaboration for the programme with a view to gain advanced insights for remedial measures to be undertaken though the plan.

(ends)

Re: Need to accord International Airport status to Madurai Airport in Tamil Nadu

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Madurai Airport was inaugurated in 2012, and it is connected to just 03 international cities namely Colombo, Dubai and Singapore. Madurai is a temple city which is surrounded by few hundred temples i.e Rameshhwaram Temple, Srivilliputhur Andal Temple, Palani Murugan temple etc and lakhs of Hindu pilgrims visit Madurai every year. Madural region has high catchment of passengers to Singapore, Malaysia and various Gulf countries. 8 lakh people in Singapore and Malaysia and more than 10 Lakh people in Gulf countries are working from Tamil Nactu alone. Madurai is not included in bilateral air services agreement (BASA) with any country except Sri Lanka. Many countries and many airlines have evinced interest to operate flight to Madurai, Air-Asia, Silk-Air, Tiger Airways, Air-Arabia, FlyDubai are awaiting MOCA nod to start flight services to Madurai for the last 9 years. Indigo airlines are presently operating international flight service from everywhere except from Madurai. For the development of southern Tamil Nadu the following action to be taken at the earliest: (i) Madurai airport be given international status and to operate 24X7 hours. (H) Madurai airport needs appointment of permanent plant quarantine and customs officers in international cargo section to support 24X7 hours loading and unloading of international cargo (Hi) an Air-India/Air India Express International flight from Madurai to Kuala Lumpur, Sharjah, Muscat, Dubai and Kuwait will benefit 3 million ethnic Indians of Tamil Nadu origin in Malaysia & Singapore and Gulf region, (iv) Include

Madurai in BASA with Singapore, Malaysia, Thailand Dubai, Muscat, Sharjah and Kuwait, (v) a new state of the art terminal building for Madurai to handle 5 million passengers per annum, and (vi) runway expansion from current 7500 FT to 10000 Ft.

In view of the above, I urge upon the Union govt. through this august House to take early action on the above mentioned demands which will boost the economic and industrial development of southern Tamil Nadu region besides helping millions of Indian workers and tourists visiting Madurai each year.

(ends)

Re: Need to sanction road-under-bridge/subway at Bauria Railway Station in West Bengal

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I would like to thank you Sir, for giving me this opportunity to talk about the problem faced by the people of my Constituency, Uluberia. I like to invite the attention of the Government to the difficulties being faced by the constituents of my Parliamentary Constituency near Bauria Railway Station, on Howrah --Kharagpur Line in South Eastern Railway due to level crossing on high traffic density stretch, daily nearly **20** thousand people are crossing the railway line for their daily necessities and the road at railway crossing is most of the times closed due to train movement at regular intervals. Sometime in urgency people are taking risks to cross the railway lines. Patients have to wait for long due to closure of the railway crossing gate. Besides, these crossings also lead to drop in speed of the trains.

During the last budget, Ministry of Railways committed to fulfill 'Mission Zero Accident' promise. I urge the Govt. to sanction a RUB or Subway at Bauria Station approach road to eliminate the difficulties being faced by general citizens and also to avoid accidents.

(ends)

Re: Construction of Bolondi Halt Railway Station in West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Bolondi under my constituency is SC/ST dominated area where girls are achieving excellence in education despite lack of rail stations which is causing hindrance to their higher aspirations. Bolondi comprises about 50 villages and 26 village panchayats. The common citizens are also facing problem. I urge the Government for an early survey regarding Bolondi Halt station which is already sanctioned.

(ends)

Re: Need to regularise the services of 133 contractual workers of the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTHWEST): The Central Institute of Fisheries Education, Andheri (West), Mumbai comes under my Parliamentary constituency of 27-Mumbai North West. Nearly 133 workers are serving in the Institute for the last 20 years on a contract basis. In the beginning of the New Year about 20 workers were relieved from their jobs. Then, I had paid a visit to the Institute on 12-1-2018 and discussed the matter with the Director and the Vice-Chancellor in my capacity as a local Member of Parliament. I came to know from them that the Institute was in need of 200 permanent workers as on date. For want of sufficient funds, the Institute is forced to hire workers on a contract basis. In fact, the contractor is gaining and hard, honest and sincere workers are losing. Presently 133 workers working in the Institute are local people and majority of them are from fishermen community only. The Institute has, therefore, requested for a financial assistance of Rs.2.50 crore for regularising these workers.

In view of this situation, I urge upon the Government of India to absorb all the 133 workers on a permanent basis by sanctioning the above amount on a compassionate ground.

(ends)

Re: Need to provide drinking water in Banka district, Bihar

श्री गिरिधारी यादव (बांका): सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांका जिले में मानसून की देरी से पेयजल एवं पानी की भीषण समस्या हो गयी है। बरसात समय पर न होने से भूमि का जलस्तर 30 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है जिसके कारण हैंडपंपों से पानी नहीं आ रहा है और तालाब सूख चुके हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में पेयजल की कुल मांग का केवल 7.6 प्रतिशत पेयजल मिल पा रहा है जो आज एक भीषण समस्या है। क्योंकि जल ही जीवन है। जल के अभाव में लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पिछले साल बिहार के 25 जिलों के 280 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र बांका भी शामिल था। जंगलों में पानी की कमी से जंगली जानवर पानी की खोज में गाँव के आसपास मंडरा रहे हैं जिससे गाँव के लोगों का जीवन खतरे में है और लोग रात में घरो से निकलने से डरते हैं। शुद्ध जल नहीं मिलने से लोग गंदे तालाब और नहरों के पानी को गाँव के लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं जिससे वे बीमार पड़ रहे हैं। आने वाले समय में किसानों को पानी की कमी से अपने खेतों को सींचने में काफी कठिनाई होने वाली है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के बांका जिले में सूखाग्रस्त होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका निदान शीघ्र किया जाये एवं लोगों की पेयजल की आवश्यकता के हिसाब से पेयजल का प्रबंध विभिन्न विकल्प माध्यमों से किया जाये साथ ही साथ अनुरोध है कि बांका जिले के सभी ब्लॉकों के सूखे तालाब को गहरा किया जाये जिससे आने वाले मानसून के पानी को संरक्षित किया जा सके और इस जिले के गिरते जलस्तर को रोका जा सके।

(इति)

Re: Development of tourism infrastructure in Rameswaram, Tamil Nadu

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Rameswaram is an important pilgrim destination of our country. Every year, crores of pilgrims visit Rameswaram from different parts of the country. They also visit Danushkodi, but the facilities are not upto the mark to accommodate the tourists. Enough accommodation is not available. Water facility is not available and transport facility is awful. For any pilgrim visiting Rameswaram he has to come to Madurai and take road. It takes four hours to reach Rameswaram. Considering the heavy tourist traffic, I request that an airstrip can be set up in Rameswaram. This will not only attract tourists, but also reduce the travel time. Rameswaram can be included under the UDAN Scheme and flights can be operated from Tuticorin & Madurai. The train facilities are inadequate and introduction of trains to major cities in different parts of the country is the need of the hour. Rameswaram station requires modernization and I request the government to modernize the same with a provision of Executive Lounge on the lines of Madurai station and escalators to help the passengers.

I request the government to allocate adequate funds for the development of infrastructure at Rameswaram and also set up an office of the Indian Tourism Development Corporation there to help the pilgrims and tourists.

(ends)

Re: Need to provide Scheduled Tribe status to certain communities of Assam

श्री नबा कुमार सरनीया (कोकराझार): मैं अपने राज्य और क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

असम के कोच राजबंगशी और आदिवासियों (मुंडा, ओरांव, गोंड, खड़िया, प्रझा, किसान इत्यादि) बहुत दिनों से जनजातिकरण को लेकर मांग करते आ रहे हैं। सोलहवीं लोकसभा के दौरान इन समृदाओं को साथ ही चार अन्य मोरान, मटक. ताई आहोम, चुटिया को भी जनजातिकरण के दर्जा देने के लिए यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। यह असम की अखण्डता और प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी हैं कि इन लोगों को जनजातिकरण का दर्जा दिया जाए।

मैं इस सदन में आपके जरिये अनुरोध के साथ मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस संदर्भ में इस सत्र के दौरान जल्द से जल्द इस बिल को पास करके इन समुदायों को जनजातिकरण का दर्जा दे। साथ ही कलिता नाथ योगी को भी जनजातिकरण दर्जा देने का जरूरी कदम उठाये।।

(इति)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

1204 बजे

माननीय अध्यक्ष: राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा।

श्री दयानिधि मारन जी।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in this debate on the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, at the outset, I would really like to congratulate the BJP for its tremendous victory.

(1205/KN/SRG)

It is a very good win. They have repeated their victory after 2014. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब अपनी-अपनी सीट पर बैठिए। प्लीज बैठिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House is not in order. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): In 2014, the BJP came to power. Unfortunately, in Tamil Nadu, the DMK was not able to win any seat. The ruling AIADMK won 37 seats. Sir, I just want to register this moment because the President gave importance to the people coming and voting. An atrocity took place in 2014. The Election Commission of Tamil Nadu imposed Section 144 – Unlawful Assembly. There was a corrupt practice in 2014 and

money was distributed to all the voters and that was the reason that DMK could not come to power and represent anyone in the Parliament in 2014.

Today, the people of Tamil Nadu have said no to money. They voted rightly under the able leadership of Shri M. K. Stalin, who formed a formidable alliance with a win of 38 out of 39 seats in Tamil Nadu and Puducherry. If only the rest of India had followed the footsteps of our leader Shri M.K. Stalin, things would have been different in this House. Anyway, our late leader Shri Annadurai always says people's decision is the God's decision and we respect it. To start my speech, I thought it would be best to quote my leader with a little pun when he started his speech as his maiden speech in the Rajya Sabha in 1962. At that time, the Congress had come to power for the third consecutive time with a majority and our leader Mr. Annadurai made a speech. He had said there was a lot of jubilation. I also find a lot of jubilation in the speeches of the Ruling Party after winning the general election in 2019. Any party has got the right to be jubilant. With your permission, I would like to point out to the ruling party that it is not very astounding for a party supported by money power, the Government agencies like the CBI and IT Department; and of course, the Election Commission was also supporting them.

The strength of the BJP does not lie in itself, but in the weakness of the opposition and that is what my leader said during 1962. When the oath taking ceremony was taking place, we have seen some of the Ruling Party Members shouting slogans in a jubilant mood. Sir, I want to again quote here our great leader, our Anna who in his maiden speech said : "Instead of being jubilant over

the victory, the Ruling Party should be humble, magnanimous, liberal and democratic." The reason I am saying this is that in the President's Address, the President did insist on water management and in fact, said in the para 19 and also in para 20 that Ministry of Jal Shakti has been formed. Sir, the President has addressed the water crisis which is looming large in India, especially in South India and Tamil Nadu. We are in utter water distress.

I am sure the Government is aware that the NITI Aayog report on water crisis had mentioned that 40 per cent of India's population will not have access to clean drinking water by 2013. This is not my report; this is NITI Aayog's report. I am just giving the highlights of the NITI Aayog report. The NITI Aayog report also says that India stands at 120th position out of 122 when it comes to water quality index. We are so bad. NITI Aayog also warns that 21 Indian cities including cities of Chennai, Bengaluru and Delhi will run out of groundwater by 2020.

(1210/KKD/CS)

Sir, 43.4 per cent of India is reeling under severe drought and early global warming system. The pre-monsoon rain is the lowest in the last 65 years. Four reservoirs supplying water to Chennai have dropped below one per cent and are literally zero. In fact, I would like to say that there is going to be a severe water crisis. A similar situation happened in 2004. At that time, my late leader, Dr. Kalaignar, while he was campaigning, saw the pitiful situation in Chennai. He had promised: "If given a chance, we will bring in a desalination plant." Sir, it happened. Whatever the DMK says, it will happen.

In 2004, when the DMK and the UPA came to power, for the first time in the history, the Central Government sanctioned Rs. 1,000 crore for a desalination plant to be implemented in Chennai. It was implemented. Later, another desalination plant was implemented.

Sir, now, the ally of the BJP, the ruling ally, the AIADMK is so complacent. They knew that there is no water; there is no rain for the last one year. But they did nothing. They are slaves. They only notice it; they do not want to be working for the people. In fact, in the last eight year, have the ruling AIADMK Government implanted the projects? Yesterday, my leader Shri M.K. Stalin, was on the roads holding pots and fighting for water for the people of Tamil Nadu.

Sir, on 16.04.2013, they were supposed to implement 115 million litres waters for Chennai at a cost of Rs. 1,370 crore. Again, they wanted to implemented in Perul a project worth Rs. 4,000 crore. They had also said that in the Ramanathapuram District, they would implement a 60 million litre water plant. They also said they would implement another plant near Chennai at a cost of Rs. 6,700 crore. But they did nothing. If only they had implemented them, Tamil Nadu would not be looking at this water shortage.

Sir, what to do? The Government's ally in Tamil Nadu is complacent. Now, they are not worried. While the President's Address speaks about anti-corruption, the most *… (Not recorded)* Government is functioning in Tamil Nadu. It is not worried to resolve the problems of people of Tamil Nadu. Instead, they are only interested in trying to make more money …(*Interruptions*)

Sir, today, we are talking about women's liberation. The President in his Address at para 36, had spoken that no girl child should be left out …(*Interruptions*) The girl children have committed suicide. All I ask is this. Why are you trying to discriminate the State Education System?

Sir, Mylswamy Annadurai who headed the Mangalyaan programme, studied in the State Board Tamil Medium school. He made India proud. Today, we have Mr. Sivan who also studied in the State Board Tamil Medium School. He is heading the ISRO and is making India proud …(*Interruptions*) Let me finish, Sir.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रूकिए। निशिकांत जी, आप रूल बताइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, रूल 352 (3)।…(व्यवधान)

Mr. Speaker Sir, it is rule 352(3), which says that 'a Member while speaking shall not use offensive expression about the conduct of proceedings of Parliament or any State Legislature.'

But here, the hon. Member is using offensive languages against the AIADMK Government in Tamil Nadu. He is using the word 'corrupt' against the AIADMK Government of Tamil Nadu, which is very offensive. This is Parliament.

महोदय, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी चीजों को एक्सपंज कर दिया जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विधान मंडल वाली चीज कार्यवाही से निकाल दें।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I was mentioning it because the President in his Address had spoken about corruption, to eradicate corruption.

I have every right to talk of it in this House. There are several cases filed against the sitting Ministers of the ruling AIADMK Government. The CBI conducted raid in the Secretariat of the Tamil Nadu Government. The Chief Secretary's room was raided …(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I am on a point of order …(*Interruptions*)

(1215/RP/RV)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रूडी जी, प्लीज़, रूल बताइए, किस नियम के तहत है?

…(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, my point of order is with reference to Chapter-V, page 9 – President's Address and Message to the House. …(*Interruptions*) Sir, please read paragraph 17.…(*Interruptions*) I would just read out the paragraph 17. …(*Interruptions*) Sir, paragraph 17 says:

> "On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member."

Sir, where does the Tamil Nadu figure in the Speech of the President? …(*Interruptions*)He is talking about the State. He is talking about the nation's

progress. Why are you severing one particular State and allowing a Member to talk against one political party? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा विषय, जो नियम के तहत नहीं होगा, वह निकाल दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, Rules are very clear about it. …(*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I have only requested the House…….(*Interruptions*) Sir, I understand their loyalty. They are in alliance.…(*Interruptions*) They are the forced allies.…(*Interruptions*) It is the duty of the master to take care of their slaves and they are doing exactly that..…(*Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : केवल दयानिधि मारन जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी। बाकी किसी सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अर्जुन राम मेघवाल जी।

…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, the water crisis is so severe.…(*Interruptions*) I think, we all will be very happy if whatever the President said in his Speech or whatever he spoke is implemented. …(*Interruptions*) Today, we have another grave issue staring at our face. …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Dayanidhi *ji,* you cannot say that it is the duty of the master to save his slave. …(*Interruptions*) हम दास नहीं हैं। न ये दास हैं, न वे दास हैं। ये ऐसे शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं? यह पार्लियामेंट है। क्या हम दास हैं या ये ए.आई.ए.डी.एम.के. वाले दास हैं?…(व्यवधान) He cannot use such type of words in the Parliament.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई भी शब्द, जो संसदीय नहीं हैं, वे निकाल दिए जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय दयानिधि मारन जी।

…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, it is not unparliamentary. …(*Interruptions*) It is not at all unparliamentary. …(*Interruptions*) We are talking about a serious issue. Today, India is reeling under severe drought. …(*Interruptions*) I am not only talking about myself but I am also talking about every State in our country.…(*Interruptions*) Today, they have come in power with a huge majority. The Prime Minister is not only for those who have voted for him but he is also the Prime Minister of those who have not voted for you. …(*Interruptions*) If Tamil Nadu has not voted for you, please introspect yourself and understand why the people of Tamil Nadu have not voted for you. …(*Interruptions*) The reason is very simple and that is the water crisis. It is very important. …(*Interruptions*) Rudy ji, allow me to speak. This is not fair.

…(*Interruptions*) I am making my first speech of this Session. You cannot do like this. …(*Interruptions*) What is this? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में बात न करें।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, today, we have a serious water crisis. I want the Government to look at Tamil Nadu. …(*Interruptions*) Why are the people of Tami Nadu upset? It is because you are imposing everything on us. The Cauvery Tribunal and the Supreme Court ordered clearly that whatever water allocated to Tamil Nadu should be released.…(*Interruptions*) Today, Karnataka is trying to build a project at Mekedatu.…(*Interruptions*) Sir, in this House the former Water Resources Minister, Mr. Nitin Gadkari has assured that the Government will never allow any dam to be built to stop water flowing to Tamil Nadu. …(*Interruptions*) Under what authority, Sadananda Gowda, Sir – a Minister of this Government – has assured in the Press that he will give permission. This is the irony.

(1220/RCP/MY)

Sir, what is this? …(*Interruptions*) Is this democracy? Is this why the people of India voted for you? …(*Interruptions*) They are imposing …(*Interruptions*) This is illegal. This goes against the orders of the Cauvery Water Disputes Tribunal. …(*Interruptions*) This goes against the order of the Supreme Court. …(*Interruptions*) This is the reason. The people of Tamil Nadu are upset with you because you normally impose, you impose Hindi on us; you impose everything; you impose NEET…(*Interruptions*)

Please take the spirit of the President's Address seriously. …(*Interruptions*) You want to be the leader of entire India. We are a part of India and we have every right. Do not impose any Mekedatu Dam on us. This is illegal, Sir. …(*Interruptions*)

(ends)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे रख सके हैं।

श्रीमती हेमामालिनी जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। असंसदीय शब्द निकाल दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

1222 बजे

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आप कल तक हमारे बीच में बैठे थे और आज आप लोक सभा के अध्यक्ष सीट पर आसन हुए हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सभी के साथ जरूर न्याय करेंगे।

इस वक्त मैं अपनी पूर्व स्पीकर महोदया सुमित्रा महाजन जी को बहुत याद कर रही हूं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर हम सब को कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं अपनी पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने आज मुझे बोलने के लिए समय दिया है।

I must say, we the Members of this august House are really lucky to be a part of this great transition taking place in our country: a transformation of a New India under the leadership of our dear Prime Minister, Narendra Modi *ji*. It was his vision and dream to make our country and bring it to a new level, for which, I think, the work has already started in the last five years from 2014 to 2019. That is the reason, we won with a huge margin in the last election. I thank the entire country, the people of this country who voted for us. I thank them. Beyond caste and creed, they voted. That shows how much faith they have in us. I also thank all the women voters who came fearlessly forward and voted for us.

Hon. President of India mentioned in his speech that it is a matter of pride for every Indian that when our country completes 75 years of Independence in 2022, we would have achieved many national goals for building a New India. To pave the way for the golden future of New India, my Government has resolved to work on an action plan.

मैं यह कहना चाहती हूं कि हर सच्चा भारतीय अपने देश को फलते-फूलते, आगे बढ़ते और विकसित होते देखना चाहता है। ठीक उसी तरह मेरा भी एक सपना था कि हमारा देश कैसा हो। जब भी मैं विदेश जाती थी तो मुझे लगता था कि यहां कितना अच्छा है, सब कुछ साथ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डिसप्लिन्ड, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है।?

(1225/SMN/CP)

जब भी मैं अपने देश में वापस आती थी, तो मुझे बहुत दुःख होता था कि ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे देश में ऐसा होना चाहिए। कहते हैं कि भले ही देर से हो, लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि अपने जीवनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है। मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूं, एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूं, न्यू इंडिया बनते देख रही हूं।

मोदी सरकार की वैसे तो अनगिनत उपलब्धियां हैं, जैसे किसानों के हित के लिए, जवानों के वेलफेयर के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत वूमैन इंपॉवरमेंट है। आज मैं कहूंगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं हैं, especially the younger ones are really doing very well. वे कंधे से कंधा मिला कर बहुत कुछ काम कर रही हैं। आप देख लीजिए, बैंक चेयरमैन की पदवी के साथ-साथ, हर सर्विस सेंटर में महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि वे मेट्रो भी चलाती हैं, उबेर भी चलाती हैं और यहां तक कि हम जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं, बहुत सारी young pilots are there. Young girls are flying the aeroplanes. इतना ही नहीं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी महिलाएं हैं। यह भी सुना है कि एयरफोर्स में फाइटर प्लेन भी लड़कियां चलाती हैं। Hats off to those young girls. इतना ही नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे डॉयरेक्शन, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग या बिहाइंड दि कैमरा हो, they are able to do all kind of things which is really very remarkable and we really feel very proud to see them. Apart from that, we have so many women doctors, engineers, scientists and

astronomers. ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमारी महिलाएं बहुत सारे काम करती आई हैं। महिला चाहे गांव की हो या शहर की, चाहे जिस जाति या धर्म की हो, मोदी सरकार ने उनको उनका हक दिलाया है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। खास तौर पर गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है। इस योजना के बारे में मैं कहना चाहती हूं –

कब तक आँखों में रहेंगे आँसू और फेफड़ों में चूल्हे का धुआँ,
कुछ ऐसा ही था गाँव की महिलाओं का सोचना।
लेकिन उन्हीं महिलाओं की आँखों से आँसू पोंछकर
धुएं का रुख जिसने मोड़ दिया, ऐसी बनी उज्ज्वला योजना।

महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा को बचाने के लिए गांव-गांव के घर-घर में शौचालय का निर्माण करना, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ में बहुत सारी जो भ्रूण हत्याएं होती थीं, इसकी वजह से उनकी संख्या बहुत कमी हुई है। प्रधान मंत्री आवास योजना में महिलाओं को रजिस्ट्री में प्राथमिकता मिलना, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक बहनों के हक को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना, यह साबित करता है कि हमारे देश के गांव की महिलाओं से लेकर शहर की महिला तक, सबके विकास के लिए कितना काम हुआ है, यही तो है न्यू इंडिया।

महोदय, जहां वर्ष 2009 के लोक सभा इलेक्शन में महिलाओं का वोट पर्सेंटेज सिर्फ 55.82 पर्सेंट था, वहीं वह वोट पर्सेंट वर्ष 2014 के इलेक्शन में 65.3 पर्सेंट हो जाना और आश्चर्यजनक रूप से वर्ष 2019 में जम्प होकर 69 पर्सेंट महिलाओं का वोट देना बहुत बड़ी उपलब्धि है न सिर्फ सरकार की, बल्कि देश की हर महिला की। संसद के इतिहास में 30 नहीं, 40 नहीं, 50 या 60 नहीं, बल्कि 78 महिला सांसदों द्वारा इस सदन की गरिमा बढ़ाना, देश की हर महिला के लिए सम्मान की बात है, अभिमान की बात है। इसका श्रेय हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी को मैं देना चाहती हूं।

(1230/SK/MMN)

मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदियां कभी अपना पानी नहीं पीतीं, बादल पानी बनकर खेतों में बरसता जरूर है, लेकिन खुद कभी उस खेत का अनाज नहीं

खाता, उसी तरह हम सबका जन्म भी परोपकार के लिए हुआ है। हमें मोदी जी से इन्सपायर होकर अपना जीवन लोगों के परोपकार और देश के उद्धार में लगाना है।

मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि पानी की हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। यहां अभी जिक्र हो रहा था कि तमिलनाडु में पानी नहीं है, पूरे देश में यही समस्या है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में जाती हूं, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है, यहां पानी के लिए बहुत सी महिलाएं तड़प रही हैं। मुझे खुशी है कि इस पर हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। जब मैं वहां जाती हूं तो यहां खासकरके यमुना के शुद्धिकरण की बात होती है। वहां साधु-संत जो इस पुण्य नदी के पानी से आच्छमन करना चाहते हैं, वे नहीं कर पाते हैं। वे हमेशा मुझ से कहते हैं कि आप सांसद तो बन गई हैं, लेकिन यमुना का शुद्धिकरण करना भी आपका ही कर्तव्य है। मैंने हमेशा माननीय मोदी जी से कहा है और मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारी सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। मथुरा क्षेत्र में यमुना नदी पर बहुत से प्लांट भी लग गए हैं। यहां काम शुरु हो गया है। मैं मथुरा वासियों को आश्वासन देना चाहती हूं कि बहुत जल्द यमुना शुद्ध हो जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से और जल्दी काम कर रही है। वहां के लोगों के लिए राधे-राधे।

महोदय, वैसे तो सपने दो आंखों से देखे जाते हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहती हूं, न्यू इंडिया का सपना दो आंखों से नहीं, बल्कि सवा सौ करोड़ भारतीयों की आंखों से देखा जा रहा है। हम सबको मिलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करके दिखाना है और सारी दुनिया को बता देना है –

भारत किसी से पीछे नहीं, भारत किसी से कम नहीं
भारत को आंख दिखाए, अब किसी में दम नहीं।

(इति)

***श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई):**

----

* Laid on the Table

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):

*Laid on the Table.

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):

---

*Laid on the Table

***श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज):**

---

* Laid on the Table

***श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):**

---

* Laid on the Table

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):**

---

* Laid on the Table

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):

*Laid on the Table

*SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT):

*Laid on the Table

***श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा):**

---

* Laid on the Table

*DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA):

---

*Laid on the Table.

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):

---

*Laid on the Table

***श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई) (आनंद):**

---

* Laid on the Table

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):**

----

* Laid on the Table

***श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर):**

----

* Laid on the Table

***श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद):**

---

* Laid on the Table

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):**

----

* Laid on the Table

1232 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to thank the hon. President for his Address.

Sir, at the outset, I would like to congratulate, Shri Narendra Modi Ji, the BJP and the NDA for their victory in the recently concluded Lok Sabha elections.

The TDP had been a partner in NDA-1, with Shri Atal Bihari Vajpayee Ji, and in NDA-2 with Shri Narendra Modi Ji, who promised us that post the unscientific and unfair bifurcation of Andhra Pradesh, he would ensure all provisions of the AP Re-organisation Act and the assurances given by the then Prime Minister, Shri Manmohan Singh, especially the granting of Special Category Status (SCS), would be fulfilled. Indeed, we had to walk out of the NDA due to the fact that the SCS was being denied to us, and the implementation/ execution of the AP Re-organisation Act was being delayed beyond a reasonable time limit. The TDP left the NDA after a long escalation process, in which we gave the Central Government every opportunity to deliver our rights. We fought hard to get our rights.

The people of India have given a massive mandate to the BJP and NDA but in Andhra Pradesh, both the BJP and the TDP have suffered heavy losses. The BJP went down to less than one per cent vote share and did not even win a single MLA or a single MP seat in our State. The people of AP punished the BJP for not delivering, and decided to give the YSR Congress Party and their leader, Shri Y. S. Jaganmohan Reddy *Garu* one chance to get from the Centre what the Telugu Desam Party was unable to get. In fact, this was and continues

to be the single most important issue for the people of Andhra Pradesh. The responsibility now lies with Shri Y. S. Jaganmohan Reddy *Garu* and the YSR Congress Party to deliver on our rights.

(1235/VR/YSH)

Now, after meeting the Prime Minister and the Home Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy Garu is saying that he will keep on asking, while we understand that the response from the Prime Minister has been categorical that Andhra Pradesh will not get special category status. Even the Finance Minister in a written response to an Unstarred Question in Rajya Sabha yesterday has also said that no State would be given this status. With the mandate given by the people of Andhra Pradesh to the YSRCP, giving them 22 MPs, all eyes are now on them to see how they will succeed where we were unable to do so. I, indeed, wish for them all success for the sake of Andhra Pradesh.

I also wish the Prime Minister all success and hope that his slogan of *Sab ka Saath, Sab ka Vikas, Sab ka Vishwas* will apply to all regions, States, and people equitably.

Since I have very limited time, I will directly come to a couple of points I wish to focus on. We have built our institutions brick-by-brick over decades, destroying, tinkering, weakening or weaponizing these institutions will cripple our democracy which we are proud of; and if corrective measures are not taken, it will ultimately destroy our freedom and liberty.

I am neither saying that this was started by the BJP nor am I blaming any other Government. All I am saying is that it reached its peak during the

Emergency and we are seeing a similar scenario now as well. There are many examples but I will give only three examples.

The first is the notification issued by the Home Ministry in December, 2018 under the IT Act on monitoring, decryption of information generated, transferred, received or stored in a computer source without any requirement to get any authorization from anyone in the Government.

The second is the misuse of the Election Commission during recent elections, which many of the hon. Members have spoken about.

The third and the latest one is how the BJP is breaking our party and grabbing four of our Rajya Sabha MPs by resorting to coercive politics and weaponizing institutions.

The hon. Prime Minister in all his speeches is using the phrase *Sab ka Saath.* But what is happening on the ground and in Parliament and State Assemblies is the other way around. They were happening earlier and are continuing even today. So, I ask the hon. Prime Minister: "Does he want history to show that this Government is making it worse or that it is making it better? Sir, what is the meaning of these slogans? Does he want that all parties should join BJP? Is that the meaning of *Sab ka Saath*? Can we not be together if we are in different parties? Can we not be together if we speak different languages? Can we not be together if we have different beliefs? Can we not be together if we have different diets? Can we not be together if we wear different clothes? So, what is the meaning of *Sab ka Saath*?

The real meaning of *Sab ka Saath* is that you should be taking us along with you to build this great country. It does not mean that you gobble MPs from other parties. It does not mean that you scare others by using CBI, IT, ED and other agencies. No party, however powerful it may be; no leader, however powerful he or she may be and no institution should be able to dictate terms or impose their wishes on smaller and regional parties. If this is allowed, it is tantamount to giving liberty to wolves which results in death of lambs.

Sir, the second point which I want to make is a very important point. Then, I will conclude it. The former Chief Economic Advisor to the Government, Shri Arvind Subramaniam has sent ripples and contested the GDP figures between 2012 and 2017. In his Working Paper presented to Harvard University, he mentioned that the growth figures have been inflated by 2.5 percentage points during this period. If this is true and if we had known, the Government could have taken necessary steps on the banking system and challenges in agriculture which may have resulted in reduced NPAs and also helped the farmers a lot. Now, the entire country is worried what the correct figures are.

(1240/SAN/RPS)

The fourth quarter growth figure of 2018-19 stands at 5.8 per cent which is less than that of China for the first time in the last few years. This figure is

really putting a question mark in the minds of people whether the Government has really inflated the growth figures or not.

It is not just the economic data, even the unemployment figures had also been suppressed, which stands at an all-time high in the last 40 years. This puts a cloud of doubt on our data and figures because we are not able to get the correct picture. If we cannot trust the figures, how do we plan, how do we make policies, how do we make laws and how do we measure their impact on the people? If we make laws in the absence of correct and trusted figures, this Parliament will be driving in the dark without the lights on. I am saying this because if we legislate with either inflated or with suppressed figures, how do we know if our decisions will have positive impact on the people or not. In such a scenario, the whole planning, budgeting and law-making process becomes meaningless. How are you going to ensure *sab ka vikas* when the data given by the Government is being questioned?

Sir, the correct figures are all the more important since we are in the Budget Session now and the Finance Minister is going to present the Budget just in a few days from now. The *Economic Survey* is also going to be presented to the House on the 4th of next month. I am sure, the figures of the *Economic Survey* have already been finalised and we cannot change them now, but the moot point is: Can we trust this data?

Sir, I suggest for the consideration of the hon. Prime Minister to constitute a Task Force consisting of national and international experts, statisticians,

macro-economists and policy-users who will be able to verify the data. This will then give the country a real and credible picture.

Sir, how are you going to win *sab ka vishwas* when there is already a sense of doubt in the minds of people on the economic growth figures, credibility of institutions, and shattering moral and ethical values in polity?

These are some of the observations I wish to make within the limited time at my disposal. Thank you.

(ends)

***श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़):**

---

* Laid on the Table

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):**

---

* Laid on the Table

सभापति तालिका के लिए नाम-निर्देशन

1242 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत, मैं निम्नलिखित सदस्य को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित करता हूं :

1. श्री सुरेश कोडिकुन्निल ।

समयाभाव के कारण अन्य नाम प्राप्त होने के बाद घोषित कर दिए जाएंगे।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

1243 hours

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. I stand here in support of the Motion.

1243 hours (Shri Suresh Kodikunnil *in the Chair*)

In the elections, the people of the country gave a massive mandate to the leadership and policies of Shri Narendra Modiji's Government. People have hailed the corruption-free, sincere and capable development, governance and performance of Shri Narendra Modiji's Government and the *Sab ka Saath, Sab ka Vikas* principle.

Sir, people wanted a stable and able leadership that they could find with BJP and Shri Narendra Modiji. What has not been developed in the last 70 years has been developed just in the last five years of Shri Narendra Modiji's Government, be it the robust economy, Ayushmaan Bharat Yojana, health protection initiatives, Saubhagya Yojana or Electricity to All Homes. For the last 65 to 70 years, even after Independence also, most of the villages in the country did not have electricity, but after our Government came, electricity has reached each and every village of the country. This Government launched PM Awas Yojana, Housing for Poor, Swachh Bharat Abhiyan. Today, there are toilets in every village. Even after 65 to 70 years of Independence, we did not have toilets in all the villages. Ladies used to go for toilet in the early morning or late in the night. Now, toilets are there in all the villages due to the initiative taken by this

Government. This Government also launched Ujjwala Yojana, giving free LPG connection to the poor. Then, there were also started Jan Dhan Yojana, Beti Bachao Beti Padhao, Atal Pension Yojana, MUDRA loans, loans for empowering the poor, Jan Aushadi Centres for providing quality medicines at lower cost.

(1245/SM/RAJ)

Sir, in the guiding spirit of National Ambition and Regional Aspiration (NARA) as envisaged by our Hon. Prime Minister, I wish to speak on three important topics from Hon. President's Address to the Parliament which are also important for my State and my constituency.

Sir, I represent Bangalore Central constituency. Once upon a time, Bangalore was called 'lake city'. Today, the lakes have been encroached because of negligence by the local bodies. Lakes have been neglected and water bodies have been encroached. There are lakes and water bodies but there are no water sources for that. There are some lakes in which water is there, but the water is polluted. I have a request to the Central Government. Already, in the AMRUT Scheme, they have given adequate funds. I want to bring it to your notice that Bangalore is called Silicon Valley of India. In my constituency, Mahadevapura constituency, there is Bellandur Lake. That is in news not only in Bangalore, in Karnataka but throughout the country and even in the world also because the frothing is there. Sometimes, new person comes to Bangalore. He will think whether it is snow or froth. It is in such a bad condition. I request the Central Government and the Urban Development Ministry. They have already given adequate funds to lake development and rejuvenation for Karnataka. But

as a special case, I request the Government to take up this lake as a special case and give adequate funds to the State Government or take directly under the Central Government and develop this lake.

Sir the second thing is that I request the Central Government to release more funds for Sewage Treatment Plant (STP) so that where water bodies have no water source, this treated water can be left into that.

My next subject is relating to urban transport. Today, Bangalore has more than 1.2 crore population. By another 10 years, it is expected that around 2 crore population is going to be there. Bangalore is becoming a bad news for our traffic. There are traffic jams. Everybody talks about Bangalore traffic. When I call anybody from here in Bangalore, they say, “Bangalore traffic is so much. How will I reach there?”

I thank our Government that in the last Budget, for suburban project, Rs.17,000 crore had been sanctioned. But the State Government is not very keen. So, I request the Government also to take extra initiative. Last time, in the month of February, the Railway Minister, Shri Piyush Goyal also came to Bangalore. He met the Chief Minister of Karnataka. There were lot of issues which were sorted out also. Even then, the Government is delaying in making a Special Purpose Vehicle (SPV) and implementing the project. This is a very important project because as per the report of RITES, it can carry about 35 lakh passengers per day and about 25 per cent of the traffic can also come down on the road. So, this is an important thing. I request the Central Government again to speak to the State Government and sort out the issues and start this project

so that it will be helpful to our Bangalorians also. This is a very important project and I request the Urban Development Ministry also to give adequate funds to the State Government to develop the lakes.

Thank you very much Sir.

(ends)

***श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर):**

---

* Laid on the Table

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):**

---

* Laid on the Table

***श्री अजय कुमार (खीरी):** माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सर्मथन व धन्यवाद हेतु लिखित प्रतिवेदन।

दिनांक 20 जून को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद की समवेत सभा को दिए गए उनके उद्बोधन का समर्थन करते हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने जहां पिछले पांच वर्ष में एनडीए की मोदी सरकार की उपलबिधयों के विषय में बताया, वहीं न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट हेतु एनडीए सरकार व मोदी जी की प्राथमिकताओं को भी देश के सामने रखा है।

मेरा पूरा विश्वास है कि वर्ष 2024 तक हमारा देश न केवल लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सक्षम होगा बल्कि देश आर्थिक, रक्षा क्षेत्रों में सक्षम होने के साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार व आतंकवाद को समाप्त करके देश के लोगों को मकान, बिजली, पानी, शिक्षा व चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साथ ही पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपना स्थान बनाएगा। धन्यवाद।

(इति)

---

* Laid on the Table

1247 hours

SHRI CHIRAG PASWAN (JAMUI): Thank you very much Speaker, Sir, for giving me this opportunity. आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से हुई मासूम बच्चों की मौत के ऊपर अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। मौत के आंकड़े असीम पीड़ा देने वाले हैं। मेरा मानना है कि प्रकृति हमें तब ही दंडित करती है, जब चूक कहीं न कहीं हम से ही होती है। विकास की ब्यार को हमारी सरकार गति देना चाहती है, उस गति में कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं बाधक के रूप में साबित होती हैं।

(1250/IND/AK)

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में कम से कम इस तरीके की घटनाएं न घटें। लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले पांच साल देश की प्रगति की राह में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया है। लोक सभा के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी परीक्षा के तौर पर थे कि हमने जो किया, जैसा किया, क्या वह सही दिशा में था। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस अंदाज़ में मेरे प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद हमें दिया, उससे एक बात साफ है कि एनडीए की राह ही भारत की राह है। खुली आंखों से देखा गया प्रधान मंत्री जी का महान और विकसित भारत का सपना कहीं न कहीं सम्पूर्ण देशवासियों का सपना है। पिछले पांच साल पहले के 55 सालों की विसंगतियों और गड़बड़ियों को ठीक करने के साल रहे और वहीं आने वाले पांच साल एक नए भारत की आधारशिला रखने के पांच साल होंगे। ये ऐसे पांच साल होंगे, जहां 'हर पेट को रोटी' और 'हर हाथ को काम' के नारों को हम सिर्फ कहने के लिए ही नहीं कहेंगे, बल्कि हम यह साबित करके दिखाएंगे कि यह हमारी सरकार का उद्देश्य है।

महोदय, मैं जमुई की सम्मानित जनता, जिसने अपनी आवाज सदन में पहुंचाने के लिए मुझे दूसरी दफा यह जिम्मेदारी दी है, को धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि बिहार विकास की सूची में बहुत अग्रणी राज्य नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मैं एक ऐसे लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि बिहार प्रदेश का सबसे पिछड़ा लोक सभा क्षेत्र है। ऐसे में मेरे जैसे जन प्रतिनिधि हमारे प्रधान मंत्री जी के मुख से 'नल से जल' जैसे संकल्प की बात सुनते हैं, तब हमारी खुशी हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। वर्ष 2024 तक हर घर में पाइप वाटर पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है, जो कि अभी तक महज 18 फीसदी है, मतलब 70 सालों में केवल 18 फीसदी घरों में ही नल द्वारा जल पहुंचाया गया। आने वाले पांच साल में इसे 82 फीसदी बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने का हमारा जो लक्ष्य है, उसे हम जरूर पूरा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जिस तरीके से साफ पीने के पानी की किल्लत है, ऐसे में हमारी सरकार का यह संकल्प और उसे पूरा करने के लिए जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से हमारे प्रधान मंत्री जी को साधुवाद अर्पित करता हूं।

महोदय, देश के हर घर में रसोई गैस, शौचालय और बिजली के बाद 'नल से जल' का संकल्प आजादी के 75 साल पूरे होने पर विकास के नए मानक के तौर पर खड़े होंगे और यही महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने संबोधन में कहा। ये सब विशाल कल्पना का अग्रिम संदेश है, जिस विशाल कल्पना को हम नया भारत कहते हैं। नया भारत एक ऐसा भारत है, जहां हमारी केंद्र की सरकार जात-पात, धर्म, मजहब से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए काम करेगी। राष्ट्रपति महोदय ने भी गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की पंक्तियों को कोट करते हुए कहा था कि नया भारत आदर्श भारत की दिशा में एक कदम होगा जहां लोग भय मुक्त और आत्म सम्मान युक्त होकर काम करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को नए भारत में व्यंग दिखता है, लेकिन मेरे लिए नया भारत वह होगा जहां सीवर में सफाई करने वाले मेरे दलित मजदूर भाइयों की मौत की खबरों पर विराम लगेगा। मेरे लिए नए भारत में विपक्ष का व्यंग नहीं, बल्कि दलित और

मजदूरों की जिंदगी में रंग देने की कोशिश होगी, जो कि मुझे ईमानदारी से मोदी सरकार की प्रतिज्ञा में दिखाई देती है। मेरे लिए नए भारत में मुस्लिम समाज की मेरी बहनों को अपना मुस्तक़बिल चुनने की आजादी होगी। हमने हाल-फिलहाल के दिनों में देखा है कि अपनी शिक्षा और सामर्थ्य से मुस्लिम समाज के युवाओं ने नए मुकाम हासिल किए हैं, जो मजहब की सियासत नहीं करते, उनके लिए यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि मजहब का सम्मान और प्रगति एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसी उद्देश्य के साथ 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ इस बार हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने "सबका विश्वास" भी इसमें जोड़ा है।

महोदय, कृषि समाज एक ऐसा समाज है, जिसके लिए शब्दों में तो बहुत ज्यादा फोकस रहा, लेकिन हकीकत में धरातल पर उतरते हुए कभी नहीं देखा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की दिशा साफ है कि किसान भाइयों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी की जाएगी और मुझे गर्व है कि प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया। लेकिन मुझे जिज्ञासा होती है कि अभी तक पूर्व में जो सरकारें किसानों की बात करती थीं, क्या उन्हें अभी तक यह दिखाई नहीं दिया कि किस तरीके से हमारे भारतीय किसानों के आगे से "खुशहाल" शब्द गायब होता गया और वे आत्महत्या करने को मजबूर होते गए, जिसका एक उदाहरण हमने देखा कि राजस्थान में एक किसान भाई ने आत्महत्या की। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पर, वहां के मुख्य मंत्री, वहां के उप-मुख्य मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी देते हुए आत्महत्या की, यह अपने आप में एक दुखद समाचार है और यह दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता निरंतर झूठे वायदे करके कर्जमाफी का लालीपॉप दिखाकर किसानों से उनका मत तो लेते हैं, लेकिन जब सही मायने में कुछ करके दिखाने की बात आती है, तो उस वक्त वे अपना हाथ खींच लेते हैं। बहरहाल मोदी सरकार की जो 'किसान सम्मान निधि' योजना है, वह उसी खुशहाली के दौर में किसानों की वापसी के प्रयास का पहला कदम है।

(1255/VB/SPR)

छह हजार रुपये की राशि शायद उन लोगों को कम लगती होगी, जिनकी अंगुलियाँ निरंतर महँगे मोबाइल फोन पर काम करती रहती हैं, लेकिन जिनकी अंगुलियाँ खेतों में काम करते-करते सख्त हुई हैं, उनके लिए यह राशि मोदी सरकार की किसान के प्रति ईमानदारी का प्रमाण है।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब हमारे विपक्ष के मित्रों से प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा- It was hollow. हो सकता है, मैं सियासत को थोड़ा कम समझता हूँ, मगर युवा भारत की धड़कनों को तो मैं समझ ही पाता हूँ। हॉलो क्या था, यह मेरी समझ के परे है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे शूरवीरों द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक खोखला था या पुलवामा हमले के जवाब में किया गया बालाकोट का एयर स्ट्राइक खोखला था या आतंकवाद के खिलाफ सशक्त मुहिम के जरिए मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित आतंकी घोषित करना खोखला था?

हम सब के लिए एक बात खास तौर से स्पष्ट है, जितने युवा हैं, उनके लिए एक बात स्पष्ट है कि देश से बड़ा कुछ नहीं और देश-प्रेम हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है।

राफेल विमानों को राजनीति की हवाई पट्टी पर लैंड करने की इज़ाजत नहीं देकर देश की जनता ने अपना संदेश साफ कर दिया है। मैं उस कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा हूँ, जब देश में पहला राफेल विमान आएगा और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी उसमें बैठकर देश की सीमाओं के सुरक्षित होने का आकलन करेंगे।

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे पूरा विश्वास है कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, उस खाई को आने वाले समय में भरा जाएगा और गाँव एवं शहर के बीच की दूरी को समाप्त करके सही मायने में एक नये भारत का, एक न्यू इंडिया का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग हासिल कर पाएँगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):

*Laid on the Table.

***श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर):**

---

* Laid on the Table

1257 hours

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I rise to oppose the Motion and to speak in support of the amendments made by our Party.

First of all, let me begin by humbly accepting the resounding mandate that this Government has got. But it is the very nature of the overwhelmingness of this mandate, of the totality of this mandate that makes it necessary for us to be heard today, for the voice of dissent to be heard today. Had the mandate been any less, there would have been a natural check and balance woven into the narrative. That is not the case. The House belongs to the Opposition. So, I stand today to reclaim this inch that has been guaranteed to us.

Let me first start by quoting Maulana Azad, whose statute stands tall outside this great hall. He once said of the country that he was fighting to build that it is India's historic destiny that many human races and cultures should flow to her, finding a home in her respectable soil and that many a caravan should find rest here, where our cultures, our languages, our poetry, our literature, our art, the innumerable happenings of our daily life shall bear the stamp of our joint endeavour. This is the ideal that was carved into our Constitution. This is the very Constitution that each of us has sworn to protect. But this Constitution is under threat today. Of course, you may disagree with me. You may say *achhe din* are here, and the sun would never set in this Indian Empire that this Government is seeking to build. But then you are missing the signs. You are

missing the signs and if you would only open your eyes, you would see that there are signs everywhere. That this country is being torn apart.

In the few minutes that has been allotted to me, let me list out these dangerous signs. The first sign is this. There is the powerful and continuing nationalism that is searing into our national fabric. It is superficial, it is xenophobic…. …(*Interruptions*) Sir, there is no room for professional hecklers; inside the corridors of this great Hall. There is no room. I urge you to put the House in order.

There is a powerful and continuing nationalism being sneered into our national fabric. It is superficial; it is xenophobic; and it is narrow. It is the lust to divide; it is not a desire to unite. Citizens are being thrown out of their homes and being called illegal immigrants. People who have lived in this country for 50 years are having to show a piece of paper to prove that they are Indians. In a country where Ministers cannot produce degrees to show that they have graduated from college, you expect dispossessed poor people to show papers, to show that they belong to this country.

(1300/UB/PC)

Slogans and symbols are being used to test allegiance. There is no one symbol or there is no one slogan that can show any Indian that he is a patriot. There is no one test!

The second sign: There is a resounding disdain for human rights that is permeating every level of the Government. There has been a ten-fold increase in the number of hate crimes between 2014 and 2019. It is like a valuation of an e-commerce start-up. There are forces in this country that are sitting there just pushing this number up. The lynching of citizens in broad daylight is being condoned from Shri Pehlu Khan in Rajasthan last year to Shri Ansari in Jharkhand yesterday, the list is not stopping.

The third sign: There is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. Five of the largest news media organisations in India are today either indirectly controlled or indirectly indebted to one man in this country. TV channels spread a majority of airtime broadcasting propaganda for the ruling party, coverage of every opposition party is cut out. Let the Government come out with facts and figures to show ad-spend per media house, what they are spending the money on and which media house they are blocking out. The Information and Broadcasting Ministry employs over a 120 people solely to check the content on TV channels every day to make sure that there is no anti-Government news being put out.

Fake news is the norm. This Election was not fought on farmers' distress, this Election was not fought on unemployment but this Election was

fought on Whatsapp, on fake news and on manipulating minds. Every piece of news that this Government repeats, every piece of news that they put out, every lie that they put out, they repeat and repeat till it becomes a truth. This is the Goebbels' Doctrine. They talk of *Namdar* and *Kamdar*. Let me tell you, the Congress Party may have put up 36 dynasts since 1999 in Parliament but the BJP has put up 31. I tell you that every time they put out one figure, one fact, that is not the truth. They are destroying the fabric of India…(*Interruptions*).

Sir, this is not a place for professional heckling. I urge you to put the House in order. I will wait. I urge you to put the House in order…(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): The House is in order. You may continue.

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Yesterday, the Floor Leader of the Congress Party said that the cooperative movement has been a failure in West Bengal. I urge him to check his facts. The one cooperative that he is referring to is the Bhagirathi Dairy in Murshidabad which is now in profit. Every small misinformation that is put out serves to destroy this country.

The fourth sign: There is an obsession with the national security…(*Interruptions*). Sir, it is my maiden speech. I will conclude. There is an obsession with the national security and the identification of enemies. When we were children, my mother would say, "Do this and do that, otherwise, *kala bhoot* will come". It is as though all of us in this country are today in fear of nameless, shameless '*kala bhoot*'. There is fear pervading everywhere. The achievements of the Army are being usurped in the name of one man. Is this

correct? New enemies are being created every day…(*Interruptions*). I urge you, Speaker Sir, no professional heckling should be allowed. The irony is that over the last five years, terrorist attacks have gone up manifold. There has been a 106 per cent increase in the death of *Jawans* in Kashmir.

The fifth sign: Religion and Government are now intertwined in this country. Do I even need to speak about it? Neither should I remind you that we have redefined what it means to be a citizen. With the NRC and the Citizenship (Amendment) Bill, we are making sure that it is only one community that is the target of anti-immigration laws.

Members of Parliament today are more interested in the fate of 2.77 acres of land than in the 812 million acres of the rest of India. यह सिर्फ 2.77 एकड़ जन्मभूमि का मुद्दा नहीं है। यह देश की 80 करोड़ एकड़ को अखण्ड रखने का प्रश्न है। मैं आपको बोलती हूं।

The sixth and the most dangerous sign: There is a complete disdain for intellectuals and the arts. There is a suppression of all dissent. Funding is being cut for liberal education. Scientific temperament is enshrined in article 51 of the Constitution.

(1305/KMR/SPS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): Hon. Member, please conclude now. You have already taken three minutes.

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): This is my maiden speech, Sir, please give me two more minutes.

Article 51 of the Constitution demands a scientific temperament. Everything we are doing is pushing India back to the dark ages. Secondary school textbooks are being manipulated and distorted in order to indoctrinate. You do not even tolerate questioning let alone dissent. The spirit of dissent is integral to India. You cannot shackle us. I wish to quote the great Hindi poet Ramdhari Singh Dinkar here.

"हां हां दुर्योधन बांध मुझे,
बांधने मुझे तू आया है,
जंजीर बड़ी क्या लाया है,
सूने को साध न सकता है,
वह मुझे क्या बांध सकता है।"

I tell you this, you cannot keep us down.

The seventh and the last sign is, there is an erosion of independence in our electoral system. The Election Commission is being used to transfer key officials. Rs.60,000 crore were spent on this election of which Rs.27,000 crore, 50 per cent, were spent by one party.

In 2017, the United States Holocaust Memorial Museum put up a poster in its main lobby. It contained a list of all the signs of early fascism. Each of the seven signs that I have pointed out to you feature on that poster. There is a danger of fascism rising in India. It is incumbent upon all of us to stand up to it. Let us, the Members of this 17th Lok Sabha, decide which side of history we want to be on. Do we want to be upholders of this Constitution or do we want to be its pallbearers?

I do not dispute the resounding mandate that this Government has got. But I have the right to disagree with your idea that there is no one before you and there shall be no one after you.

HON. CHAIRPERSON: Your allotted time is already over. Please conclude.

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, In conclusion I quote poet Rahat Indori.

“जो आज साहिबे मसनद हैं, वह कल नहीं होंगे,
किरायेदार हैं, जाति मकान थोड़ी है,
सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में,
किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़े ही है।”

(इति)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, 352(1), यह मैडन स्पीच थी, इसलिए मैंने नहीं रोका। 352(1) में इन्होंने एन.आर.सी. की बात की है और राम जन्म भूमि के 2.77 एकड़ की बात की है। दोनों ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में हैं, दोनों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे इनकी स्पीच से एक्सपंज कर दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Nishikant Ji, I will check the record.

***श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा):**

----

* Laid on the Table

***श्री पी. पी. चौधरी (पाली):**

---

* Laid on the Table

1308 बजे

श्री दिलीप घोष (मेदीनिपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, माननीय प्रताप सारंगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, from yesterday I have been noticing that the Members of the Ruling Party are using this green book, without any reference, without any understanding, to impede the Opposition's right to protest. Yesterday I spoke of the Election Commission. Where in the book is it written that the Election Commission cannot be discussed? They raised their point. About Ram Janmabhoomi 2.77 acres, where is it written that Ram Janmabhoomi cannot be discussed? All these are bogus points. Mr. Nishikant Dubey is a past master and he has been put up by the Ruling Party to obstruct the Opposition, and Mr. Rajiv Pratap Rudy is his colleague. They together are obstructing the freedom of speech of the Opposition. I strongly oppose the wrongful use of Rule 352 and the way he is trying to protest.

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ji, we are going according to rules. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. All of you are senior Members. Nishikant Ji, you are well aware of the rules and Sougata Ji is also well aware of the Rules.

(1310/SNT/KDS)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सौगत बाबू प्रोफेसर हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): You are a senior Member. He is also a senior Member. You are well aware of the rules. Also, Sougata Ray*ji* is well aware of the rules.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : 352(1) और 352(5) यदि उनको पढ़ना नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? कौल और शकधर में देख लीजिए। 5 में इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, 5 में सी.ए.जी. दिया हुआ है, 5 में कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल दिया हुआ है।

HON. CHAIRPERSON: Now, we are discussing on Motion of Thanks on the President's Address.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मुझे क्या पता कि इनको नहीं मालूम है । सर, वह सीनियर हैं। हम इनसे सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है या ममता जी को डिफेंड करते हुए इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि इनको नियम-कानून ही नहीं पता। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down Sougata Ray*ji*. You please continue Dilip Ghosh.

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर) : धन्यवाद, महोदय। मैं पहली बार सदन में आया हूँ और इस ऐतिहासिक सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी का ऐतिहासिक भाषण हुआ है, उनके पक्ष में धन्यवाद ज्ञापन का जो प्रस्ताव माननीय प्रताप सारंगी जी ने रखा हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दो-चार शब्दों में मुझे बोलना है। महोदय, हमारे प्राइम मिनिस्टर केवल देश में ही पॉपुलर नहीं हैं, बल्कि जापान से जर्मनी, आस्ट्रेलिया से अमेरिका, हर जगह मोदी-मोदी हो रहा है। इसलिए, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को जीने के लिए जो प्राथमिक वस्तुएँ चाहिए- खाद्य, वस्त्र, स्थान, चिकित्सा और शिक्षा, इन सारी बातों पर गहराई से चिंतन करके जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ बनाई गई हैं, उनका लाभ देश को मिल रहा है। इसलिए सारे

देश में खुशहाली है, लेकिन मुश्किल होती है कि ऐसे महान नेतृत्व पर कुछ लोगों का विश्वास है या नहीं, यह तो मालूम नहीं है, लेकिन सम्मान देने की भी उनकी आदत नहीं है। सीनियर लीडर बोलते हैं कि …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) से हम घृणा करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि एक वरिष्ठ नेता, जो बंगाल से आते हैं और जो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस बात का मुझे खेद है। बंगाल के लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं इसका खण्डन करता हूँ। अच्छा हुआ कि देश से इन्होंने माफी माँगी ली है, जिससे हमारी भी इज्जत बच गई। सर, मैंने सीनियर लीडर से सुना है कि वह ओल्ड इंडिया में जीना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा ओल्ड इंडिया उनको पसन्द है? वह इंडिया, जिसमें साम्प्रदायिक दंगा होता था, जिसमें जात-पात था, भ्रष्टाचार से डूबा हुआ इंडिया, महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार होने वाला इंडिया, तंदूर काण्ड वाला इंडिया, वही इंडिया चाहते हैं क्या? हम तो नहीं चाहते हैं। हम तो न्यू इंडिया चाहते हैं और आज न्यू इंडिया में एक से एक नौजवान हैं। सारी दुनिया में न्यू इंडिया का बोलबाला है। यह न्यू इंडिया हम चाहते हैं, इसको हम बनाकर रखेंगे।

महोदय, मैं कल एक जगह गया था। एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया था, जहाँ सारे लोग लगभग राजस्थान के मूल निवासी व्यवसायी थे। एक व्यवसायी ने मुझसे बोला – 'दिलीप दा, हमारे परिवार के लोग, हमारे सम्प्रदाय के लोग कहते थे कि राजनीति बहुत गड़बड़ है, इसमें हिंसा है, भ्रष्टाचार है। इसमें नहीं जाना है। लेकिन आज हमारे घर के जवान लड़के, जो एम.बी.ए., इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वह बोलते हैं कि आज राजनीति में भी जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी जी ने डायरेक्टशन चेंज कर दिया। आज की नौजवान पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। यह न्यू इंडिया हमने बनाया है, हम इसी में जीना चाहते हैं। हम उस ओल्ड इंडिया में नहीं जाना चाहते हैं। महोदय, इस सरकार ने सैकड़ों महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजनाएँ चालू की हैं लेकिन, हम बंगाल के लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि इन सारी योजनाओं का लाभ हमको नहीं मिल पाता है। ऐसी मुख्यत: तीन योजनाएँ हैं। पहली है आयुष्मान योजना। इससे 50 करोड़ लोगों को सुविधा मिलने वाली है, लेकिन करोड़ों बंगालियों को इसकी

सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लेती है। इसीलिए हमको वंचित रखा गया है और जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि जहाँ हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है और यदि डॉक्टर है तो नर्स नहीं है। नर्स है तो दवाई नहीं है और दवाई है तो बेड नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। बंगाल के करोड़ों लोगों को इससे वंचित रखा गया है। सर, दूसरी, किसान सम्मान निधि योजना जो केन्द्र सरकार ने शुरू की है, उससे भी हमको वंचित रखा गया है। लोग बोलते हैं कि वहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं, तो फिर क्यों उनको 6 हजार रुपये के लिए वंचित करते हैं? आज तक वहाँ की सूची नहीं भेजी गई है। पूरे देश के लोगों को सुविधा मिल रही है, किन्तु वहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। देश में 30-35 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, लेकिन बंगाल को नहीं मिल रहा है। एक और अच्छी बात का मैं उल्लेख करता हूँ। हम बंगाल से आते हैं। बंगाल के लोग मछली खाना पसंद करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी शाकाहारी हैं, सादा भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बंगाल के लोगों की चिन्ता है कि उनको मछली ठीक-ठाक मिले, क्योंकि बंगाल में मछली को पौष्टिक भोजन का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने मछली पालन और उत्पादन के लिए अलग विभाग और दफ्तर बनाए। बंगाल के लोग जितना उपयोग करते हैं, उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसका लाभ बंगाल को मिलेगा। इस हेतु मैं विशेष रूप से माननीय नरेन्द्र मोदी जी और उनके मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूँ और यह काम हमारे लिए विशेष रूप से लागू हुआ है।

(1315/SJN/RK)

महोदय, अभी हमारे मित्र बंगाल के बारे में बोल रहे थे। जो बंगाल कभी देश को दिशा देता था, जो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलनों में सबसे अग्रणी रहा, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने देश और दुनिया को बहुत-सी चीजें दी हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों में, विज्ञान में, खेल-जगत में, ज्ञान के जगत में, सैनिक स्थिति में, हर जगह में बंगाल का योगदान रहा है। नया-नया इनोवेशन हुआ है। अभी बंगाल से एक नई बात आई है – कट मनी। हमारे मुख्य मंत्री ने कट मनी का नया इनोवेशन किया है, जिसे आपने कभी सुना ही नहीं होगा, मैं उसकी व्याख्या करता हूं। कट मनी क्या होता है? हमारे

प्रधान मंत्री जी बंगाल के विकास के लिए जो पैसा भेजते हैं, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, उसमें जो लाभार्थी होते हैं, उनको पहले पैसा भरना पड़ता है, तब जाकर उनको घर मिलता है, उनको शौचालय मिलता है, उनको बाकी सुविधाएं मिलती है। इसको कट मनी कहा जाता है। इसको रेकग्निशन मिला है। *… (Not recorded)* इसको बोल रही हैं, जिन्होंने आठ साल तक कट मनी लूटा है, लोग उनके घरों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रही हैं कि हम कट मनी वापसी के लिए अलग से एक कानून बनाएंगे। यह वहां की बड़ी पापुलर गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट आठ साल से चल रही है, पूर्ण बहुमत है, फिर भी उनके एमएलए, एमपी, काउंसिलर, पंचायत भाग-भागकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसी पापुलर गवर्मेंट है। यह बड़ी ही चिंता की बात है। वहां तो हालात ऐसे हैं। आप जाइएगा, सरकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था नहीं है। आप गणतंत्र ढूंढ़ते रह जाएंगे कि कहां पर है? थाना है, पुलिस नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है, कालेज है, प्रोफेसर नहीं हैं, धरने पर बैठे हैं। कोर्ट है, लॉयर नहीं है। ऐसा बंगाल है, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसा सोनार बांग्ला बनाकर हमारी मुख्य मंत्री ने हमको दिया है। हम उसी में रह रहे हैं। इसीलिए आज हमको यहां आना पड़ा।

मैं बंगाल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनको आइना दिखाया और हमारे 18 लोगों को जिताकर यहां पर भेजा है। वह बंगाल, कभी रवीन्द्रनाथ का, कभी अरविन्द का और कभी रामकृष्ण का माना जाता था। आज वहां बंगाली, बिहारी, हिन्दीभाषी-बंग्लाभाषी में भेद किया जा रहा है। धर्म में भेद करके राजनीति होती थी, अब भाषा में भेद किया जा रहा है।

मेरे मित्र अर्जुन सिंह जी बैठे हुए हैं, वे आज बाहरी हो गए हैं। उनके पूर्वज बिहार और यूपी से वहां पर रहने के लिए गए थे, अब उनको बाहरी कहा जा रहा है। ऐसा विचार कभी हम लोगों ने नहीं सुना है। इस पर मारपीट हो रही है, हिंसा का वातावरण है। देश में 542 सीटों पर चुनाव हुआ है। 500 सीटों पर कोई झंझट नहीं हुआ, लोगों ने शांतिपूर्वक वोट डाला। लेकिन बंगाल की केवल 42 सीटों पर मारपीट हुई, खून-जख्म हुआ।…(व्यवधान) लोगों ने रास्ता अवरोध किया। वहां मतदाता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। सरकार है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है।…(व्यवधान) और भी

मजेदार बात है, जब वहां हमारे मित्र ईवीएम से हार जाते हैं, तो बैलेट की बात करते हैं। जब बैलेट से हार जाते हैं, तो ईवीएम की बात करते हैं। जब सब जगहों पर हार जाते हैं, तो चुनाव को बंद कर देते हैं। अभी 18 में म्यूनिसिपेलिटी का चुनाव बंद है, इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार जाएंगे। बाई-इलेक्शन बंद है। अभी आठ जगहों पर बाई-इलेक्शन हुआ, जहां हमारी एक भी सीट नहीं थी, हमने चार सीटें जीतीं, हमारे मित्रों ने तीन जीतीं और कांग्रेस ने एक जीती। लोगों ने मैन्डेट दे दिया। आप लोगों को राम-राम, सत्ता छोड़ दीजिए, जो योग्य है, उसे सत्ता संभालने दीजिए। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। इस परिस्थिति में यहां 'नहीं' नहीं है, यहां आसन है, लेकिन सदस्य मौजूद नहीं हैं, देखिए। बंगाल की परिस्थिति इससे भी बदतर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज जिस प्रकार की दहशत चल रही है, कानून पूरे देश में एक होता है। लेकिन आप बंगाल मत जाइएगा, बोलते हैं कि आपको बंगाली सीखकर आना पड़ेगा। अगर माननीय हेमा दीदी गंगासागर स्नान करने जाना चाहती हैं, तो पहले उनको बंगाली सीखनी पड़ेगी। अगर मंत्री महोदय कोलकाता जाएंगे, तो आपको बंगाली सीखकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे प्रधान मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी जी अगर बंगाल जाना चाहें, तो उनके हेलीकाप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपको जाकर वापस आना पड़ेगा। हमारी मुख्य मंत्री की बहुत इच्छा है कि वह प्रधान मंत्री बनें। शुक्रिया है, कोई बंग्लाभाषी प्रधान मंत्री बने, तो हम बंगाली में बात करेंगे। लेकिन होता क्या है कि 42 सीट जीतकर कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए उन्होंने योजना बनायी कि बांग्लादेश को बंगाल में मिला लो और दोनों को मिलाकर देश बने, तो वहां मेजोरिटी बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसीलिए उनके पास चुनाव में नेता पापुलर नहीं है, तो बांग्लादेश से अभिनेता को प्रचार करने के लिए लाया गया था। वह बाहरी नहीं है। वहां से घुसपैठिए आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं, वे बाहरी नहीं हैं। इटली से कोई आ जाए, तो वह बाहरी नहीं है। लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी चले जाएं, माननीय अमित शाह जी चले जाएं, तो वे बाहर के लोग हैं। आप बंगाल में नहीं जा सकते हैं, आपको अनुमति नहीं है।

इसीलिए हम जय श्रीराम बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं। भगवान राम मर्यादा परुषोत्तम थे। आदर्श राज्य कैसा होता है, उन्होंने दिखाया है।

(1320/GG/PS)

इसलिए हम राजनीति करने वाले लोग उनको जय श्री राम बोलते हैं। यह कोई धार्मिक स्लोगन नहीं है। ये लोग गलतफहमी में बैठे हुए हैं। उसके बदले में क्या बोलते हैं – जय बंग्ला। जय बंग्ला बंगाल में है तो देश में यह स्लोगन कब हुआ? यह तो बंग्लादेश का स्लोगन है। सब कुछ बंग्लादेश से ला रहे हैं। बंगाल को पश्चिम बंग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि बंगाल को गुजरात बना रहे हैं। हम बोलते हैं कि गुजरात तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि बंगाल के नौजवान को अगर नौकरी करनी है तो कोलकाता छोड़ कर या तो गुजरात जाना है या फिर महाराष्ट्र जाना है। तो हम बोलते हैं कि वहां क्यों जाना है, यहीं गुजरात बना देते हैं, यहीं नौकरी करो, बाहर क्यों जाना है? लेकिन इससे भी उनको विरोध है।

सर, इस परिस्थिति में हमको दो-चार बातें ही बंगाल के बारे में बोलनी थीं। क्योंकि जो बंगाल स्वतंत्रता के बाद से ही आगे चल रहा था, अब उसको पीछे ले जाने की साज़िश चल रही है। बंगाल को अलग करने की साज़िश चल रही है। यहां माननीय प्रधान मंत्री मुख्य मंत्रियों को बुलाते हैं, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री नहीं आते हैं। अर्थमंत्रियों को बुलाते हैं तो हमारे राज्य के अर्थ मंत्री नहीं आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, तो वे नहीं आते हैं।

सर, जीएसटी का विराध सबसे ज्यादा वहां होता है। लेकिन संयोग से सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलता है। वैस्ट बंगाल गवर्मेंट को सबसे ज्यादा लाभ जीएसटी का मिला है। लेकिन विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी ऐसी राजनीति है। अब उनका यह भेद भी खत्म हो गया है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, क्योंकि दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए भगवान अच्छा करे, समय पर दिमाग ठीक हो। बंगाल की हालत, रक्षा के लिए आपको आमंत्रण है, आप आइए, लोगों को सिखाइए, क्योंकि वहां पर परिवर्तन होना चाहिए। बंगाल इस प्रकार नहीं जी सकता है। हम

बंगाल को वह बंगाल बनाना चाहते हैं, जो देश का नेतृत्व करे, दुनिया का नेतृत्व करे। इसीलिए हम यहां हैं, लोगों ने हमको भेजा है।

महोदय, आपने हमको समय दिया है और हमने अपनी बात रखी। सबको धन्यवाद। सदन को धन्यवाद। भारत माता की जय।

(इति)

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):**

---

* Laid on the Table

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): We are fortunate that we have inherited the legacy of such remarkable patriots. They left us not only with a free India, but also left us with unfinished tasks for the development of our society.

Every breath in our collective life as a nation is a tribute to our freedom fighters and a commitment to accomplish whatever is still unaccomplished.

The Government needs to check the growing unemployment and jobless growth phenomenon in the country, loss of more jobs in the country as a consequence of reckless economic mismanagement done due to reckless action of Government in the form of demonetization and GST.

The Government have to take special measures to check malnutrition among women and children. You have to increase the wages of Anganwadi Workers and helpers as well as ASHA workers so that the benefit reaches to the poorest of the poor. The Government didn't mention about the Women Reservation Bill which is long pending. You have to strengthen the hands of farmers by making modern technology available to them free of cost. Singur Andolan established the rights of the farmers over their agricultural land. It was correct and an appropriate step, which will be written in golden letters, since it empowered the farmers' rights over their agricultural land under the leadership of Mamta Banerjee.

---

*Laid on the Table

There should be strict action taken by the Central Government to tackle the alleged growing intolerance manifesting in violence and the spread of communal polarization in the country. I oppose the Motion of Thanks on the President's Address.

(ends)

1322 hours

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Sir. I would like to thank my YSR Congress Party for giving me an opportunity to speak on this subject. I thank my Ongole people for sending me to this august House as a Member of the 17th Lok Sabha.

Firstly, I would like to congratulate BJP and its allies headed by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji for a victorious comeback. Sir, it is appropriate for me to put before you the hard work done by my young leader, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Ji. He took *padyatra,* walked a long distance of 3,448 kilometres. He went to every nook and corner of all the villages, understood the problems of the people there and also came up with nine Navratna welfare schemes. In Telugu, there is one saying that "*nadichinavadu nashtapodu*". It means that the people who have walked during *padyatra* will never lose. The people of Andhra Pradesh have rewarded him also by giving him a landslide victory of 22 Parliament seats out of 25 seats and 151 Assembly seats out of 175 seats. That is the credit of my leader, Shri Jagan Mohan Reddy Garu. He has got a lot to do also.

Now, I will come to the main topic, that is, the Motion of Thanks on the President's Address. This Government, headed by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, is for the farmers. Sir, I am talking especially for my Parliamentary constituency. Tobacco is grown there in large quantity. About 40 per cent of the country's tobacco is grown in my Parliamentary constituency.

The farmers are now facing a lot of problems. They demand a better price. They are expecting Rs. 100, but the market is giving them Rs. 80. I would request our hon. Minister of Commerce and Industry to intervene in this matter and to see that this thing is done through Tobacco Board.

Now, I come to the livestock development. Ongole bull is very famous. It is known throughout the world. The livestock has to be developed. I request the concerned hon. Minister to look into this matter.

Sir, infrastructure means waterways. Andhra Pradesh has got a long coastline of 1073 kilometres. You can develop a lot of ports. About 50 years back, centrally-funded Visakhapatnam major port was created. As per the Reorganisation Act, the construction of Dugarajapatnam Port is proposed, but there is no progress. Also, the foundation stone for Ramayapatnam Port in Prakasam District has already been laid. My request to you is that the work on this project should be taken up expeditiously.

The work regarding modernisation of Buckingham Canal, that starts from Kakinada to Chennai, which is about 971 kilometres, is also pending.

(1325/RC/GG)

The Visakhapatnam-Chennai corridor project, which is on the sea side, is also pending. Then State roads have to be developed into national highways. The conversion particularly from Amravati to Anantapur, which was decided in the AP Reorganisation Act, has to be implemented.

Regarding Railways, Visakhapatnam Zone project is still pending and nothing has been said about it. Nadikudi-Srikalahasti is the biggest Railway

project for Andhra Pradesh. It is also going at a slow pace. Regarding irrigation, Polavaram project is the lifeline for Andhra Pradesh. Sufficient funds are not being allotted by the Centre even though it is a national project. It has to be taken care of.

I would request the Government to take up the Veligonda project in Prakasam district as a national project. Andhra Pradesh has got a lot of natural resources like natural gas, granite, uranium and gold is also there. Therefore, the Government of India has to seriously think about developing them.

We have also got a lot of tourism facilities. We have 1073 kilometres of coast line. So, these beaches can be developed with the Government funds. In Andhra Pradesh, our youths are in an aggressive mood. They have studied software technology. They have gone to work in other countries like the USA and the UK. They have to be supported.

Our State is in dire need of funds. Our young Chief Minister is facing a lot of problems with a negative cash balance of Rs.35000 crore. The previous Government did over-spend and had not cleared the bills also. So, the Government of India has to come forward and try to help our young Chief Minister. This is our request.

Then, there is a long pending demand of providing Special Category status to Andhra Pradesh. Our Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu is doing padayatras. A lot of people have asked him *"Jagan anna, maaku pratyeka hoda ippinchandi. Industries vaste maa pillalu bagupadataru."* That

means, the Special Category status has to be given immediately to Andhra Pradesh so that our young people could earn their livelihood and could live peacefully.

Then Central Government is implementing a lot of schemes to develop the country. I would request that Andhra Pradesh should also be considered for these schemes. Our young Chief Minister wants to do many things. A lot of educational institutions can be developed there. More seats should be allotted to the educational institutions in our State. In medical colleges, the number of seats is very less. I would request you to increase the number of these seats.

We are all with you. *Sabka Sath, Sabka Vikas aur Sabka Viswas* is the mantra of our Government. If you can also take care of the requirements of Andhra Pradesh, then the people of Andhra Pradesh will always be thankful to you.

(ends)

***श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली):**

---

* Laid on the Table

1329 hours

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for this opportunity that you have given me to speak in support of the President's Address.

Sir, as I stand here, I am overwhelmed with the feeling of gratitude that my Prime Minister gave me an opportunity to come to this temple of democracy, sit here and speak here in this hallowed hall where the great Sardar Patels, the Baba Saheb Ambedkars, the K.M. Munshis, the Chakravarty Rajagopalacharis and the Atal Behari Vajpayees stood, spoke and crafted the country's present, future and history.

(1330/SNB/KN)

Sir, the very fact that a 28 years old young man, hailing from a middle-class family can even dream of coming into an institution as great as this shows how the Bhartiya Janata Party under the leadership of the great Prime Minister Shri Narendra Modi has radically transformed the country's electorate, country's polity in such a manner that our country's democracy is only being strengthened every single day.

Sir, I remember in 2014, as a volunteer of the hon. Prime Minister in Bengaluru and in other parts of the State, I was distributing pamphlets, writing slogans and making speeches in small gatherings in support of the hon. Prime Minister. I never dreamt that in five years' time, I will have the opportunity to be speaking in this great institution because for a very long time, politics was more of a family business and the country's political institutions and the

country's political geography, more or less, seemed to be under the control of a few oligarchs and more and more, it seemed like a kleptocracy. Today if a *chaiwallah* has risen to the post of the country's Prime Minister, not for once but for two times, it only shows that the country's democracy is being strengthened and along with him he is bringing people like us as faces of new India; as faces of young India to come and speak on the aspirations of the country.

Sir, this victory is historic in so many counts. It is not only the result of the workers of the Bhartiya Janata Party but the common Indians fought this election. The hon. Prime Minister, many a times, has spoken that this election was an election where the common Indians fought. He fought this election because he wanted to see a better India. In his mind and in his heart, he had hopes that his tomorrow will be better than what his yesterday was -- from the autorickshaw driver who plastered NAMO again on his autorickshaw to the IT savvy guy in Bengaluru who wore a t-shirt of NAMO again to those NRIs sitting in different time zones woke up and tweeted their support for the hon. Prime Minister. The common Indians felt that the victory of the hon. Prime Minister is a victory for a new India which is why they all came together.

We speak of different quotients in this country. We speak about intelligent quotient of a person; we speak about emotional quotient of a person. I think, from 2014 to 2019 one of the greatest transformations that have taken place in the country is that the political quotient of the electorate of this country has tremendously increased. We are today a much more an enlightened

society and a great more matured and an enlightened democracy and this is the result of the Opposition's fake news, the Opposition's untruth and the Opposition's propaganda and it all fell flat because the young people of today did not believe in the narrative that was crafted by a handful of editors or anybody sitting in the Lutyens Club in Delhi, but they speak, write and edit what they want to do on their own because today social media has given a democratic platform where I can speak what I want unhindered by the fact that a few people with prejudices can stop me. This has also contributed to the rise in the country's political narrative back among the young Indians.

Sir, from 2014-19, we have achieved a lot of things. Some great transformations took place. As a young Indian who read in his social sciences text book that we are a developing country for the last 60 years, there was a sense of frustration, a sense of anger when he found that other countries, much smaller in size than ours, with much less population than us were galloping faster and developing. Why was it that our country was not progressing in the same pace?

(1335/RU/CS)

If Indians could prosper outside of India and if they could do well for themselves and their families in countries, say, UK and US and other parts of the world, why was it that Indians were not performing well in India? These questions troubled all of us. But from 2014 to 2019, howsoever much the Opposition may oppose us, the foundation for building a new India started – an India, which respects performance over pedigree, an India which votes and

elects its leaders on the basis of what they deliver and not on the basis of what surnames they have next to their names. A new India rose in 2014 where the country's economy got such major changes and structural reforms so much so that honesty, transparency, integrity in our professional lives were respected, were encouraged and the country's economy rose through the effects of demonetisation, through the effect of GST and through the effect of IBC.

I must fondly, with great reverence and gratitude, remember the way Shri Arun Jaitley has piloted and pivoted the GST which is such a complicated constitutional and financial structure. The country will be ever indebted to him.

Today, India's economy is more formal, more organised, transparent and clean. It is not just that. In the last five years, the kind of achievements we made are excellent, whether it was in Foreign Policy, in international relations, in building ties with other countries, or whether it was in the field of ensuring that the most necessary public services reach the last man in the line. Truly, this country saw that the Indian Government, if it wants to touch the common man, can actually touch the common man's life.

Sir, Babasaheb Ambedkar had once prophetically said one point, on the 25th November, 1949, while introducing the Constitution of this country in this very hallowed House. He was asked as to what he thought about the Constitution and whether it was a good Constitution or a bad Constitution.

This is what Dr. Ambedkar said:

> "I feel, however good the Constitution may be, it is sure to turn out bad because the people who are called to work on it happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to

be good, if those who are called to work it happen to be a good lot."

Sir, nothing has changed from 2014 to 2019. It is the very same Constitution, the very same laws, the very same officers, the very same workers and the very same loopholes in the organisations. But what has changed was the change of the leader. A good leader became the Prime Minister and therefore, the country's fortunes have changed.

For a very long time, our economy was in shambles. Ten years under the UPA Government was a decade of decay, a decade of lost opportunities, a decade where young India felt that the world was zipping past them but we just stood like mute spectators. But, Sir, we have made a massive turnaround in the last five years. It is a turnaround that inspires all of us to put in one extra hour of work because our Prime Minister tirelessly works 20 hours a day and we, as young Indians, are inspired by him.

For a very long time, the Lutyens economists of this country very derisively labelled the 2.5 to 3 per cent economic growth that the country achieved under Jawaharlal Nehru as the Hindu rate of growth. Sir, I beg to disagree with this because what we saw then was a myopic confused economic policies and action, but what we are witnessing today is an India, under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, which is galloping as the world's fastest economy. Today, we are witnessing the real Hindu rate of growth in this country.

Sir, the other most important thing that we witnessed was that a culturally repressed country, which could not wear its identity up its sleeve and proudly say that we belong to a civilisation as great as ours, and when a young Indian in school was made to cringe and feel apologetic that he belonged to a great Hindu faith, has changed in the last five years.

(1340/NKL/RV)

That, I think, is one of the irreversible changes which is beyond the confines of Indian polity.

Today, Sir, what the great Atal Bihari Vajpayee*ji* had given the poetic expression – 'हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय' – has found to be a socio-political expression under the Prime-ministership of Shri Narendra Modi. Whether it is the *Kumbh Mela* which attracts millions and millions of people from around the world or the Prime Minister, proudly doing the Ganga Arti on the banks of the Varanasi, whether it is the meditation in Kedarnath or the Yoga Day which is celebrated by hundreds of countries, including the Islamic countries in the world, we feel proud that we belong to a Hindu civilisation as great as ours.

Sir, the people of this country gave us a very big mandate in 2014. They gave a big mandate to the Prime Minister because they wanted him to do bold things. In 2019, they have given us a bigger mandate because they want us to do bolder things in 2019, and the next five years will witness the rise of a new India.

Sir, in summation, I want to say as to what this new India will look like. The hon. *Rashtrapati's* Address outlines as to how the new India will look like. A 'New India', Sir, would mean that each common Indian, the poor man on the street and the last proverbial man in the line – he will feel that he is a part of the national mainstream and no one is left out. '*Sabka Saath, Sabka Vikas'* is not merely a slogan. The common Indian women in the village also got the benefit of *Ujjwala Yojana* at her doorstep, as did the young start-up in Bangalore received his start-up funding. Every single person was touched by the Modi Government. This will continue in an unprecedented fashion in the next five years.

Sir, in the President's Motion, a great stress has been laid on education. As a young Indian, Sir, I must thank the Narendra Modi Government for having come up with a spectacular education policy. The Draft National Education Policy, 2019 which is out for discussion and debate, in my personal opinion, will promise a route and branch reform of the Indian Education system. A young Indian today takes loans to the tune of lakhs of Rupees. He mortgages his family property because he wants to go for studies as India's educational infrastructure is dysfunctional. I will conclude in a few minutes, Sir. The other thing that really gives me a lot of hope is that for the first time, our country's Prime Minister and the Government is speaking the language of young India. It is speaking of starting 50,000 start-ups, and someone coming from Bangalore, which is the start-up capital of India, I must congratulate the Prime Minister for taking this initiative of starting 50,000 start-ups.

Sir, start-ups means disruption. Start-ups means new ideas. Start-ups are the new India's face. Along with the Birlas, the Godrejs, the Ambanis and the Tatas of yesterday, the new India's Oyo, the Swiggy, the Zomato, the Flipkart and the Cult – all of them will join them. This is the rise of a new India.

Lastly, Sir, there is just one thing that I would want to bring to your notice. I have heard the Opposition. In all humility at my command, I must say that I do not think that they have learnt their lessons. Yesterday, I heard the floor Leader of the Lok Sabha from the Congress Party calling my Prime Minister – calling this country's Prime Minister – in the most fowl and unparliamentary language. During the whole of the campaign, the Prime Minster was subjected to such a grave personal attack, and the people of the country taught the Opposition a lesson. I must warn all of them. If they still have not learnt their lessons, in the next Lok Sabha, starting from this seat to that seat – the whole of the 543 seats – will be occupied by the Prime Minister Narendra Modi's Bhartiya Janata Party MPs. See the kind of arrogance and the kind of a sense of entitlement! Even now, they are blaming the EVMs.

(1345/KSP/MY)

Sir, what baffles me is, after the elections, every single VVPAT was counter-checked with the electoral ballot, - I must say that I am proud to be an Indian because the Election Commission in this country conducts elections in a free and fair manner which is an example for the rest of the world to follow - and not a single VVPAT mismatched. But this still continues.

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, I will conclude in two minutes.

Sir, I read a newspaper report today that the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha yesterday gave the Bharatiya Janata Party and the Prime Minister a lecture on morality. If there is anybody who is the least qualified to speak and give us a lecture on morality today, it is the Congress Party. The President of the Congress Party as well as his mother are out on bail and they give us a lecture on propriety, on financial propriety! Azadji quoted the example of Jawaharlal Nehru that he did not go in support of campaigning of a particular Congress candidate because he had the perception of being corrupt. But I must remind him of history and historical lessons that the very same Prime Minister Jawaharlal Nehru had a V.K. Menon of the famed Jeep Scam sitting right beside him in his Cabinet. This is the history; this is the reality of the Congress Party.

The reason why the Congress Party does not want the rise of a New India is because in the New India they cannot make their scams; in the New India, people respect you for your work, for your merit and your talent, not because you have a fancy surname that your great grandfather had given you and in the New India, people respect the fact that you work hard, you work 20 hours a day for your people. This is the rise of a New India which the Congress Party cannot digest.

Sir, nearly 50 per cent of this House today has first time Members of Parliament. On behalf of all of them, I request all the seniors who are present

here to guide us, to mentor us and to teach us as to how we can all become effective parliamentarians. We have come here with a lot of idealism. We all want to approach the old problems with a fresh set of eyes and we want to contribute our best in the service of the *Bharat Mata*.

Lastly, I want to bring to your notice the lamentable, pitiable state in which my State today is. I will be failing in my duty if I do not do that. While the whole of the country is making tremendous progress, my State Karnataka is lagging behind. I will not take more time, but kindly permit me, because the people from there have sent me to speak about their travails and tribulations.

Sir, we, Kannadigas, have had a great history of political administrators. From the days of Hakka, Bukka, Krishnadevaraya of the Vijayanagara Empire, from the days of the great Kempe Gowda of Bengaluru, from the days of the Nalvadi Krishnaraja Wodeyars of Mysuru which my brother represents today, to Sir M. Visvesvaraya, Karnataka had many great political leaders and administrators who led this State forward. But today, under the most corrupt, most insensitive and most apathetic State Government, we are facing backwardness. While the country is progressing, we are lagging behind.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, I will just take one more minute and I will conclude.Sir, I want my State to progress. Bangalore today is facing the worst of traffic jams and it is the city which is moving at the slowest pace. From the thousands of crore plus IMA Scam where more than 10,000 FIRs have been registered against the kingpin to the new scams that are

tumbling out of the cupboards of the Government every single day, we are witnessing the most corrupt Government. From this place, I want to assure the people of Karnataka.

(1350/SRG/CP)

*Respected Members, it seems that a new government with new hopes would emerge in Karnataka. Our aspiration, dreams and innovative ideas would be realised with the new government in Karnataka. All of us should make efforts to see that the new government comes to power. The responsibility of ensuring new a government in Karnataka lies on the youth.

I want to assure all of them. I want to thank all of you for giving me this opportunity to speak. I would want to conclude with just one saying that millions and millions of Sangh Swayamsevaks of this country have spoken about " परम् वैभवम् नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्।"

With these words, I would like to conclude.

(ends)

---

*Original in Kannada.

*SHRIMATI SHARDABEN ANILBHAI PATEL (MEHSANA): I support the Motion of Thanks for Hon'ble President of India. I support all the efforts in development in Defence, HRD, Agriculture, Women & Child Empowerment, External Affairs Policies.

All the development will make India much more stronger.

(ends)

---

*Laid on the Table.

*SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): I welcome Honourable President's announcement extending PM KISAN Program to all farmers irrespective of the land holding.

I humbly request the issue of landless labourers who depend upon the land for their livelihood may be included in this Address.

The Government should come out with a plan to introduce a program like Universal Minimum Income to help crores of landless labourers who are also in Below Poverty Line (BPL).

---

*Laid on the Table

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri A.Ganeshmurthi in Tamil,
please see the Supplement. (PP 398 to 398…..)}

*Laid on the Table

1351 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर, कल हमारे मंत्री श्री प्रताप सारंगी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरूआत की, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कल सारंगी जी ने जिस तरह विपक्ष को आड़े हाथों लिया, उसे पूरा देश देख रहा था। इनके पास जवाब देने की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि देश के अंदर 50-60 साल इनका शासन रहा है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर 5 साल मोदी जी की सरकार क्या करेगी, उसका विजन रखा गया। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के अंदर प्रधान मंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति, जो गाँव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठा है, गरीब व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की। मैं तीन बार का विधायक हूँ और पहली बार लोक सभा के अंदर आया हूँ। उन तमाम जगहों पर जहाँ चार-चार किलोमीटर तक बिजली की लाइन ले जाने के लिए पैसा चाहिए था, हम विधायक निधि से पैसा नहीं दे सकते थे, राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। प्रधान मंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना थी, उससे गाँव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सुविधा मिली। प्रधान मंत्री जी ने एक आह्वान किया कि गैस की सब्सिडी अपने आप खत्म कीजिए। वह एक जन-आन्दोलन बन गया और करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी अपने आप ही खत्म कर दी। यह बहुत बड़ा जन-आन्दोलन था। प्रधान मंत्री जी एक करिश्माई नेतृत्व के धनी हैं।

उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की। स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांति के रूप में देश के अंदर आगे आया। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाएँ यहाँ बताईं। सरकार ने पहले भी 5 साल, जिसके बलबूते मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उसे तो वे पूरा करेंगे ही। इसमें 109 बिंदुओं के माध्यम से एक विजन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं, करोड़ों युवा मतदाताओं ने प्रचण्ड बहुमत के साथ मोदी जी को प्रधान मंत्री के पद पर सुशोभित किया। पहली बार हमारे लिए खुशी की बात है कि 78 महिला सांसद, हमारी बहनें जीत कर लोक सभा के अंदर आईं, देश के अलग-अलग इलाकों से आईं।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास का पहले नारा था। उन्होंने एक बात और कही है – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब संयुक्त अधिवेशन था, जब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको संयुक्त, सेंट्रल हॉल के अंदर नेता चुना। तब उन्होंने कहा था कि इस देश का मुसलमान भी सुरक्षित है। मुसलमानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने आपको डरा कर वोट लिए, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। इससे बड़ा हृदय किसी का हो नहीं सकता।

महोदय, पांच साल नए आयाम इस सरकार ने विकास के दिए। 17 तारीख से लोक सभा की पहली बैठक थी, शपथ ग्रहण था। 16 तारीख को प्रधान मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के अंदर देश की पार्टियों के वरिष्ठ नेता आए थे, फिर एनडीए की बैठक रखी। मैंने उनके काम करने की शैली देखी कि एक प्रधान मंत्री इतना काम कैसे कर सकते हैं। पहले हम टेलीविजन पर देखते थे, सुनते थे। वे उन बैठकों के अंदर तीन-चार घंटे बैठे और दोबारा 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक उन्होंने ली। देश के ज्वलंत मुद्दे, वन नेशन, वन इलेक्शन। इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। अन्य पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया कि चुनाव एक साथ होने चाहिए। यह सबकी इच्छा थी। प्रधान मंत्री जी ने एक नई पहल की शुरुआत की है।

दूसरा, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़े। उनकी इच्छा थी कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो नए एमपी जीत कर आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। नए मेंबर आफ पार्लियामेंट ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। हम सबको वहां पर उन्होंने आश्वस्त किया था।

(1355/SK/KKD)

न्यू इंडिया की बात चली, मैंने कल और आज कई वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने। मैं तो पहले राजस्थान की राजनीति में था, पहली बार दिल्ली आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि विपक्ष की तरफ से अच्छे सुझाव आए। यहां जो बहस होती है, उससे ही कुछ निकलकर आता है कि आम आदमी का भला कैसे हो। हमने कई सदस्यों की बात सुनी, हमारी एक बहन बहुत एग्रेसिव हो रही थी, उन्होंने

बहुत ज्यादा इंगलिश में बोला। जो इंगलिश कम जानते हैं उनकी समझ में कम बात आई लेकिन सोनिया जी की समझ में पूरी बात आ गई, उनको बात वहीं पहुंचानी थी।

देश गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है, निश्चित रूप से गांधी जी का अहिंसा के साथ एक और संदेश था कि पर्यावरण को बचाया जाए। अगर पर्यावरण नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जंगलों में बिना कारण आग लग जाती है, बरसात का सीजन नहीं होता है लेकिन बरसात हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। किसी का घर बाढ़ में बह जाता है, किसी का घर जल जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि प्राकृतिक आपदा के जो पहले नियम थे, केंद्र से जो पैसे जाते हैं, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदा की राशि जो केंद्र सरकार से राज्यों को मिलती है, ज्यादा होनी चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है।

मेरी अगली मांग पेयजल के लिए है। डार्क जोन के इलाकों में पानी गहरा होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। पीने के पानी की स्थिति यह है कि पूरे देश में अगर कोई क्रांति होगी तो पानी के ऊपर होगी। राजस्थान में पीने और सिंचाई का पानी पंजाब से गंगा नगर और हनुमानगढ़ होते हुए आता है। पंजाब से एक ट्रेन आती है, जिसे कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लुधियाना से सैकड़ों फैक्ट्रियों का गंदा पानी इंदिरा गांधी कैनाल में छोड़ दिया जाता है, यह पानी राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर होते हुए आता है। केंद्र सरकार को इसमें दखल देकर पंजाब की सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि फैक्ट्रियों का गंदा रासायनिक पानी इसमें न छोड़े नहीं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इस देश में और ज्यादा फैलेगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत को एक आंदोलन का रूप दिया, उसी तरह पीने के पानी के साथ सिंचाई के साधन देश में कैसे बढ़ें, राजस्थान में कैसे बढ़ें, इसके बारे में सोचना चाहिए।

जब हम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की रिपोर्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि भूजल की स्थिति गिर रही है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को

धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया गया। इसके कैबिनेट मंत्री राजस्थान से हमारे भाई को बनाया, इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के पैरा 23 में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कही है। देश के पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो, यह देखना चाहिए क्योंकि ये देश की तरक्की में बहुत बड़ी भागीदारी कर रहे हैं।

मैं यही निवेदन सरकार से करूंगा कि किसानों को बचाना है। आपने किसान सम्मान योजना लागू की है, 6000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में आए, यह आजादी के बाद पहली बार हुआ है। बात तो कांग्रेस के लोग भी करते थे, राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सारा कर्ज माफ कर देंगे, वोट ले लिए। राजस्थान में एक किसान ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में लिखा - मुख्य मंत्री दोषी हैं, मैं मुख्य मंत्री की वजह से मर रहा हूं, इन्होंने कहा कि सारा पैसा माफ कर देंगे इसलिए मैंने बैंक में ऋण जमा नहीं करवाया और बैंक वाले कुर्की करने के लिए आ गए, मैं आत्मसम्मानी हूं इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। हनुमानगढ़ में भी किसान ने इसी तरह आत्महत्या की।

प्रधान मंत्री परंपरागत खेती में मेरी मांग है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 50 प्रतिशत जैविक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इस दिशा में त्वरित गति से ठोस कार्य योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है।

(1400/YSH/RP)

सभापति महोदय, वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, इसके लिए मोदी जी ने पांच साल में बहुत प्रयास किए और आने वाले टाइम में भी करेंगे, ऐसा पूरा देश सोच रहा है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसी भी कोने के अन्दर चले जाएं, वहां लोग छाती ठोककर कहते हैं कि हम भारतीय हैं। भारत का नाम वर्ल्ड में बढ़ाया और महाशक्ति के रूप में उभारा, चाहे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ हो या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो। पहले यह ही पाकिस्तान था, यह ही चाइना था। अभिनंदन को किस तरह एक टेलीफोन पर भारत लेकर आ गए। भारत का मान नरेन्द्र मोदी जी ने बढ़ाया। सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ।

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): Hon. Member, there are so many other Members who want to speak. Your time is already over.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): मेरी मांग यह रहेगी कि आर्मी में जब हमारे जवान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है। अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के जवान जो बदमाशों, आतंकवादियों से, नक्सल प्रभावित इलाकों में शहीद होते हैं तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यह मेरी सरकार की ओर से मांग रहेगी।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान राज्य की बात करूंगा। ऐसे 11 राज्य है, जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इनमें से पांच राज्यों को विशेष दर्जा मिल चुका है। राजस्थान सारे मापदंड पूरा करता है। अरावली की पर्वतमालाएं, भारत-पाकिस्तान की लंबी सीमा, ट्राइबल बेल्ट, थार का रेगिस्तान और चंबल के बीहड़, जिसमें डाकू जगन गुर्जर जैसे लोग भी हैं। मैंने दो दिन पहले मामला उठाया था कि किस तरह वह राजस्थान में वे बदमाशी करते हैं। मेरी मांग है कि पांच राज्यों में राजस्थान भी है जो 11 राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hanuman ji, please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): प्रधान मंत्री से मेरी मांग है कि राजस्थान की लंबित पेयजल परियोजना जो भी केन्द्र के अंदर हैं, चाहे सिंचाई की परियोजना हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर से सिंचित क्षेत्र बढ़े, चाहे नर्मदा जो गुजरात से आ रही है, चाहे यमुना का पानी हो, जल्दी से जल्दी राजस्थान को मिले। हरियाणा और पंजाब भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दे। यह भी मैं दिल्ली की सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे राज्य को, जो भाईचारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का है, वे कायम रहे। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Poonam Maadam.

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): लेकिन जल को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो।

सभापति महोदय, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ …(व्यवधान) 15 लोग मारे गए और 60-70 घायल हो गए। कल भी मैंने इस मामले को उठाने का प्रयास किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और पांच-पांच लाख रुपये की घोषणा करके आ जाते हैं। ऐसा हादसा वर्ष 2008 में हुआ। मेहरानगढ़ के अंदर माताजी के दर्शन करने के लिए 200 से ज्यादा मौते हुई। चोपड़ा आयोग बना और चोपड़ा आयोग ने रिपोर्ट दी कि इसके अंदर दोषी जो नेता थे…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You can conclude now. Madam, you may start your speech.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): जिनको देवी दर्शन कराने की बात थी, उन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर लॉज होनी चाहिए …(व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

…(Interruptions) …(Not recorded)

SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL): *

{For English translation of the speech
Laid by the hon. Member,
Shri A.K.P. Chinraj in Tamil ,
please see the Supplement. (PP ……………… to … ………..……)}

* Laid on the Table

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):

*Laid on the Table

***डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):**

---

* Laid on the Table

1404 hours

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion on the President's Address in the 17th Lok Sabha.

Sir, today, our country stands at an epic moment in the history of Indian politics. The re-election of a political party with absolute majority and an even larger mandate in the era of coalition Governments is a victory that has transcended the borders of caste, religion and dialect.

(1405/RPS/RCP)

ऐसा पहली बार देश के इतिहास में हुआ, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात रखी, हम सभी ने कहीं न कहीं इस बात की अनुभूति भी की कि स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पहली बार इस देश में, इस चुनाव के माध्यम से एक उदाहरण हम सबने देखा कि इस देश के नागरिकों ने रीजन से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, जातिवाद-धर्मवाद से ऊपर उठकर, इस चुनाव मैदान में अपनी जिम्मेदारी सोच-समझकर भाग लिया और उसका परिणाम आज समग्र देश के सामने है। जब जनता चुनाव लड़ती है, तब कैसे परिणाम शक्य कर सकती है, वह परिणाम हम सबने इस देश में देखा। The people of this country have reaffirmed their faith in future in the hands of our hon. Prime Minister, Shri Modi *ji*, an insurmountable faith that has made margins of victory unimaginable. If I were to speak in the words of Benjamin Parker, and I quote: "With great power comes great responsibility". कई लोग इसे बोझ के रूप में देखते हैं, कई लोग यह कहते हैं कि अभी इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो कैसे परफार्म करेंगे, लोगों को कैसे यह सरकार संतोष दे पाएगी। वर्ष 2014 में भी यह बात बार-बार इस देश में हुई, इस सभा में हुई और 2014 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार के कार्य, निष्ठा से, जिम्मेदारी के रूप में, लोगों की आशा-अपेक्षाओं के अनुरूप न्याय देने का कार्य, जिस प्रकार से हमारे प्रधान

मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसी के कारण यह जिम्मेदारी, फिर से, मजबूती से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को समग्र देश के नागरिकों ने दी है।

सर, इस विशाल जनादेश को हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करके, और भी ज्यादा कार्यशीलता और निष्ठा से इस देश के हरेक नागरिक को उनका अधिकार पहुंचे, योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसे लिए हम सभी कटिबद्ध हैं।

सर, यह विक्ट्री केवल भाषणों के माध्यम से मिली हुई विक्ट्री नहीं है, केवल कागजी योजनाओं से मिली हुई विक्ट्री नहीं है। उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना, उनको लोगों तक पहुंचाना और प्रॉपर मैकेनिज्म तथा सतत मॉनीटरिंग के माध्यम से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार इस देश में यह शक्य किया है कि जो सच्चे अर्थ में लाभार्थी है, उसे उस योजना का लाभ मिले। पहली बार एक मॉनीटरिंग मैकेनिज्म इतनी मजबूती से प्रस्तावित किया गया, जिसके माध्यम से 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' का सूत्र चरितार्थ करने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया। प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए एक मॉनीटरिंग सिस्टम के माध्यम से जन-जन को इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत सफलता से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है।

सर, हमने इस देश में पिछले पांच साल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मुझे लगता है, हर जगह हम सभी देखते हैं, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में यह बदलाव आया है कि लोगों को केन्द्र सरकार के साथ सीधे जोड़ने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने शक्य किया है। यहां पर हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, पहले जब हम अपने क्षेत्र के दौरे पर रहते थे, गांवों में जाते थे, गांव के किसी चौपाल पर जब हम किसी व्यक्ति से बात करते थे, तब वे बातें स्थानिक संस्थाओं से अपेक्षाओं तक सीमित थीं, राज्य सरकारों से अपेक्षाओं तक सीमित थी, बहुत कम ही कोई बात होती थी केन्द्र सरकार को लेकर। आज नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम सबने यह अनुभूति की है कि समग्र देश में, जन-जन तक केन्द्र सरकार की योजनाओं, केन्द्र सरकार के कार्यों और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की चर्चा है।

(1410/RAJ/SMN)

आप किसी भी गांव में जाकर किसी से बात कीजिए, चाहे वह छोटा बच्चा हो, कोई महिला हो या कोई बुजुर्ग हो, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस देश में आपका कोई काम कर सकता है, आप तक आपका अधिकार कोई पहुंचा सकता है, ऐसी आशा किससे है तो मुझे लगता है कि हम सभी को एक ही जवाब मिलेगा। मुझे अवश्य यह जवाब मिला है कि अगर कोई काम कर सकता है, कोई बदलाव ला सकता है, हमारे आशाओं, अपेक्षाओं और अधिकार को हम तक कोई पहुंचा सकता है, तो वह हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं। यह परिणाम इसी कार्य का परिणाम है कि किसी न किसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। वह चाहे सीधा संवाद हो, योजनाएं हों, लोगों तक उनका अधिकार पहुंचाने की बात हो या उनका खुद का दौरा हो। इस देश में कितने लोक सभा संसदीय क्षेत्र और राज्य ऐसे होंगे, जिन्होंने इतिहास में पहली बार अपने प्रधान मंत्री जी को स्वयं देखा होगा। मुझे लगता है कि समग्र देश के सारे संसदीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं, पिछले पांच सालों में सभी विभाग के मंत्री या उनके द्वारा दौरा अवश्य हुआ होगा।

सर, आज विपक्ष हर मंच पर बोल नहीं सकता है, पर यह बात विपक्ष में भी कहीं है कि वे यूपीए की सरकार में जितने काम अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए थे, उससे ज्यादा काम नरेन्द्र भाई की नेतृत्व वाली, एनडीए की सरकार में अपने क्षेत्र में करा पाए हैं। *… (Not recorded)* …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the chair.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): सर, वही एक कारण है। केवल सबका साथ, सबका विकास, एक सूत्र नहीं था।…(व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। जब मैं बोल रही हूं तो आप सुनिए और जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए जो भी आपको बोलना है। अभी मत बोलिए।…(व्यवधान)

यह जो वोट है, परिणाम है, पहली बार सकारात्मक काम, सकारात्मक विचार और जन-जागरूकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण और सतत कार्यशील प्रधान मंत्री और उनके साथ जुड़ी हुई समग्र

सरकार का यह परिणाम है। पहली बार इस देश के लोगों ने परफॉर्मेंस को वोट दिया है, इस देश के लोगों ने कार्यशीलता को वोट दिया है। पहली बार, इस देश में एक पॉजिटिव मैनडेट के साथ स्पष्ट बहुमत से फिर से नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, लोगों को जोड़ने का कार्य हो, अलग-अलग अभियान में भी जन भागीदारी का काम हो, नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में पिछले पांच सालों में हमने ऐसे बहुत से अभियान देखे हैं, जो बहुत सफल हुए हैं, क्योंकि उसमें जनभागीदारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनमें स्वच्छता अभियान, हम देश को महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, भारत को विश्व फलक पर ले जाने की बात करते हैं, पर प्राथमिक सुविधा, जैसे बहनों और विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट्स ब्लॉक्स भी हम प्रोवाइड नहीं करा पाए। हम विदेश जाते थे और विदेशों की स्वच्छता के बारे में तारीफ करते थे, लेकिन हमारे द्वारा यहां स्वच्छता की दिशा में कुछ भी नहीं होता था। पहली बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने समग्र देश को, मुझे लगता है कि शास्त्री जी के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी दूसरे लीडर हैं, जो देश को आह्वान करते हैं, अगर देश को कोई संदेश देते हैं तो उस संदेश के साथ, उस आह्वान के साथ समग्र देश उनके साथ जुड़ता है।

सर, वह स्वच्छता अभियान हो, अन्य सरकारी योजनाओं की बात हो या उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी देने की बात हो, पूरा देश अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर देश हित की भावना के लिए, देश की प्रगति के लिए इस अभियान में जुड़ा।

(1415/IND/MMN)

आज हम देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान एक लोक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। जिस भी कार्यक्रम में हम जाते हैं, उस कार्यक्रम में अगर कोई मुख्य थीम है तो वह स्वच्छता अभियान है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): Please conclude.

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Sir, I have just started my speech. जन-जागरुकता का जो काम हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री ने किया

है, जो जन-भागीदारी का कार्य हमारे प्रधान मंत्री श्री ने किया है, भूतकाल में ऐसी जन-भागीदारी हमारे देश ने कभी नहीं देखी। पिछले पांच साल में इस देश की जनता को बहुत बड़ी रिस्पाइट मिली है। पहले एक ईरा था, जहां headlines of the newspapers were decided by the magnitude of the corruption scandals. पहली बार इस देश ने यह बदलाव देखा कि हमारे देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ और जो पहले चुनावी मुद्दे भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई के होते थे, अब पहली बार विपक्ष के पास सरकार के विरुद्ध कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। विपक्ष के पास ठोस मुद्दों का अभाव था। विपक्ष ने इमेजनरी मुद्दों के साथ प्रचार किया, बनाए हुए मुद्दों के साथ प्रचार किया। भूतकाल के चुनाव जो पॉलिसी पैरालिसिस, भ्रष्टचार और महंगाई आदि मुद्दों पर लड़े जाते थे, आज वह चुनाव गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ा गया।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have already made your points.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बातें कहना चाहती हूं, then I will conclude. यदि मैं अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बोलूंगी, तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं करूंगी। पहली बार देश ने एक बोल्ड लीडरशिप देखी, एक डिसीजन मेकर लीडर इस देश को मिला, जिन्होंने किसी भी कंज़रवेटिव निर्णय से ऊपर उठकर, किसी भी पापुलेस्ट मैज़र से ऊपर देश हित को रखा। पहले से देश में बहुत चीजें पैंडिंग थीं। शायद बहुत लोग करना भी चाहते होंगे, लेकिन सबको चुनाव बीच में दिखता था। मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिला, जिन्होंने कभी भी चुनाव को ध्यान में नहीं रखा और देश हित को प्राथमिकता देकर, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जहां देश की बात आई, वहां मोदी जी ने कंज़रवेटिव निर्णय से ऊपर उठकर, पापुलेस्ट निर्णय से ऊपर उठकर स्ट्रांग निर्णय लिए। पहले देश में जहां जनप्रतिनिधि की व्याख्या यह होती थी कि पहले खुद का विकास, खुद की प्रगति, फिर पार्टी की प्रगति और उसके बाद देश आता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सूत्र नरेन्द्र भाई के रूप में चरितार्थ हुआ। 'Nation first, Party

second and self, last'. इस सूत्र को चरितार्थ करने का कार्य हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री ने किया।

HON. CHAIRPERSON: You conclude now.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): महोदय, मैं जामनगर, द्वारका क्षेत्र से चुनकर आती हूं। वह क्षेत्र इस देश का बार्डर एरिया है। बिलकुल वैस्टर्न जोन का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है।

HON. CHAIRPERSON: If you have more things to say, you can lay your speech.

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Sir, I will lay it but I had requested for more time. Sir, I would request you to give more time. I am speaking after a long time.

HON. CHAIRPERSON: There are a number of other speakers also, including from your Party.

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): I have not spoken much. I would request you to give me more time. There are hardly any Members here. Let me speak for some more time.

HON. CHAIRPERSON: No, there are a number of speakers waiting for their chance.

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Sir, my humble request is to give me five minutes more.

HON. CHAIRPERSON: Do you want five minutes more?

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Yes, Sir. I will conclude very quickly. I am going to conclude.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude within two minutes.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): महोदय, It is the last district of our Western Zone. यहां द्वारकाधीश का मंदिर भी है और हमारे चार धाम में से एक धाम का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र की बेटी के रूप में मैं यहां करती हूं। उस क्षेत्र के लोगों ने पिछले पांच साल में यह नहीं सोचा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी हद तक अपग्रेड हो पाएगा। पहले यह माना जाता था कि बिलकुल आखिरी तबके का क्षेत्र है, इसलिए यहां कोई सुविधा की जरूरत नहीं है और यह सोचा जाता था कि यहां कौन जाएगा। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जो आखिरी तबके का क्षेत्र था, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम हुआ। उसे अव्वल क्रम का दर्जा केंद्र सरकार ने माननीय नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में दिया। रोडवेज की बात तो पहले हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंच मार्क होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल रोडवेज को डेवलप किया जाता था और बाकी किसी भी क्षेत्र को प्राधान्य नहीं दिया जाता था। पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज हो, वाटरवेज हो, रेलवे हो सभी को अपग्रेड करने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री श्री ने किया है।

(1420/VB/VR)

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL): Please conclude.

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Sir, I am concluding it in two minutes. I am already concluding it.

HON. CHAIRPERSON: You have already made all the points.

SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): I wanted to speak more, but I request you to give me just two minutes.

HON. CHAIRPERSON: Please make your last point and conclude it.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): सर, पहली बार केन्द्र से इतनी मजबूत चीजें जामनगर-द्वारका क्षेत्र में पहुँची हैं, इसलिए उसके बारे में बोलने का थोड़ा-सा राइट तो बनता है। पहले केन्द्र को इन चीजों को वहाँ तक पहुँचाना ही अशक्य था।

HON. CHAIRPERSON: Please make your last point.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): सर, पहली बार उस क्षेत्र में और समग्र देश में एक होलिस्टिक गोल के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, जिसमें रोडवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़ और एयर पोर्ट्स आदि को अपग्रेड करने का कार्य माननीय नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में हुआ।

मैं किसान की एक ही बात रखना चाहती हूँ। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक….

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions)… (Not recorded)

(इति)

HON. CHAIRPERSON: You can lay your speech on the Table of the House. Now, Shri Prataprao Jadhav ji.

1422 बजे

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिव सेना पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पिछले पाँच साल में सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो अच्छे काम किए, जो अच्छी योजनाएँ सभी तबके के लोगों के लिए लाए, उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में उल्लेख किया।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं, जो बहुत सालों से सूखे की चपेट में आ रहे हैं। सूखे की चपेट में आने की वजह से वहाँ के जो बड़े-बड़े डैम्स हैं, वे भी सूखे हैं। डैम्स सूख रहे हैं और इधर पीने के पानी की भी किल्लत है। हजारों करोड़ रुपये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सूखे से निपटने के लिए खर्च किये जाते हैं। लेकिन जब तक हम इसके लिए कोई अच्छा उपाय नहीं सोचेंगे और उसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक सूखे की तकलीफ दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी।

इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी सरकार में जो जल-शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसके माध्यम से अगर यहाँ पर नदी जोड़ो प्रकल्प बनाया जाए और जिन नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, उस पानी को यदि सूखे डैम्स या नदियों में लाया जाए, तो सूखे का सामना हम कर सकते हैं। पीने के पानी की किल्लत भी कम हो सकती है। इसी प्रकार से, मेरे क्षेत्र की वैनगंगा, नलगंगा और पैनगंगा नदियों को जोड़ने के लिए जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ गई है। उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर वैनगंगा, नलगंगा और पैनगंगा नदी जोड़ प्रकल्प पूरा होता है, तो जो हमारा पिछड़ा हुआ विदर्भ है, उसके छह-सात जिलों के किसानों को और सभी लोगों को पीने के पानी के लिए फायदा हो सकता है।

मेरे से पहले सम्माननीय सांसद प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बोल रही थीं। मैं भी उसी विषय पर बोलूँगा। यह जो फसल बीमा योजना है, इसको बनाते समय इसमें जो भी प्रावधान किये गये, उसकी वजह से किसानों को कम फायदा हो रहा है और बीमा कम्पनियों को ज्यादा फायदा

हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसकी और समीक्षा होनी चाहिए। जो लोग किसानों के नेता हैं, जो किसानों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उन लोगों से सुझाव लेकर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का ज्यादा-से-ज्यादा फायदा किसानों को कैसे मिले, इसके लिए समीक्षा करनी चाहिए।

(1425/PC/SAN)

सभापति महोदय, यह देश कृषि प्रधान देश है। यहां के लगभग 65-70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि देश का किसान बहुत बुरी हालत में गुजारा कर रहा है। किसानों को हर बार किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि बजट का उल्लेख कर लेना चाहिए था। जैसे हमारी सत्ता के पहले रेलवे के लिए बजट आता था, वैसे ही कृषि के लिए अलग बजट लाने की ज़रूरत है।

सभापति महोदय, चुनाव में एनडीए को जो बहुमत हमारे महाराष्ट्र में मिला, उसको लेकर हमने घोषणाएं की थीं कि किसानों के ऊपर जो कर्ज़ा है, उन्हें उससे मुक्ति दिलाई जाएगी, लेकिन उसका भी उल्लेख इस भाषण में नहीं हुआ। इसलिए किसानों को इस कर्ज़ से मुक्ति मिलनी चाहिए। हमारे देश में कॉर्पोरेटेव सैक्टर और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनको जो पेंशन मिलता है, वह बहुत कम मिलता है। उनको 800 रुपये से लेकर 1,000, 1,200 और 1,500 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। उन लोगों का इतने में गुज़ारा नहीं हो सकता। बहुत दिनों से ईपीएस-95 के माध्यम से उन लोगों का आंदोलन चालू है, अनशन चालू है। उन्होंने कहा है कि 7,500 रुपये महीने की कम से कम हमें पेंशन मिलनी चाहिए। जो कर्मचारी ईपीएस-95 में शामिल नहीं है, उन लोगों को भी इस योजना में शामिल कर के उन्हें भी पांच हज़ार रुपये महीने तक की कम से कम पेंशन अपनी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, सन् 2016-17 के बजट में मेरे बुलढाणा लोक सभा क्षेत्र के खामगाव-जालना रेलवे मार्ग को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत 3,000 करोड़ रुपये की मान्यता उस टाइम दी गई थी, लेकिन अभी तक उसका काम कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ। उसको भी गति देने की ज़रूरत है। पिछले 100 सालों से लोगों की इस रेलवे मार्ग की मांग वहां पर चल रही

है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आईएचएसडीपी, जो यूपीए सरकार के टाइम में शुरू हुई थी, बहुत सारे शहरों में लाखों की तादाद में घर बनाए गए। वह योजना उस टाइम नगर परिषद, महानगरपालिका के माध्यम से वहां चलाई गई। उसमें काफी रुपये का भ्रष्टाचार हो गया, जिसके कारण अब लाखों घर खाली पड़े हैं। इधर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जनता से वादा किया है कि वर्ष 2022 तक हम सबको अच्छे-पक्के मकान रहने के लिए देंगे। आईएचएसडीपी के तहत बने हुए जो मकान हैं, उसकी पूरा समीक्षा कर के, उसका ऑडिट कर के जिन लोगों ने उसमें भ्रष्टाचार किया, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। अगर हम क्वॉलिटी कंट्रोल के माध्यम से उनकी इंक्वॉयेरी करें, तो हम लाखों घर आज भी गरीब लोगों को उन शहरों में दे सकते हैं।

सभापति महोदय, एनडीए को इतनी बड़ी तादाद में यहां बहुमत मिला, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राम मंदिर का मुद्दा और अनुच्छेद 370 हटाने की बात कहीं पर नहीं आई। हमें जो इतने सांसद, इतना बड़ा बहुमत मिला, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना चाहिए। इसी मुद्दे पर इतना बहुमत हमें यहां मिला है। यह बात भी हमारी सरकार को आगे करनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है - लोकसंख्या में हो रही वृद्धि। हमारे देश में 'हम दो, हमारे दो' जैसे बहुत सारे कानून आए। यूपीए के टाइम में भी यह नारा लगाया गया। कई लोगों के सख्ती से ऑपरेशन कराये गये, लेकिन महोदय, आज भी इस देश की लोकसंख्या में वृद्धि बढ़ती जा रही है। इसके लिए सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। इधर, हिंदुओं के लिए नारा दिया जाता है - 'हम दो, हमारे दो' उधर, दूसरे लोगों का 'हम पांच, हमारे पच्चीस' का नारा चालू है। इस तरह जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग जनसंख्या बढ़ाकर लोकशाही के माध्यम से सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। अत: सभी लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून - जैसे सबका साथ, सबका विकास - वैसे ही सब के लिए एक कानून इस देश में करने की ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

(इति)

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री सारंगी जी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार रख रहा हूं। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों का दस्तावेज का रोडमैप होता है। श्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ – सबका विकास को मूलमंत्र मानकर आम जनता के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करने का संकल्प दर्शाता है। लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में हमेशा चुनाव एंटी इंकम्बेंसी पर होता था लेकिन पहली बार लोक सभा का चुनाव मोदी जी के पिछले पांच वर्षों के काम पर जनादेश मिला। जनता ने अपने जनादेश में एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्ष 2014 के चुनाव से ज्यादा बहुमत से वर्ष 2019 में भाजपा एवं एनडीए के पक्ष में मतदान करके प्रचंड बहुमत दिया। इससे साफ है कि इस बार का लोक सभा का चुनाव प्रो-कम्बेंसी पर हुआ। इस चुनाव का परिणाम सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संतुष्ट होकर के अपनी मुहर लगाने का काम किया। एक तरफ देश के इस चुनाव में श्री मोदी जी केवल भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं मांग रहे थे बल्कि पूरे देश में इस बार उन्होंने जनता से नये भारत के निर्माण के लिए मतदान करने का आवाह्न किया था। परिणास्वरूप देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इस बार महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान करके पुरुषों के लगभग बराबर पहुंच गईं क्योंकि देश की जनता में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि सरकार हमेशा उनके साथ है तथा सरकार उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा तथा पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि सरकार उनके न्यूनतम आवश्यकताओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार जनता की जनआकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है1 आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए

---

*Laid on the table

कई योजनाओं को लागू किया। किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहली बार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के प्रत्येक किसान परिवार को 6000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में डालने का निर्णय लिया गया। किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृत दी जा चुकी है। पहली बार हमारी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया तथा पहली बार इनके लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी गयी है। देशवासियों को सुरक्षा में स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों के परिवार के लिए नेशनल डिफेंस फंड से बच्चों के स्कॉलरशिप में वृद्धि की गयी है। सरकार ने जल के संकट के समाधान के लिए एक अलग से जन शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने एवं कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार आने वाले वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्ष 2022 तक हमारी सरकार किसानों के एमएसपी को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करेगी। फूड प्रोसैसिंग में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गयी है। फसल बीमा योजना एवं सोइल हेल्थ कार्ड हो या फिर यूरिया की सौ प्रतिशत नीम कोटिंग उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। पहली बार हमारी सरकार ने देश के 112 जनपद जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा में अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ जनपदों को आकांक्षा जनपद के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया है। इसमें सिद्धार्थनगर जनपद का मेरा क्षेत्र है। आज हमारे जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लाखों परिवारों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। आज मेरी सरकार ने सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। सरकार देश के 50 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गयी है। इसके तहत अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। सस्ती दरों की दवा उपलब्ध कराने हेतु 5,300 जन औषिधि केंद्र भी खोले जा चुके हैं। वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण अंचलों में लगभग डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग दो करोड़

नये घर बनाए जाएंगे। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2022 तक देश के सभी लोगों को जिनके पास अभी तक पक्की छत नसीब नहीं हुई है, उनहें आवास देने का लक्ष्य पूर्ण करना है। सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सरकार ने वर्तमान समय में 400 योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के तहत भेजा जा रहा है। सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जब देश 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस समय देश में किसान की आय दोगुनी होगी। हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी। हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी। हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन की सुविधा तथा हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा। सरकार की स्वच्छता मिशन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अन्र्तगत हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सरकार ने हर गरीब की पहुंच में मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसी परिपेक्ष्य में सरकार ने हर तीन संसदीय क्षेत्रों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। आगे चलकर के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। देश का हर गांव सड़क सम्पर्क से जुड़ा हो इसके लिए प्रत्येक गांव को पक्की संड़क से जोड़ने का निर्णय किया गया है। गंगा की धारा अविरल और निर्मल हो, इस दिशा में एक अलग मंत्रालय काम कर रहा है। भविष्य में हमारी सरकार राज्यों के सहयोग से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब हमारा देश आने वाले दिनों में विश्व की तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होगा। भारतीय संसाधनों के बल पर कोई देशवासी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा।

श्रीमन, इसी के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1430/SM/SPS)

1430 hours

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I thank you for allowing me to speak in this august House. I oppose the Motion of Thanks to the Address made by the Hon. President of India to both Houses of Parliament.

Sir, the President’s Address is a policy statement of the Government which has failed miserably in every field. Sir, The Government has failed in terms of growth of economy. The level of unemployment has reached the highest level in the last 45 years. The agricultural production has gone down. The small and marginal farmers are in distress.

Sir, the farmers are not getting the fair price for their produce. The Government could not do anything to help the people in spite of serious drought in many of the States in the country.

Sir, two major economic policy-decisions taken by the Government, GST and Demonetisation, proved to be an utter failure. While the poor farmers and small borrowers are being intimidated and threatened by the banks and financial institutions for recovery of loans, Nirav Modi and Vijay Mallya who have availed bank loans to the tune of tens of thousands of crores are roaming scot-free in foreign countries, leading a luxurious life. Banks are not ready to provide education loans to poor students.

Sir, 95 per cent of natural rubber production in the country is from the State of Kerala, especially from the district of Kottyam. More than 11 lakh small and marginal farmers holding less than 1 hectare of land are major producers of

natural rubber. They are in deep trouble due to the fall in the price of natural rubber.

Sir, the Government has done nothing to improve the conditions of the poor rubber growers. The former UDF Government in Kerala did introduce a noble scheme of Price Stabilisation Fund which was not continued by the LDF Government. The Central Government is not giving any consideration to the farmers.

Sir, according to Dr. M.S. Swaminathan, the father of the Green Revolution in India, farming will be economically feasible only when the farmers get the price for their products at least 50 per cent above their cost of production.

Sir, the cost of production of rubber is around Rs.170 per kg as per the Rubber Board. The farmers are getting only Rs.100 to Rs.120 now. Earlier it went down even to the level of Rs.85 per kg. The Government of Kerala at that time introduced a scheme which gave the farmers Rs.150. The difference between the market price and Rs.150 was deposited in the farmers' bank accounts. Sir, now, I demand that the farmers should be given at least Rs.225 per kg. for which the Central Government has to take steps for price stabilisation.

Sir, Kerala has faced unprecedented floods during August-September, 2018. The farmers are not in a position to repay the bank loans because of the loss they have faced due to the unprecedented floods. Their livelihoods have been lost and they do not have anything now. Most of the farmers have lost even their lands in which they were doing the farming. Today, all the Members of Kerala in the Lok Sabha made a dharna before the Parliament demanding the

Central Government to intervene and not allow the banks to resort to intimidatory steps for recovery of the loans.

Sir, banks are going with recovery measures. The farmers are not in a position to pay off their loans. The Government of Kerala have declared a moratorium. The first declaration was upto 31st July. Now, it has been extended upto 31st December. But the banks and RBI are not ready to accept this. The Central Government has to make the RBI to allow the moratorium upto 31st of December, 2019.

Farmers want their loans to be waived. Even the poor students who have been given loans are being asked to repay immediately. The students are not in a position to repay the loans because they have not been employed so far.

(1435/AK/KDS)

The Government should give ample time to the students to repay the loans, and also waive at least the interest on loans given for educational purposes.

I have to express one more issue here. The second resignation from the hierarchy of the RBI has happened yesterday. The world-renowned Economists, who earlier used to work with the Government of India, have all quit, namely, Shri Urjit Patel, Governor of the RBI; Shri Arvind Panagariya, NITI Aayog Vice-Chairman; Shri Arvind Subramanian, Chief Economic Advisor to the Finance Minister; Shri Surjit Bhalla, Member of the Prime Minister's Economic Advisory Committee; and now Shri Viral Acharya, Deputy-Governor of the RBI. All renowned Economists are not in a position to work with this Government

because the Government's economic policies are not in favour of the poor people of India. Why are all these experts hesitating to work with the Government? This Government is in favour of the rich. The rich people are becoming richer, and the poor people are becoming poorer. Under such conditions, the Government should not follow the present economic policies that they are following right now.

The Government may come out with an audacious plan for genuine disinvestment in the public sector by getting out of businesses like aviation, hotels, telecommunications and monetising many of its other enormous unproductive assets like surplus land, etc.

Sir, as you know, I come from Kottayam, which is known as the land of lakes, literacy and latex. I have already mentioned about latex here. Now, I would like to mention about the lakes also that are there. The hon. President of India has pointed out the steps being taken to clean-up river Ganga and to make it pollution-free. It is also mentioned that the Government will endeavour to clean-up other rivers like Kaveri, Periyar, Narmada, Yamuna, Mahanadi and Godavari. The Vembanad Lake is the longest lake in India and the largest in the State of Kerala. It is rich with various species of flora and fauna. It is included in '*The Ramsar Convention*' as a wetland of international importance. It is a major source of tourist attraction. The world-famous tourist centre 'Kumarakom' is beside this Lake. The Vembanad Lake is facing high-levels of pollution. A recent study has shown that if this rate of pollution continues, then the Vembanad Lake may vanish in 50 years.

HON. CHAIRPERSON (SHRI SURESH KODIKUNNIL) : Hon. Member, please conclude now.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, kindly give me one more minute to speak.

Similarly, the Meenachil River, which flows through the heart of Kottayam District, is a source of drinking water for several lakhs of people. It is also dying due to pollution.

Sir, Changanacherry is also a place near to it. Therefore, I am speaking on behalf of you also.

HON. CHAIRPERSON: It is agreed, but time available with us is also limited.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, the River Pamba that flows through Sabarimala -- the world-famous pilgrim centre and where crores of pilgrims take bath -- is also polluted.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Therefore, I would urge upon the Government of India to take immediate steps to make these important water bodies pollution-free.

Sir, last but not the least, in paragraph number six of his Address, the hon. President of India has mentioned that almost all the professions have been represented in both the Houses of Parliament. I belong to the profession of Chartered Accountancy. There are two Chartered Accountants in this Lok Sabha, and five in the Rajya Sabha.

(1440/UB/SJN)

Ours is a profession which acts as a partner in nation building. Sir, I request that this profession of chartered accountancy be given due consideration.

(ends)

1440 hours

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to present our viewpoint in the Address by the hon. President, Shri Ram Nath Kovind ji.

I stand here to support the Presidential Address. Sir, as I stand here, I bring blessings from the land of *Maa Kamakhya* for each and every one present in this august House today. Currently, we are celebrating an auspicious occasion of Ambubachi and I take this opportunity to extend an invitation on behalf of the Chief Minister of Assam, Shri Sarbananda Sonowal ji to the hon. Members of this august House to make a short visit to *Maa Kamakhya* and seek her blessings.

Mr. Chairman, Sir, we have been talking about national integration when it comes to North-East. We have been hearing this for the last seventy years. We have had a Prime Minister for the last five years whom we can proudly call a 'hands-on Prime Minister'. Why hands-on? It is because he has more knowledge on issues related to Assam and the North-East than the briefing we do. Ever since he has become the Prime Minister, as per the records available, he has made eighteen trips to Guwahati and the entire North-East and during those trips, he has made around forty-eight public addresses over the last five years, other than the Government or the official programmes which were allocated by the Prime Minister's Office.

The hon. Prime Minister today knows what is going on in and around of North-East. As I speak, I must express our gratitude to him because it is because

of him that we have Hima Das, an athlete from a remote village in Assam or Rima Das who makes a film which is recognised world over. The celebration is not confined today within the geographical limits of Guwahati or North-East but the whole country erupts in joy.

Mr. Chairman, Sir, for the last few years, when we get up in the morning and switch on our TV and see our hon. Prime Minister putting on an Assamese Gamocha over his shoulders, it gives us an immense sense of pride, not just for the people for Assam but for the entire North-East. He is capable of carrying the entire country on his shoulders.

Mr. Chairman, Sir, we have been talking of national integration but we have not been talking of mental integration. Today, the people of North-East are mentally integrated with the idea of India. When the hon. Prime Minister puts on an Assamese Gamocha or speaks of the new engine, he is not only saying that Guwahati is the gateway of the North-East India but also that Guwahati is the gateway of the entire South-East Asian countries.

We have had an advantaged Assam two years back under the patronage of our hon. Prime Minister. Today, we have business consulates of Bhutan and Bangladesh established in Guwahati. Sir, I would like to draw your attention to the stark differences that have come out because of the fact that we had a Prime Minister for ten years who represented our State but I do not have a record of how many visits he had made to Guwahati or the entire North-East. But, at least, I can talk about my constituency, in Silchar in South Assam, that during those

ten years, between 2004 and 2014, we did not have a single Prime Ministerial visit to my home constituency.

(1445/KMR/GG)

And as I stand here, I can proudly say that my Prime Minister Shri Narendra Modi Ji visited Silchar four times during those five years.

Mr. Chairman, Sir, we must acknowledge the fact that this election has been a transcending election because during this election corruption has not been an issue and price rise has not been an issue. Those had always been issues during the previous elections. In this election, the vote was pro incumbent government and the massive support that we have received across the country including the North-East has given us more responsibility and has made us more humble.

Mr. Chairman, Sir, the world becomes actually a better place if only the teacher practices what he preaches. Since yesterday we have been seeing my friends, hon. Members of the Opposition, speaking on lofty ideals, speaking of various ideas. But this hallowed hall is not for screaming and shouting; this hall is also not for theatrics. If you had practiced what you preach, then you would have been sitting here today and we would have been sitting on the other side. But our Prime Minister, as I said, is a hands-on Prime Minister and he practices what he preaches.

I would like to draw your attention to a few issues pertaining to Assam. You have got a chance for long years, you were there in the State for 15 long years, and you were there at the Centre for ten long years in the recent past, I

am not talking of the previous years. You have got lots of chances to do a lot of good things for the people of the North-East which included the following things that I am going to enumerate. You failed to complete those projects.

These projects include the Second Bridge over Saraighat, the Dhola-Sadia Bridge in Upper Assam, and the Bogibeel road-cum-rail bridge in Upper Assam. Work on gauge conversion project of 213 km Lumding-Silchar railway line started in the year 1996 and for 18 long years you could not complete the project. Gas cracker project at Lepetkata could not be completed. It was only after our Prime Minister took charge in 2014 that this project picked speed and ultimately saw the light of the day.

Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to your notice today that around 50 kms of new track has been laid under the Railways. Today we have connections with Tripura. Today we are having eight Rajdhani trains plying from eastern part of the country to Delhi. In the coming years, maybe within a year or 18 months, we will be connected through railway to the remotest of the States like Manipur and Mizoram. This will be only done under the able guidance of our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji.

1448 hours (Shri Rajendra Agarwal *in the Chair*)

Mr. Chairman, Sir, the new projects that have come up in the North-East need to be mentioned because for five years our Government has worked relentlessly. In addition to the Central Government for the last five years, we have had Sarbananda Sonowal Ji's Government in the State since 2016 summer. We are having five new bridges to be constructed over the mighty river

Brahmaputra. We are having four new national highways to be made of around 160 kms under NHIDCL, which was set up in the year 2014 in July.

Mr. Chairman, Sir, around 12,000 kms of new roads are being laid under the PMGSY scheme. You can well imagine that with 12,000 km roads in the villages, in the remotest villages of Assam, today the villagers of Assam feel connected with the country's mainstream. Other than these roads of 12,000 kms, we are also seeing the completion of 1,069 RCC bridges under the PMGSY scheme.

Mr. Chairman, Sir, the refinery at Numaligarh is coming up. Approximately, Rs.1,100 crore has been sanctioned for the modernisation of Guwahati airport.

(1450/SNT/KN)

Hon. Chairperson, Sir, I can proudly say that the Guwahati Airport today is the 5th busiest airport in the country. The A.I.I.M.S is coming up in Guwahati. The Barauni-Guwahati Gas Pipeline is coming up in the near future. The production of the NRL has been multiplied by three times. It has gone up from 3.0 MMTPA to 9.0 MMTPA. The Indian Agricultural Institute will come up at Gogamukh in the very near future. Today, we are having international flights from Guwahati to Dhaka and Bangkok. We are having our Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport for carrying cargo, produce of the farmers and vegetables, which are going to five different airports all across the world from our Airport.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आप कनक्लूड कीजिए।

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Sir, I would also like to draw your attention to another paragraph where our President has enumerated about the *Jan Dhan Yojana*. Today I must bring on record what has happened in the State of Assam. Before 2014, the reach of the sanitary latrine was 37.9 per cent, today it is 100 per cent. Before 2014, 42 per cent beneficiaries were under the Saubhagya Yojana, now it is 100 per cent. LPG was available to 41 per cent, today it is 92 per cent. Financial inclusion was 45 per cent, today it is 90 per cent.

Sir, this brings to the last part of my topic. If I do not say or speak on this topic, I would be doing dishonour to a lot of families. I stand here proudly and I am having goose bumps now because I carry the aspirations of the displaced persons of the entire north-eastern people.

Sir, my grandfather was a freedom fighter. He served in Indian jails for almost four years of his life in Jorhat Jail and Nagaon Jail. Sir, you have also carried a Committee under your chairmanship. You have done a commendable job for the North-Eastern region. You have recommended the passage of the Citizenship Amendment Bill which was placed and passed in the last Lok Sabha. There are many fears which are being discussed in the Parliament and back there in the State, but I assure you that if this Citizenship Amendment Bill is passed, then whatever atonement that was done during the time of partition, needs to be corrected. We have had our national leaders during the time including Jawahar Lal Nehru*ji* saying that, "if the law is inadequate in this respect, the law needs to be changed and we should protect and give security to the people whose forefathers fought for the freedom of our country."

Last but not the least, hon. Chairperson, Sir, I would reiterate our commitment on the protection of the indigenous people of the entire North-East. As has been laid out in the Assam Accord, we should take care of the cultural, the linguistic and the other issues which are so dear to the people of North-East. Sir, I assure you that the Government will do everything to provide the constitutional safeguards to indigenous people.

This is my last point. We come from a land of Lachit Borphukan. *He said,* **"My uncle is not bigger than my country."* He fought the Mughals 17 times and defeated the Mughals 17 times. He said when he had given a word to his own maternal uncle, his maternal uncle failed to do so and and Lachit Borphukan chopped off the head of his maternal uncle by saying, *"Desotkoi momai dangor nohoi".* It means – Your *mama* cannot be bigger than the country. It should be reminded to those who without any fear today stand with the *tukde tukde* gang and do their theatrics.

Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak.

(ends)

---

* Original in Assamese

***डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर):**

---

* Laid on the Table

***श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक):**

---

* Laid on the Table

1454 hours

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks proposed by Shri Pratap Chandra Sarangi*ji.*

At the outset, I wish to extend my heartfelt gratitude to the hon. President of India who came to the Parliament to address us all a few days back. Hon. Chairperson, Sir, the President's Address consisted of a detailed description of the welfare schemes and programmes which the Government pursued in the past five years and also the achievements it made in the period between 2014 and 2019.

(1455/RK/CS)

I wish to point out some of those achievements which the Government has made in this duration.

Sir, 2.5 crore households have got free electricity connections. More than 2 crore people, who are poor and needy, have got a roof over their heads under the Pradhan Mantri Awas Yojana. Sir, 12 crore women across the country, who did not have access to cleaner fuel, got gas connections under the Ujjwala Yojana of the Government of India. More than 9 crore toilets across the country have been constructed under the Swachh Bharat Mission. And, 38 crore bank accounts have been opened under the Jan Dhan Yojana for the poor and needy of this country. There are 22 crops for which the MSP has been raised to 1.5 times the cost of production. I feel the biggest achievement of this Government has been to give a befitting reply to the terror factories which are running across

the borders of India by means of the surgical strike and the air strike which has been lauded by the nation and which can be seen in terms of the massive mandate that has been given to this Government by the 90 crore people who voted in the 2019 elections.

Hon. Chairman, Sir, it is all encompassing what all the Government has done in these five years. Our hon. Prime Minister has a vision to create a new India and the President's Address talks of it. It talks of how the economy will grow to become a five trillion-dollar economy in the next five years and how India would be contributing to leadership on the global development front.

I am glad the Government has allocated Rs.13,000 crore to treat cattle-related diseases. It is a very good decision. I also congratulate the Government for its decision to carve out a separate Ministry altogether in order to overcome the water crisis in the country. So, Modi Ji has a vision to make a new India and I think the historic mandate which the NDA has got under his leadership, gives him all power to reshape the agenda and future of the country.

However, Sir, I wish to draw the attention of the House towards certain issues which I feel are very relevant for the country. The first such issue being the creation of an All India Judicial Service. I have been talking of this issue off and on in the Parliament at various occasions. I recollect our hon. Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad ji talking about it on the floor of the House. He said that the time has come for us to think about the creation of an All India Judicial Services on a serious note because there are as many as 5,000 vacancies which lie in the district and the subordinate courts which make it even more important

for us to consider the proposal seriously and remove all the roadblocks which fall in the way of realising this proposal.

Even the policy think-tank of the Government, the Niti Aayog has talked about this proposal, says that the examination should be conducted through the UPSC and appointments and recruitments should be made in the lower judiciary. This, Chairman, Sr, would not only Just address the issue of long-pendency and vacancies in the lower judiciary but also will provide representation to the marginalised communities in the Indian judicial system. So, I urge the Government to step up its efforts in order to make this proposal be realised and the creation of All-India judicial services becomes a reality.

The second issue that I wish to raise here relates to the Iron Man of India, the great unifier of nation, Sardar Vallabhbhai Patel, whose tallest statue in the world has been erected by the NDA Government led by Modi Ji as a mark of gratitude. I thank the hon. Prime Minister for this thought and initiative. Perhaps one of the biggest ironies of an independent India is that for a man like Sardar Vallabhbhai Patel, who gave India much more land than it was born with, we do not even have an inch of land to give in order to build his *samadhi* in the national Capital of Delhi. This is an irony of independent India.

So, the question arises as to where does the common man go to pay homage to this great leader. Pandit Jawaharlal Nehru's house has been made into a Museum. Why cannot the same be done for Sardar Vallabhbhai

Patel? He lived at 1, Aurangzeb Road, when he was the Home Minister of India. I would request and urge my Government to take over that house, get back that property and build a National Memorial as a mark of respect for the great leader who will continue to inspire the generations of India.

(1500/PS/RV)

Lastly, I find the hon. President's Address mentioning about the Constitution providing guidance to ensure social justice. Here, I wish to point out that despite the constitutional arrangement of reservation of 15 per cent for the Scheduled Castes, 7.5 per cent for the Scheduled Tribes and 27 per cent for the Other Backward Castes in various posts and services of the Central Government, the representation of these castes and communities has not reached adequate levels. As per the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, as on 1st January, 2017, there are as many as 28,713 backlog vacancies of the SCs, STs and the OBCs in the Central Government. This is a very important issue which relates to the direct interests of the marginalised and the weaker sections of the society -- the SCs, STs and the OBCs. So, I urge the Government to initiate measures for filling up these backlog vacancies by means of a special recruitment drive.

These were the three important issues that I wish to raise. I once again thank the hon. President of India for addressing us. I urge the House to adopt the Motion of Thanks. With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1301 hours

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to address this august House in the opening session of the 17th Lok Sabha. Let me begin by thanking the people of my constituency, Patiala, for giving me the opportunity to represent them here in Parliament. I assure them that I will do my very best to carry their voice to be heard in this august House.

Hon. Chairman, we are indeed blessed to be here at a time when we observe a very historic year. This is the year of 550th Birth Anniversary of our First Guru, Sri Guru Nanak Dev Ji. It is also the year of 150th Birth Anniversary of our Father of the Nation, Mahatma Gandhi Ji and the Centenary of the Jallianwala Bagh and also the 70th year of our Constitution. The importance of these historic events can be underscored by a strong affirmation of the ideals of the Constitution and the vision of our forefathers. I am sure that all of us collectively, irrespective of parties and States that we represent, will strive to strengthen our commitment to the values of our Constitution and in the process, strengthen our democracy.

In his Address to both the Houses, the hon. President of India touched upon many important issues. Some of these have been highlighted by many of the esteemed Members. Allow me to draw your kind attention to some of the issues which, I consider, will impact the people of Punjab whom I represent.

Punjab has always occupied a very special place in the hearts of the people of India. Punjabis have always been at the forefront of everything – be

it giving the nation its much-needed food security or guarding its frontiers. In the State, we witnessed two decades of militancy-related violence and was also the theatre of two wars with Pakistan. In the 1970s and 1980s, we witnessed the Green Revolution which gave great prosperity to our State. But I am sorry to say this. Today, this '*Annadaata'* State, is in a severe crisis. Our groundwater table stands totally depleted and our farmers are in an acute state of debt. The treatment that the Centre has given us is unfair; it has not done much; and there is a need for a total debt waiver scheme for all the farmers. The State Government of Punjab has done its bit by giving some relief because it has very limited resources. I call upon the hon. Prime Minister to do a one-time debt waiver scheme and help us out as the situation is similar with the farmers all over the country.

(1505/RC/MY)

To add insult to injury, the State of Punjab has been burdened with a huge financial debt of Rs. 31,000 crore, which has been imposed on us due to non-reconciliation of the food account. Its is quite ironic that we purchase food for the Government of India and then end up by paying over Rs. 3000 crore every year as interest on this debt. This will probably continue for the next 20 years. So, I call upon the Finance Minister to find an equitable solution to end this.

Punjab is facing a very serious water problem. On the one hand, its irrigation system is old and dilapidated; and it needs urgent upgradation for which I hope the Government of India will clear a project soon. On the other

hand, its water table is declining alarmingly and the reality of Punjab becoming a dessert State is quite real. I call upon the Agriculture Minister to increase the subsidy on underground irrigation pipe scheme and save our precious water resource.

Our State's border areas are very thickly populated unlike other States. The meagre grants given by the Central Government under the Border Area Development Programme are like a small drop of water in the ocean. The Government of India must come forward to assist the State through a special package for development of its border areas. Further, the flight of industry from these areas first due to militancy and later due to special packages given to the neighbouring hill states has seriously compromised the economic health of Punjab.

Let me now turn to some specific issues related to Patiala, my constituency. There has been a long pending proposal to declare Patiala-Sirhind-Morinda road as a National Highway and to four lane it. This road connects many shrines of historical and religious importance - Patiala with Fatehgarh Sahib and further with Chamkaur Sahib. There is a demand to name this highway after Mata Gujri Ji, the mother of Dasam Pitah Sri Guru Gobind Singh Ji. I request the Union Transport and Highways Minister to conclusively approve this project as it has been approved earlier but work was never initiated.

A related issue is, the approval of construction of Ring Road in Patiala as part of the Bharatmala Scheme. I am given to understand that none of the

six towns proposed by the State Government have been approved. I can only request the Union Minister, Gadkari Sahib to not deprive our State of its legitimate share of development. Patiala, as you know, is declared as a counter-magnet town of the NCR by the Ministry of Housing and Urban Affairs. This only strengthens our case for approval of the Ring Road project.

I also call upon the Union Housing and Urban Affairs Minister to include Patiala in the list of new towns to be taken up under the Smart Cities Programme. In fact, I feel all the counter-magnet towns in the States around Delhi, should be included in this scheme whether it is Patiala or Hissar.

I will conclude by saying that the people of Punjab look at the Government of India with hope - that they will provide them their rightful due - in the true spirit of Cooperative Federalism. Mr. Chairman, Sir, Punjab has always stood by the nation. So, its high time the nation stood by Punjab and recognised and redressed its legitimate demands.

Thank You!

(ends)

***श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट):**

---

* Laid on the Table

*SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA):

*Laid on the Table

1509 बजे

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सदरे जम्हूरिया के ख़िताब के सिलसिले में शुक्रिया की तहरीक पर बोलने का मौका दिया।

I am equally grateful to my leader, Dr. Farooq Abdullah, for having given me an opportunity to speak in this House. I am proud that I am standing in this august House where seven decades back, a senior from our clan Maulana Mohammad Sayeed Masoodi stood.

(1510/CP/SNB)

Thereafter, Shri Shenu-Ul-Shenim was declared as the best parliamentarian along with the late Atal Bihari Vajpayee. जब सारा मुल्क जम्हूरियत के रक्स में रक्सा है, the country is celebrating the dance of democracy and 610 million people have been part of this dance. It is unfortunate that the State of Jammu and Kashmir is being deprived of having an elected Assembly and an elected Government.

बड़े दु:ख की बात है कि सारे मुल्क में जम्हूरियत का बोलबाला है और बगैर किसी वजह के जम्मू-कश्मीर को इससे अलग रखा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर इस वक्त प्रेसीडेंशियल रूल के तहत है, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं शुक्रिया की तहरीक पर बात करूंगा तो मेरे जेहन में जम्मू-कश्मीर होगा और जम्मू-कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल है, वह होगी।

चेयरमैन सर, जम्मू-कश्मीर में गवर्नर राज लगने का कोई अवसर नहीं था। अगर लगा भी तो, एक बाज़ाब्ता एक हुकूमत तशकील देने का एक सुझाव था, एक प्रस्ताव था। जो इस वजह से नाकाम हुआ कि रिपोर्टनरी एक फैक्स मशीन ने काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टीट्यूशनल इंपेयरमेंट था।

अब जम्मू-कश्मीर में प्रेसीडेंशियल रूल जारी रखने की कोई वजह नहीं है, कोई अवसर नहीं है। इस बात का दु:ख है कि सदरे जम्हूरी के खिताब में जम्मू-कश्मीर में इलेक्शन कराने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इलेक्शन कराने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जम्मू-कश्मीर में हम एक एकाउंटेबल, एक जवाबदेह हुकूमत बनाएं, ताकि जो एक खलीज है, वह खलीज पाटी जाए और लोग उस तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाएं, जो सारे मुल्क में है। इलेक्शन को मोअखर करने के लिए तरह-तरह के बहाने तलाशे गए, इस मौजूदा पार्लियामेंट इलेक्शन में। एक ताज्जुब होगा मुअज़्जिज मेंबरान को कि एक नया तरीका इख्तियार किया गया। Clubbing of polling stations and clustering of polling booths. दस मील के मुरब्बा, मील के अहाते में एक जगह पर पोलिंग बूथ रखे गए। कहीं-कहीं हैमलेट से पांच-छ: किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ रखे गए। There was an effort to ensure that less and less people come to the polling stations and the polling percentage in the State was below average. उसके बावजूद भी पार्लियामानी इलेक्शन हुए और सरकार के यह कहने के लिए कोई वजह नहीं बच पाई कि इलेक्शन मोअखर किए जाएं। एक तरफ सरकार बड़े फख्र से कहती है कि हमने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए, हमने पंचायत के इलेक्शन करवाए और पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए और दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शन को बगैर किसी वजह के टाला जा रहा है। 5 से 8 किलोमीटर तक पोलिंग स्टेशन हैमलेट से, बस्तियों से, आबादियों से दूर रखा गया। जब वह भी काम नहीं कर पाया, तो अब नई बात आ रही है। नई बात यह कही जा रही है कि डीलिमिटेशन का जिक्र हो रहा है। एक तरह तो तरदीद होती है डीलिमिटेशन की, नहीं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आईन ऐसी इज़ाज़त नहीं देता है। The Constitution would not permit it. दूसरी तरफ ऐसी भी जिम्मेवारियां हो रही हैं कि और मोअखर करने का एक बहाना बनाए जाए।

जनाब चेयरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर का अपना एक आईन है। डीलिमिटेशन का जो इश्यू है, जम्मू-कश्मीर का आईन जो है, it is Section 47 of the Constitution that deals with delimitation.

(1515/SK/RU)

2026 तक डिलिमिटेशन फ्रीज की गई है। जैसा कि सारे मुल्क में है कि डिलिमिटेशन का 2031 तक कोई अवसर नहीं है। Nor would the Constitution permit delimitation till 2031 like the rest of the country. But the idea of delimitation is being projected or put forth as a reason for deferring elections. इसकी कोई जवाज़ ही नहीं है।

स्पीकर साहब, जब सदर-ए-जम्हूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक की बात हो रही है, ज़ाहिर सी बात है कि मैं जम्मू-कश्मीर की तनाज़र में बात करूंगा। जम्मू-कश्मीर का अंग-अंग कराह रहा है। हम हर हफ्ते खबरें अमवात की सुन रहे हैं। मौत किसी तरफ भी हो, कैसे भी हो, तकलीफदेह है। लेकिन यह तकलीफदेह बात है कि सदर-ए-जम्हूरिया के खिताब में जम्मू-कश्मीर मसले के हल के लिए कोई पेशरती की बात नहीं की गई है। जम्मू-कश्मीर के मसले को हल करने का बातचीत ही वाहिद तरीका है, जो 70 साल से लटक रहा है। जब तक हम डॉयलॉग की प्रोसेस शुरु नहीं करेंगे, We feel encouraged by a change in the narrative. प्राइम मिनिस्टर साहब ने रीजनल एस्पिरेशन्स की बात की, अपोजिशन की बात की, खातिर में लाने की बात की लेकिन वह परक्युलेट नहीं होता है, एड्रैस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है।

हमें उम्मीद थी कि सदर-ए-जम्हूरिया के खिताब में जिक्र होगा कि क्या डॉयलॉग की संजीदा कोशिश की जाएगी। रियासत के गवर्नर ने इशारा दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने जवानों से अपील की है कि वे आ जाएं, बातचीत के मेज़ पर, उन्होंने हुर्रियत की बात भी की। लेकिन एक खिताब में एक वाज़ह एक रोड मैप होना चाहिए था ताकि जम्मू-कश्मीर इस दलदल से निकल जाता। जम्मू-कश्मीर में अगर यह पोट बॉयलिंग रखी जाएगी तो इसका असर सारे मुल्क पर होगा।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन की बात है, एक साल में छ: महीने नेशनल हाईवे बंद रहता है। एक ट्रक को 300 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 10 से 15 दिन लग जाते हैं। डैवलपमेंट की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। सड़कों का हाल बदतर है, बिजली कहीं है ही

नहीं है, होटलों के कमरे खाली हैं, टूरिस्ट कहीं है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेल है। दिल्ली से श्रीनगर का किराया दिल्ली के दुबई के किराये से ज्यादा है क्योंकि सारे रास्ते बंद होते हैं। तकरीबन महीने में से 10 या 15 दिन नेशनल हाईवे बंद रहता है और जो अन्य हाईवे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। सड़कों की हालत बदतर है। इसके लिए जरूरी है कि फौरन ही इंतखाबात किए जाएं ताकि जवाबदेह, एकाउंटेबल हुकूमत बन जाए जो लोगों के लिए जवाबदेह हो, जो तरक्की की दौड़ में जम्मू-कश्मीर को शामिल करे।

इसके अलावा यह मुतालवा होगा कि जम्मू-कश्मीर के मसले के दाइमी हतमी और मुनसिफाना हल के लिए एक संजीदा कोशिश की जाए, एक मीनिंगफुल डॉयलॉग की शुरुआत की जाए। यह इकोनामिकली वाइज़ नहीं है कि सारी कंट्री के लिए कि जम्मू-कश्मीर ऐसे ही रहे। आप हैल्थ केयर का स्टैट्स देखिए। बिहार में 100 से ज्यादा अमवात हुई है, यह हैल्थ केयर का मसला नहीं है, हास्पिटल का मसला नहीं है, यह स्टार्वेशन का मसला है। रिपोर्टडली बच्चे स्टार्वेशन की वजह से मजबूर हो गए ऐसा कोई फल खाने के लिए जो कि अभी कच्चा था। यह स्टार्वेशन की बात है। इस सारे पसमंजर में कोई मतलब नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में स्ट्रीटस में अमन रखने के लिए खर्च करें, यहां की हैल्थ केयर, डैवलपमेंट की तरफ ध्यान न दें।

मेरा यही मुतालवा है कि एक इलैक्शन फार्म कराया जाए और मीनिंगफुल डॉयलॉग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शुरु किया जाए ताकि मसले का हल निकल आए।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यहां बहुत लंबी सूची है, सभी को अवसर मिले इसलिए समय का सभी सदस्य ध्यान रखें।

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी):** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव में महिलाओं ने पूर्व की अपेक्षा में ज्यादा मतदान किया है, एवं महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है। इस 17वीं लोक सभा के लिए सबसे ज्यादा 78 महिलाओं का चुना जाना लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास" के मूलमंत्र को लेकर बिना किसी भेदभाव, बीते पांच वर्षों में मेरे क्षेत्रवासियों ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देशवासियों के मन में आशा की किरण जगी है। यहां तक कि मेरा संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्से अति पिछड़े व आदिवासी बाहुल्य हैं जहां अब तक भी न कोई नेटवर्क है और ना ही संचार का साधन, परन्तु मुझे यह साक्षा करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि वहां भी मेरे भ्रमण के दौरान "मोदी है तो मुमकिन है।" "सबका साथा, सबका विकास" "अब की बार तीन सौ पार" व "फिर एक बार मोदी सरकार" के नारे लगते रहे हैं।

मैं साझा करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय सीधी आज तक रेल सुविधाओं से वंचित है। 2014 के पूर्व लगभग 35 वर्ष से लंबित पड़ी ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को बजट न मिलना इसका प्रमुख कारण था। परंतु 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बनने के बाद ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को एक नया जीवन मिला और अब तक लगभग दो हजार करोड़ से भी ज्यादा का बजट प्राप्त हो चुका है। जिसके परिणामस्वरूप आज रीवा से सीधी तक के भू-अधिग्रहण की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक और ऐतिहासिक सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र के सिंगरौली रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन व भोपाल के लिए साप्ताहिक ट्रेन के रूप में मिली, जिस कारण हमारी क्षेत्रवासियों को अत्यधिक सुविधा है।

---

*Laid on the table

सिंगरौली में नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, बैढ़न में रिजर्वेशन काउंटर, सीधी में पासपोर्ट सेवा केन्द्र, संजय टाईगर रिज़र्व को विकसित करने हेतु 290 करोड़ रुपये का बजट, मड़वास व सरई सहित मेरे आग्रह पर मेरे संसदीय क्षेत्र को और भी कई ऐतिहासिक सौगातें प्राप्त होने के साथ, केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना सहित और भी अन्य योजनओं के लाभ मेरे संसदीय क्षेत्रवासियों को बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। एक और ऐतिहासिक सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र को सिंगरौली जिले के चितरंगी जनपद पंचायत अंतर्गत बीछी सोन नदी पर पुल निर्माण हेतु लगभग 28 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार 30 मई को शपथ लेने के बाद से ही नए भारत के निर्माण में जुट गयी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलबध हों, जहां प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहां बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो, जहां आदर्शों की बुनियाद मजबूत बने, जहां विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी। हमारी केन्द्र सरकार द्वारा पांच लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स फ्री करना सरकार की अभिनन्दनीय पहल है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से केन्द्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने व उनको मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 2022 तक हर गरीब की अपनी पक्की छत हो इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना कारगर साबित हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल करेंगे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी केन्द्र सरकार ने बहनो की रसोई में गैस चूल्हा ही नहीं भेजा है अपितु धुएं से जलने वाले फेफड़ों और बढ़ने वाले आंसुओं को पोंछा है। मैं जनधन बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना के बारे में एक उदाहरण साझा करना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शहडोल जिले का एक विधान सभा ब्यौहशि है। मैं विगत वर्ष एक यादव परिवार जिनके परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की एक साथ आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गयी थी मैं वहां संवेदना प्रकट

करने गयी थी। जाने के बाद देखा कि परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। मैने जिलाधिकारी से बात की कि शीघ्र पता करें कि इन लोगों का जनधन या सुरक्षा बीमा था। कुछ देर में जिलाधिकारी ने बताया कि महोदया इस परिवार में सबका दोनों बीमा है। तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ हुई और कुछ दिनों में निर्धारित राशि परिजनों को प्राप्त हो गई। ऐसे कई परिवार हैं जो इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। इस हेतु भी मैं आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

(इति)

***श्रीमती रमा देवी (शिवहर):**

---

* Laid on the Table

(1520/YSH/NKL)

1520 बजे

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): स्पीकर सर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सारंगी जी ने कल अपनी सारंगी बजाई थी, तो विपक्ष के चेहरे पर जब मैंने रोष का भाव, गुस्सा, पीड़ा, दर्द महसूस किया तो मुझे एक शेर याद आया कि

"तमाम चेहरों पर खौफ जारी है,

यह चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। "

जब इधर यहां योजनाएं बताई जा रही थीं, तो उधर पेट में मरोड़ हो रही थी कि यू.पी.ए. ने यह किया, यू.पी.ए 2 ने यह किया।

"मुझे पतझड़ो की कहानियां सुना सुनाकर न उदास कर,

नए मौसमों का पता बता जो गुजर गया सो गुजर गया।"

सर, मैं पांचवी बार दिल्ली आया हूँ, मैं वहां बैठा करता था। मैंने 1 करोड़ से शुरू किया था और 5 करोड़ छोड़ कर गया। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली व खरंजा का निर्माण करता रहा। एक बार मैंने सोचा कि जिंदगी भर किया क्या? एम.पी बनते रहें, विपक्ष में रहे, क्षेत्रीय दलों में रहें, खडंजा का निर्माण करते रहें। मैं पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे मशहूर नेता मोदी जी के नेतृत्व में एम.पी. बनकर आगरा से आया हूँ, तो राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका हो रही है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे उन्होंने काम अच्छा नहीं किया था, लेकिन अब अच्छे काम में कन्वर्ट हो गया है कि नरेन्द्र भाई मोदी जी को बहुत गरीब घर में पैदा किया। अगर वे गरीबी में पैदा नहीं होते और गरीबी नहीं भोगी होती तो लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं आती। अगर नामदार की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते तो गरीबों का भला होने वाला नहीं था। मैं तो ईश्वर से फिर कहूंगा कि जब तक लोकतंत्र रहे, जिसने गरीबी भोगी हो उसे ही प्रधान मंत्री बनाना। क्योंकि मुंशी प्रेमचन्द की 'एक पूस की रात' कहानी है, उसको

डनलप पिलो पर सोने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, टॉमी हील पहनने वाले और रे-बैन का चश्मा लगाने वाले याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, 90 परसेंट नम्बर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है, जिसने पूस की रात एक पिछौरा में काटी हो, एक चादर में काटी हो। मोदी जी ने काटी है, इसलिए गरीबों के लिए ये तमाम योजनाएं आई हैं। इनटोलरेंस की बातें बड़ी हुई। मैं उन दिनों यहां नहीं था, लखनऊ में था। मुझे आज बड़ा अचम्भा हो रहा है कि today is the black day for democracy. आज ही के दिन, जब मैं 14 साल का था तब आपातकाल लगा था लेकिन आपातकाल का इधर से जिक्र ही नहीं हुआ। मेरे लिए छोड़ा था। आज ही के दिन लगा था काला दिवस। जिक्र होना चाहिए, ट्वीटर पर नहीं लिखना चाहिए। यहां इसके बारे में बताना चाहिए। मेरे लिए छोडा तो मैं बता रहा हूँ। आज ही के दिन अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, जार्ज फर्नांडीज, चन्द्र शेखर, मोरारजी भाई, चरण सिंह जी, मधु लिमये, मधु दंडवते सब बंद कर दिए थे। अपने प्रकाश सिंह बादल, हमारे बीजू पटनायक, कर्पूरी, ठाकुर मुलायम सिंह यादव तक इसमें आते हैं। आप इंटोलरेंस की बात कर रहे हैं। उस दिन मालूम है कि क्या लिखा था

"यह मत कहो आकाश में कि कोहरा घना है,
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। "

अगर उस दिन आपने यह कह दिया होता कि बादल हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपको जेल भेज देतीं कि आप हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हो। मेरे गांव के एक तांगे वाले ने केवल यह दिया कि चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल तो 19 महीने जेल में रहा था। उसी दिन मनु शर्मा जी, जो हेमन्त शर्मा जी के पिताजी है, उसी रात उन्होंने लिखा था कि

"मौसम की आंखों में नमी हो गई, लगता है कोई गमी हो गई,
मेरे टेबल पर पड़ी संविधान की पुस्तक में बहुत सारे पन्नों की कमी हो गई।"

संविधान में आपातकाल का कुछ कहा है लेकिन परिस्थितियां नहीं थी जिसमें वह लगा था। फिर दुष्यंत को लिखना पड़ा कि उस समय के हालात सन् 1974-75 के याद करो।

(1525/RPS/KSP)

जय प्रकाश जी के लिए कहा था :

"एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में
या यूं कहें कि इस अंधेरी कोठरी में
एक रोशनदान है।"

इन्होंने उस रोशनदान को बन्द कर दिया था। जेपी साहब को जेल भेज दिया, उनकी किडनी खराब हो गई। डायलिसिस शब्द मैंने बचपन में तभी सुना था, जब उनकी डायलिसिस जसलोक अस्पताल में हुई थी। आज माफी मांग लीजिए तो ठीक रहेगा या इनटोलरेंस कहना बन्द कर दीजिए। …(व्यवधान) चले गए।

यह जो सरकार आई है, केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के परिश्रम की पराकाष्ठा के पसीने से यह खुशबू आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर बैठे हैं। आपने भी कहा था – गरीबी हटाओ, लेकिन हटी नहीं, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है।

"गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है,
अगर गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे।"

रिक्शा चलाने पर आप मजबूर हो नहीं सकते। शौचालय शब्द को अभी तक आप नॉनवेज क्यों कहते रहे? हमारे प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से शौचालय का जिक्र किया। हम सारे लोग गांव से ही आए हैं। महिलाएं खेत में शौच के लिए जाती थीं। जब तीन-चार दिन लगातार बारिश होती है, जिसे हम लोग 'झड़ी' कहते हैं, तब वे खेत की मेड़ पर बैठती थीं और जब पानी ओवरफ्लो करता था तो गांव की सड़क पर बैठती थीं। जब अचानक हेडलाइट वाली कार आती थी या गांव का कोई बुजुर्ग उधर से निकलता था तो वे शौच करते हुए खड़ी होती हैं। इस देश में कहा गया है कि खाना खाते हुए अगर कोई साहब आ जाएं, लाट साहब आ जाएं, तब भी

आपको उठना नहीं है। खाना खाते हुए उठने में कौन सी आंतें उलट जाएंगी, लेकिन शौच करती हुई महिला को जब खड़ा होना होता है तो उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है, पेट भी खराब होता है और कपड़े भी खराब होते हैं। एक दिन आपमें से किसी ने कहा कि यह बहुत छोटा काम है। अगर छोटा काम था तो नेहरू जी कर जाते, इंदिरा जी कर जातीं, मोरारजी भाई कर जाते, चरण सिंह कर जाते, देवगौड़ा या गुजराल जी कर जाते। …(व्यवधान) उसे आप बोलना। उन्होंने इस दर्द को समझा और इसे इज्जतघर नाम दिया है। मैं पुलिस में था, अगर 100 बलात्कार की एफआईआर आती हैं तो उनमें से 90 मामलों में शौच करने जाती हुई महिला के साथ बलात्कार की बात होती है। शौच के लिए महिलाएं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त होने के बाद जाती हैं, इसका लाभ गुण्डे भी उठाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाएं ग्रुप में शौच के लिए जाती हैं, क्योंकि उनमें असुरक्षा की भावना होती है। क्या कभी आपने दस आदमियों को बीड़ी पीते हुए, शौच करते हुए बैठे देखा है? नहीं, क्योंकि वे सुरक्षित हैं। यह कोई छोटा काम नहीं है। यह बहुत बड़ा काम हुआ है।

आवास हम लोग पॉलिथिन में देखते हैं, खपरैल में देखते हैं, पूर्वांचल और बिहार का बहुत बुरा हाल है। एक शेर है :

"सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, नाराज़ हैं,
दिल पर हाथ रखकर यह कहिए देश क्या आज़ाद है।
कोठियों से मुल्क के म्यार को मत आंकिए,
आधा हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।"

इस आधे हिन्दुस्तान की चिन्ता मोदी जी ने प्रधान मंत्री नगरीय आवास योजना और प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करके करने का काम किया है। उज्ज्वला गैस योजना की बात है। सर, जब मैं यहां एमपी बनकर आया था, गंगवार साहब यहां थे, हम लोगों को 48 कूपन तीसरे महीने मिलते थे और पहले ही दिन 1200 एप्लीकेशन्स आ गई थीं। …(व्यवधान) बेईमान लोग उसे बेचते भी थे। …(व्यवधान) मेरा भतीजा मैनपुरी में रहता था। बलराम सिंह यादव वहां एमपी थे, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि आदरणीय एमपी साहब, मेरा भतीजा आपके क्षेत्र में रहता है, उसे

एक कूपन दे दीजिए। उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा, मेरा साढ़ू तुम्हारे क्षेत्र में रहता है, पहले तुम उसे एक कूपन दो, तब मैं दूंगा।

सर, कहने का मतलब यह है कि एक एमपी दूसरे एमपी से आदान-प्रदान कर रहा था, लेकिन आज गांव की अंतिम महिला को भी गैस चूल्हा दिया गया है। इसी को अन्त्योदय कहते हैं। आपके शहर से, मैं अपना एक अनुभव बताउंगा। आपको पता है कि मैं मेरठ में था, पुलिस में था। मैं एक बार घर छुट्टी पर गया तो मां रात में बच्चों का दूध गर्म करने के लिए सात बार उठी, पूरी फैमिली आई हुई थी और बच्चे गुनगुना दूध पीते थे। मैंने उनसे कहा कि आप तो रात भर नहीं सोई हैं। मैं जब लौटकर आपके शहर में आया, पता नहीं इस सदन में उस एजेंसी का नाम लेना चाहिए या नहीं, नाम ले लेता हूं – …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) वहां कोई कर्नल की वाइफ थीं, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक गैस कनेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म भर दो। मैंने पूछा कि कब आऊं तो उन्होंने कहा कि पांच साल बाद आना। मैंने पुलिस के अपने स्टारों को देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) से लिखवा दो। मैंने कहा कि यह कौन है? उन्होंने कहा कि …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हैं। मैंने कहा कि मेरी वहां तक पहुंच नहीं है। फिर मैंने नियमों के तहत उनकी कार का पांच-सात बार चालान किया।

(1530/RAJ/SRG)

फिर, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इतवार को गैस ले जाना तो मैंने कहा कि मैं चूल्हा नहीं लूंगा, चूल्हे में ही आपके यहां बहुत इनकम होती है। वह श्रुतिगंज में सरदार बनाता है, मैं उससे चूल्हा ले लूंगा। भरा हुआ गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और रेगुलेटर ले कर, उसी दिन छुट्टी लेकर, संगम एक्सप्रेस में बैठ कर गांव गया और जब मैंने वह अपनी मां को दिया तो उन्होंने कहा कि सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात से बढ़ कर यह गिफ्ट है। मैं ऐसे डिसक्राइब करूंगा।

मैं छः महीने बाद फिर घर गया तो कहा कि मां बड़ी परेशानी होती होगी। यह ब्लैक में मिलती होगी, इटावा जाना पड़ता होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे अमृत की तरह खर्च कर

रही हूं। तीन पुलिस अफसर की मां और एक पुलिस अफसर की पत्नी के लिए वह सोना-चांदी से भी बड़ी गिफ्ट थी। आज मोदी जी ने गांव की अंतिम महिला को गैस सिलेंडर देने का काम किया है।

आयुष्मान योजना, हम सभी लोग गांव से आए हैं। सर, जब हम बीमार होते हैं तो एक-दो दिन ऐसे ही काट देते हैं। अगले दिन हम चाय में तुलसी जी पी कर अपने बुखार को उतारते हैं। उसके अगले दिन काढ़ा पीते हैं। फिर भी ठीक नहीं होते हैं तो 10, 15, 25 30 या 35 रुपये, जो भी होते हैं, उसे लेकर झोला झाप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बुखार आ रहा है। वह कहता है कि पांच दिनों का कोर्स है। भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, हमें 28 रुपये की दवाई दो। वह बिना रैपर की, बिना बहुराष्ट्रीय कंपनी की लाल-नीली-पीली कुछ गोलियां कागज में मोड़ कर दे देता है और हमारी किडनी को खराब करता है। हम सभी को मरना है, लेकिन अब मोदी जी के जमाने में इलाज के अभाव में किसी को नहीं मरना है।

सर, दिल्ली में सात फाइव स्टार होटल्स से बड़े अस्पताल हैं। अगर धोखे से हमारे गांव का यहां आ गया तो उसके सारे खेत बिक जाएंगे। जो ठीक होते हैं, वे भी मैनेजमेंट की आलोचना करते हैं कि दस लाख रुपये खर्च होने के बाद अभी खिचड़ी नहीं खा रहा है। जो ठीक नहीं होता है, वह कहता है कि आठ लाख रुपये चले गए, तीन रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज पर पैसे लाए हैं, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं। उन सभी के दर्द को अगर किसी ने समझा है तो मोदी जी ने समझा है, इसलिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों के साथ उनको धन्यवाद देता हूं। अभी वर्ष 2019 है। जब आप वर्ष 2024 में जाएंगे, अभी योजना शुरू की गई है, हर गांव में एक मरीज किडनी, ट्रांसप्लांट, कैंसर, या बाईपास वाला मिलेगा और अगर वहां लाल-नीले झंडे वाले पहुंच गए तो वह कह देगा कि घर की तरफ मत आना। मैं मर रहा था, पांच लाख रुपये में मोदी जी ने इलाज कराए, इधर की तरफ तुम्हारी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, गाड़ी तोड़ दी जाएगी। मैं यह आज आपको कह रहा हूं। आप पांच साल बाद आयुष्मान योजना का प्रभाव देखना। चिकित्सा, सरकार की प्राथमिकता है। हम लोग एम्स के लिए चिट्ठी लिखते हैं। आयुष्मान योजना बहुत बढ़िया है। पांच लाख रुपये, प्रति व्यक्ति,

प्रति साल मैं बद्दुआ देता हूं कि किसी को इसका लाभ न मिले, लेकिन लोग बीमार होते हैं और ऐसे समय जब तीन रुपये सैकड़ा पर लोग कर्ज लेते हैं, उनके लिए मोदी जी इंतजाम कराएंगे।

मुद्रा योजना से अंडेवाल, केलेवला, ठेलेवाला, चाउमिनवाला, बर्फवाला और पंक्चरवाला, पचास हजार रुपये से अपना रोजगार कर रहे हैं। वे श्रमजीवी लोग हैं। अगर आप पचास हजार रुपये नहीं देते तो वे कट्टा अपने हाथ में लेते और अपराध करते। मुद्रा योजना के लोन ने अपराध को भी कम करने का काम किया है।

मैं यूपी पर आ रहा हूं, किसानों की आय दोगुना करने के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा तो मैं चौंका कि न आलू दोगुने होंगे, न गेहूं और न धान लेकिन उनकी आय कैसे दोगुनी हो जाएगी। रात में अखबार पढ़ा कि पॉल्ट्री, पिगरी, स्प्रींकलर, ड्रिप एरिगेशन, फूल-फल की खेती के द्वारा और नीली क्रांति, झंडे में जो चक्र है, वह नीला है, वह प्रगति का सूचक है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि नीली क्रांति होगी, इससे आय दोगुनी नहीं बल्कि चारगुणी होगी, क्योंकि अभी मैं पांच दिन पहले तक मछली पालन का मंत्री था और पशुपालन मंत्री था, रीता जी भी थीं, इरिगेशन का मंत्री था। किसानों की आय इन्हीं माध्यम से दोगुनी हो सकती है। अब पशुपालन विभाग बना दिया गया। मैं इसी का मंत्री था। मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 13 हजार करोड़ रुपये दे दिए गए। जिस राज्य में अच्छा पशुपालन होता है, वहां के किसान कभी दैवीय आपदा आने पर आत्महत्या नहीं करते हैं। यहां पर बादल जी बैठी हुई हैं। मुर्रा भैंस, शाहीवाल, थारपारकर, गिर गाय की नस्ल है। बुंदेलखंड के लोग आत्महत्या करते हैं। वहां छोटी-छोटी गायें हैं – वे गोबरी और चायवाली गायें हैं, वे दूध वाली गायें नहीं हैं। इसलिए पशुपालन के लिए 13 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया गया है। नीली क्रांति से पूरा साउथ फायदा उठाएगा।

विदेश नीति के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान) You can change your wife but not neighbour. पड़ोसियों को पिछली सरकार ने शपथ लेते ही निमंत्रण दे दिया। नवाज शरीफ आए, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं मिल्ट्री साइंस का प्रोफेसर हूं, तो मुझे लगा कि उनको बुलाना चाहिए। उनको बुलाया, फॉर्मलिटी भी हो गई, अम्मी के लिए शॉल भी दे दी, दो

कदम आगे। इसके बाद हम लोग चौंक गए कि अपनी जान को खतरे में डाल कर हमारे प्रधान मंत्री जी शगुन का लिफाफा देने चले गए।

(1535/IND/KKD)

हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए और उन्होंने क्या किया - पठान कोट अटैक। हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए, उन्होंने पहले चूमा, फिर चाटा, फिर काटा। तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते, जो चाटते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। पाकिस्तान दही के धोखे में चूना चाट गया। यह वो समय नहीं रहा कि भारतीय संसद पर हमला कर दो और कुछ न हो। उन्होंने पठानकोट किया, हमने उरी किया। उन्होंने पुलवामा किया, तो हमने बालाकोट किया। आतंकवादियों ने मौलाना से कहा कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, हूरें स्वागत करती हैं। इस बार मोदी जी ने एयर फोर्स द्वारा इतना बारूद गिरा दिया कि वे जन्नत से ऊपर चले गए हैं। इस बार उन्हें जन्नत भी नसीब नहीं हुई है।...(व्यवधान) वहां जाकर गिन लो। शौचालय भी गिन लो। मैंने न तो शौचालयों की संख्या बताई है, न आयुष्मान की बताई है। यदि आप लाशें गिनने जाते हो, तो शौचालयों की संख्या भी गिन लेना।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीरो करप्शन के साथ पांच साल सरकार ने काम किया। काजल की कोठरी में पांच साल रहो और एक टीका भी लगाकर न आओ, यह काम कोई पॉलिटीशियन नहीं कर सकता, यह केवल कोई फकीर हो या सन्यासी हो या औघड़ हो, वही कर सकता है और हमारे मोदी जी इसी सीमा में आते हैं। मोदी जी पर एक दाग नहीं, लेकिन आप तो वर्ष 1948 में कृष्ण मेनन के समय शुरू हो गए थे। मेरे पास 150 कांड हैं। अंतरिक्ष में 2-जी, जमीन में बोफोर्स और जमीन के नीचे पाताल में कोयला। न अंतरिक्ष छोड़ा, न जमीन छोड़ी और न पाताल छोड़ा। मोदी जी अंतरिक्ष में तिरंगा फहराना चाहते हैं, लेकिन ये 2-जी और कॉमनवैल्थ घोटाला करना चाहते हैं। ऐसा काम कोई फकीर ही कर सकता है।

"न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर यह कैसा सफर है,
फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है।"

इसलिए देश को वही आगे ले जा सकता है, जो फकीरनुमा हो।

"बिजली उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में,
गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में, बूढ़ा बरगद साक्षी है,
किस तरह से खो गई रमसूदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में।"

हमारी सरकार ने पांच साल में बिजली पहुंचा दी। जिस काम की हम 70 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह काम पांच साल में हो गया।

महोदय, अब जरा महाठगबंधन पर चर्चा हो जाए। बहुत साल पहले हमारे चाचा कौटिल्य ने कहा था कि कोई राजा जब बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियां हुआ करेंगी। यह ध्रुव संधि हुई थी। एक-दूसरे को गाली देने वाले, गेस्ट हाउस कांड का वर्णन करने वाले आपस में मिल गए। यह तो होना ही था। वर्ष 2014 में मलूक नागर की पार्टी को डबल जीरो सीट मिली। सपा वाले बूथ कैपचर से पांच सीट और इधर माँ-बेटे और वहां बाप-बेटे भी हार गए थे। इस बार गाय-बछड़ा में से बछड़ा गायब हो गया है। यह कांग्रेस का पुराना चुनाव चिह्न है। यह तो होना ही था और मैं चुनाव में कहता था कि आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लो, चुनाव के बाद बहनजी प्रेस कांफ्रेंस बुलाएंगी और उसमें कहेंगी कि अखिलेश यादव ने हमारा वोट ले लिया, लेकिन हमें वोट ट्रांसफर नहीं किया। मुझे राजनाथ सिंह जी ने एक बार टोका, मैंने कहा कि यह सरकार बन भी जाए, तो नहीं चलेगी।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): महोदय, मैं कनक्लूड करने जा रहा हूं। यूपी में सपा-बसपा होता रहा। यह गठबंधन क्यों हुआ, क्योंकि

'तुम संग पुरुष न मौसम नारी, यूपी लूटो बारी-बारी।'

इस बार बारी-बारी समाप्त हो गया, क्योंकि योगी जी आ गए। फिर इन्होंने कहा कि गठबंधन करो कि

'तुम संग पुरुष न मौसम नारी, आओ मिलकर करें दिल्ली की लूट की तैयारी।'

दिल्ली का रास्ता यूपी से हो कर आता है। हमने गाजियाबाद से आगे दिल्ली में घुसने नहीं दिया।

महोदय, मैं आगरा से आता हूं। जल शक्ति मंत्रालय बन गया है। यमुना नदी में पानी नहीं है। बैराज बहुत जरूरी है। गिरता हुआ भू-जल स्तर बहुत बड़ी समस्या है। यदि पानी नहीं रहेगा, तो ताजमहल को बहुत खतरा है। यमुना नदी में पानी रहे। हमारा इंटरनेशनल शहर है। यहां इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए। हमारे यहां 15-20 हजार गोरे घूमते रहते हैं। यदि कोई आईपीएल हो जाएगा, तो हमें रेवेन्यू मिलेगा। यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए और एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कोई भी दुनिया का व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से हिंदुस्तान आता है, तो ताजमहल देखने आता है। उसके बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाता है। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि

"तू पूरी तरह भी साथ दे, तो कुछ और बात है,
तू जरा भी साथ दे तो और बात है,
चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग,
पर दूसरा भी साथ दे तो अलग बात है।"

मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन अच्छी सरकार का समर्थन करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

***श्री कमलेश पासवान (बासगाँव):**

---

* Laid on the Table

***श्री रमेशभाई लवजीभाई धडुक (पोरबंदर):**

---

* Laid on the Table

(1540/VB/RP)

1540 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरी मेडन स्पीच नहीं है, मैं यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। साथ ही, मैं बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और अम्बेडकर नगर के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ भेजा है।

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 17वीं लोक सभा को संबोधित करके सरकार की नीतियों और देश की दिशा के बारे में हमें बताने का काम किया है।

सरकार कहती है कि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्तम्भ किसान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार को किसानों की इतनी ही फिक्र है, इतनी ही परवाह है, तो पिछले पाँच वर्षों में कृषि विकास दर में 33 प्रतिशत की कमी क्यों हुई है, किसानों की आय 14 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर कैसे पहुँची है? मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि एमएसपी के जिस वादे पर सरकार स्थापित हुई थी, आज एमएसपी दोगुनी क्यों नहीं हुई है? इस पर सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए।

एक तरफ सरकार की मार्केटिंग लाइन है- 'सबका साथ, सबका विकास।' दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 10,226 करोड़ रुपये की बकाया राशि को सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। अभी हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे, यदि वे इस पर भी कुछ बोलते, तो बहुत अच्छा होता।

बैंकों एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं की साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निपटारा सरकार ने कर दिया, जिससे यह प्रश्न उठता है कि यह किसका विकास और किसका साथ है, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ।

मान्यवर, देश के लाखों किसान अपने हक़ की लड़ाई लड़ते रहे, तो सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया। जब इंतजार करके, लड़कर और थककर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, तब भी सरकार ने उनको बेबस और नज़रअंदाज करके छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2015 से लेकर आज तक हुई आत्महत्याओं के आँकड़ों को सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इन शर्मनाक आँकड़ों को सदन में रखने का काम किया जाए ताकि यह कड़वी सच्चाई हमारे सामने और देश के सामने आए।

अगर आँकड़ों की ही बात की जा रही है, तो सरकार के एक और मुद्दे के प्रदर्शन को देखने की जरूरत है। आज देश में बेरोज़गारी इस स्तर पर है, जितनी यह पिछले 45 वर्षों में नहीं हुई थी। जहाँ सरकार एक करोड़ नौकरियों के वादे पर सत्ता में आई थी, आज वहीं सरकारी नौकरियों का गला घोंटा जा रहा है। नौज़वान लोग बेबस हो चुके हैं। वे एम.ए., बी.ए., एम.एस.सी., एम. फिल और पी.एच.डी. करके भी खलासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

मैं नौज़वानों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की आवाज़ भी उठाना चाहता हूँ। अल्पसंख्यकों को भी बदहाली में छोड़ दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों में गौ माता के अपमान के संदेह में न जाने कितने अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार हुए हैं। लेकिन सरकार ने आज 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे से मुँह फेर लिया है और देश के नागरिकों को लाचार छोड़ दिया है।

मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर जरूर दिलाना चाहता हूँ कि वह अपने चप्पल को देखे, अपने जूते को देखे, अपनी बेल्ट को देखे, अपनी घड़ी के पट्टों को देखे और यहाँ पर लाए हुए देशी-विदेशी हैंड बैग्स को देखे और पूछे कि उसका चमड़ा किस चीज का बना हुआ है।

मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि आज उनके गौ-रक्षक कहाँ गये, कहाँ गये उनके धर्म के सेवक और कहाँ गये समाज सुधारक?

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती अगाथा संगमा।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): मान्यवर, आखिरी पॉइंट है।

आज देश का प्रजातंत्र एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है।

माननीय सभापति: अब आप बैठ जाएँ। समय की सीमा भी है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय अगाथा जी, आप अपनी बात प्रारंभ कीजिए।

(इति)

(1545/RCP/PC)

1545 hours

SHRIMATI AGATHA K. SANGMA (TURA): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address which was moved by Shri Sarangi *ji*. On behalf of my party, the National People's Party and my President Mr. Conrad K. Sangma, I would like to congratulate our hon. Prime Minister Modi *ji* for a very decisive mandate in the Election of 2019.

I may be a sole Member of the Lok Sabha from my political party, the NPP, but in no way do I stand alone. I stand here today as a woman and I speak here on behalf of the women of my country. I speak here today as a tribal and on behalf of the 8.6 per cent population of tribals in my country. I speak on behalf of the youth of my country. I speak on behalf of mother Earth that is facing the threat of devastation because of man-induced climate change. I speak on behalf of the youth of this country that is worried about unemployment and their well-being.

I have multiple identities. I am a woman; I am a tribal; I am a youth; I am a Christian. But today, as I stand here as a Parliamentarian, most of all, I am an Indian. I would like to assure our hon. Prime Minister and his Government that as long as the Government is working for the integration of this country, for the sustainable development of this country, my party, the NPP and myself, will extend our cooperation and our support to this Government.

Therefore, it is an honour for me to speak in favour of the Motion of Thanks on the President's Address today. It is a very comprehensive President's

Address. Since I have not been given much time, I will not be able to address all the important issues of the President's Address. Therefore, I will take a few minutes to just address a few issues.

In the morning, I was reading a newspaper. In the newspaper, the India Meteorological Department said that water is going to be a big problem in our country. Half of India is facing a drought-like situation. Ground water is depleting at a very alarming rate. I would like to acknowledge and thank the Government for taking water as a very important priority even in the President's Address. I thank the Government for opening a new Ministry that will streamline water. The issue of water can be addressed, I believe, by having water policies at the State level. Since all of us know that water is a State Subject, it is crucial for State Governments to also come up with some kind of a water policy. I am very happy to inform you here that my State, the Government of Meghalaya, has or is about to launch the first State Water Policy. It happens to be the first State that will be coming up with a separate Water Policy. I would like to say that this can be an example for other States in our country. If possible, the Central Government must encourage and incentivise State Governments to come out with a good State Water Policy.

I was also reading in the President's Address that there are going to be two crore new houses that will be built under the Pradhan Mantri Awas Yojana. My humble suggestion is that in areas where we have abundance of rainfall, like my own State of Meghalaya and the other States of North East, it would be a wonderful idea to incorporate rooftop rain water harvesting in the new houses that will be built under the Pradhan Mantri Awas Yojana. I think, even in the

States that do not have good rainfall, it would be a good idea to incorporate it in the new houses.

(1550/SMN/SPS)

Sir, I was reading about the *Namami Ganga* Scheme in the Presidential Address and it says many rivers like Narmada, Cauvery and the Yamuna will be included but the river Brahmaputra was not mentioned. I would request the Government to kindly consider and incorporate the Brahmaputra river which is the lifeline of the North Eastern States.

माननीय सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्रीमती अगाथा के. संगमा (तुरा): सर, मुझे बस 5 मिनट दीजिए।

माननीय सभापति: इतना सम्भव नहीं है। आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

SHRIMATI AGATHA K. SANGMA (TURA): Sir, in terms of agriculture, I would like to say that organic farming was mentioned in our Presidential Address. If the Government of India brings about this organic farming, I would like to say that the Government of Meghalaya will extend full support for incorporating these kinds of policies in our own State as well.

Sir, I am very happy to see that in the Presidential Address, our hon. President has mentioned that the tribal lifestyle is something from which we can learn a lot and it is very true. I would like to say that we are having the problem of deforestation. We are having one degree increase in temperature in our climate. According to our UN census, tree ratio per person in Canada is 8,953. In US, it is 716 and in India, it is 28. We have started a one tree one citizen campaign. (ends)

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):

*Laid on the Table

1552 बजे

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): धन्यवाद स्पीकर महोदय। आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं जे.एम.एम. पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले आदिवासियों की संरक्षा की बात हुई। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टेट्स में जो लॉज़ हैं, चाहे वे 5th शैड्यूल हो, 6th शैड्यूल, सी.एन.टी. एस.पी.टी. एक्ट हो, उनका कड़ा पालन होना चाहिए। हमारे स्टेट में उनका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हर बार, हर तरह से उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के लिए होने वाली है। मेरी इस पर सलाह रहेगी कि जिस तरह से रोडमैप होता है, रेलवे मैप होता है, वैसे ही वाटर मैप हमारे पास होना चाहिए। हम लोग जिस तरह से रोड बनाते है, पानी की धारा किस तरफ से बहेगी, इसका हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। रेलवे इस चीज़ का ध्यान रखता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन जब रोड बनाते हुए, अगर हम लोग इस कंटूर मैप का ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में फ्लैश फ्लड्स नहीं होंगे। थोडा सा महंगा जरूर होगा, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए।

किसान की आय को दुगुनी करने की बात की जा रही है। इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि किसान की आय दुगुनी सिर्फ फसल बीमा, बीज और खाद से नहीं हो सकती है। मवेशी भी कहीं न कहीं उनकी आय दुगुनी करने का स्रोत हैं। इसे राजनीति में न फंसाकर मवेशी हाट सुचारू रूप से चले। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि फसल के साथ किसी भी किसान के लिए मवेशी भी आय का स्रोत होता है। मैं अपने स्टेट के कुछ मसले बताउंगा। पी.डी.एस. की बात यहां आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में हमारे झारखण्ड की अगर हम बात कहेंगे तो इतने रिमोट एरियाज़ हैं, जहां पर आपका टावर सेल भी नहीं है। लोगों को 5-6 बार वहां पर अपना अनाज लेने जाना पड़ता है, बायोमैट्रिक सिस्टम फैल्योर की वजह से। यह समस्या हो सकती है कि ऐसा अन्य स्टेट्स में भी हो। सरकार के लिए मेरा यह सुझाव रहेगा कि जहां

बायोमैट्रिक सिस्टम काम नहीं करता है, वहां आप मैनुअल सिस्टम काम में लाइए, जब तक वहां पर आपका टावर स्थापित नहीं हो जाता है।

मैं यहां पर झारखण्ड की कुछ समस्याओं को लाना चाहूंगा। हमारे झारखण्ड में गंगा गुजरती है, वहां पर गंगा पुल की बात की गयी थी। तीन साल पहले प्रधान मंत्री जी ने वहां जाकर उस गंगा पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन तीन वर्ष के बाद भी वहां एक ईंट नहीं जोड़ी गई है। बन्दरगाह की बात है, बन्दरगाह में भी कोई अवरोध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्लो काम चल रहा है। एन.एच. 80 का जो काम है, नेशनल हाइवे का जो काम है, क्योंकि पैचेज़ में काम हो रहा है। उससे काम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। मैंने पिछले सदन में भी इस बात को रखा था, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं हुआ है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहूंगा कि हर एक समुदाय में हर एक जाति, धर्म के लोग अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है कि इसको उन पर छोड़ देना चाहिए। इसका मैं विरोध कर रहा हूं। सर, 2-3 पॉइंट और हैं।

जमशेदपुर में एक घटना घटी थी, हमको लगता है कि वह अपकी भी नॉलेज में होगी। सदन के सभी सदस्यों के लिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह देश सिर्फ हिन्दू और मुसलमान का ही नहीं है, सभी लोगों का है। मैं मन्दिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, आदिवासी हूं मैं चर्च भी जाता हूं और गुरुद्वारा भी जाता हूं।

(1555/KDS/MMN)

किसी डर और खौफ से नहीं जाता हूँ, क्योंकि यह मेरी इच्छा है, इसलिए मैं जाता हूँ। यह हमारे भारत का संस्कार है। अंत में, मुझे लगता है कि एम.पी. लैड के बारे में, जो सबके लिए है, उसकी एक बात करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम इस सिस्टम को चेंज किया गया था। ढाई करोड़ न करके इसे पाँच करोड़ किया जा रहा है।

(इति)

***श्री संजय सेठ (राँची):**

---

* Laid on the Table

1556 बजे

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूँगा। मेरा इस सदन पर विश्वास है। यह उर्दू, संस्कृत, हिन्दी का समन्दर है और इस समन्दर में आप मुझे डूबने नहीं देंगे।

महोदय, प्रेसिडेंट के भाषण में मुझे गीता दिखाई देती है, इसी में मुझे कुरान दिखाई देता है, और इसी में मुझे बाइबिल दिखाई देता है और इसी में मुझे गुरुग्रन्थ साहिब दिखाई देता है। इस ओर से भी इतनी आवाज़ और हमारी ओर से भी इतनी आवाज़ है, लेकिन प्रेसिडेंट स्पीच में ही गीता की आवाज़ है, कुरान की आवाज़ है, गुरुग्रन्थ साहिब की आवाज़ है। यही नए भारत की आवाज़ है। मोदी जी के दिशा-निर्देश में भारतवर्ष को आगे ले जाने का शब्द इसी में समाया है। यही भूतकाल है, यही वर्तमान है, यही भविष्य है।

महोदय, मैं उस प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ जहाँ बार-बार हमारा पड़ोसी क्लेम करता है कि हमारी टेरिटरी है। हमारे प्रदेश को 'जय हिंद' प्रदेश का नाम दिया गया है। मोदी जी जब भी अरुणाचल प्रदेश आते हैं, वह किसी से भी मिलते हैं तो जय हिन्द से स्वागत करते हैं इसलिए मैं भारतवर्ष और इस सदन को आज यह वादा करता हूँ कि अरुणाचल का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है, जो चाइना की ओर देखे। यह भारतवर्ष का हिस्सा है और भारतवर्ष का ही बेटा है। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि समय कम है। मैं पालियर्यामेंट में दोबारा चुनकर आया हूँ।

उस पार बैठकर हम भी चिल्लाते थे लेकिन उस चिल्लाहट में कोई गहराई नहीं है। उस पार बैठकर हम भी बहुत हल्ला करते थे, लेकिन इस बार रूरल इंडिया के दिल में, आंखों में कानों में मोदी जी की आवाज गूंजी। उस आवाज़ में सबका साथ था, सबका विकास था, उस आवाज में सबका विश्वास था इसलिए हम दोबारा यहाँ चुनकर आए हैं।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्यों में एक स्टेट है इसमें से आप लोगों में से भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? जब भी मुझे परिचय देने का मौका मिलता है, तो लोग पूछते हैं, आप शिलाँग से हैं न? मेरा कैपिटल इटानगर है। हम परिचय से वंचित थे। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वंचित थे। आज़ादी के 70 वर्षों के पश्चात् मोदी जी के आने के बाद आज मेघालय में रेलवे की क्या स्थिति है, त्रिपुरा में रेलवे की क्या स्थिति है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम दो साल के बाद रेलवे के नक्शे में जुड़े हैं। इसलिए मोदी जी को मैं भगवान के अवतार के रूप में देखता हूँ। लुक ईस्ट पॉलिसी यू.पी.ए.सरकार ने दी थी, मोदी जी ने कहा कि लुक ईस्ट से नहीं होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम रेलवे से जुड़े। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आधार पर पहली बार गुवाहाटी से मुझे अपने होम टाउन पासीघाट में फ्लाइट से लैंडिंग करने का मौका मिला। जो सपना हमारे फोरफादर्स ने देखा था, वह सपना मोदी जी ने पूरा किया है।

(1600/SJN/VR)

ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बोगीबील ब्रिज है। पहले हमें डिब्रूगढ़ मेडिकल जाने के लिए दो घंटे लगते थे, लेकिन मैं अब नौ मिनट में डिब्रूगढ़ पहुंचता हूं। इसमें अलूबारी ब्रिज, दिबांग ब्रिज जुड़ा। यह केवल पब्लिक के लिए नहीं है, यह सीमा सुरक्षा और देश के हित में भी है। उसी पुल से हमारी मिलिट्री जाती है, उसी पुल से आर्म्स और एम्युनिशन जाता है। हम बिना हथियार के भारत वर्ष की रक्षा के लिए खड़े थे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री पेमा खांडू जी हैं। He has been declared the youngest and the most performing Chief Minister. ऐसे एक प्रॉमिसिंग लीडर के साथ आज अरुणाचल प्रदेश है और आने वाले कल में पेमा खांडू जी भारतवर्ष के एक नंबर के मुख्य मंत्री बनेंगे। यह केवल कहने से नहीं होता है। चाइना बार्डर में नरेन्द्र मोदी जी ने सिलेंडर पहुंचाया है। ऐसी बहुत-सी मां-बहनों के दिल में, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, सिलेंडर को पकड़ते हुए, हाथ कांपते थे। यह मोदी जी ने वहां भेजा है। यही सपना था, 'अंत्योदय' का जिसमें हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज चाइना बार्डर तक सिलेंडर पहुंचाया है और मेडिकल सिक्योरिटी दी है। उन्होंने टेलीकॉम और एयर सर्विस में बहुत से काम किए हैं।

सभापति महोदय, मैं मोदी जी के बारे में अंत में कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में जब भी अत्याचार होता है, शायद मोहम्मद पैगम्बर ने इंसान के रूप में इनको भी इस दुनिया में भेजा है। जब-जब इस दुनिया में अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, तब-तब शायद राम जी को भी इंसान के रूप में आना पड़ता है। मैं मोदी जी को भी उस रूप में देखता हूं। आने वाले कल में भारत को आगे लाने के लिए…(व्यवधान)

(इति)

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर):

* Laid on the Table

1602 बजे

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने प्रेसीडेंट साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया है। ऐसी बात नहीं हैं कि प्रेसीडेंट साहब के अभिभाषण में कोई अच्छाई नहीं मिली, खाली अपोज़ीशन उसकी बुराई करे। ऐसी बात भी नहीं है कि सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, अपोज़ीशन कुछ भी न बोले। लेकिन हमको देखना है कि हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आज मॉब लिन्चिंग का जो हाल हुआ है, कल यहां पर लोगों ने कहा था कि अगर भारत में रहना है, तो भारत माता की जय नहीं, बल्कि यह कहिए…(व्यवधान) मेरा सिर्फ यह कहना है…(व्यवधान) मैं पुराना हूं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूं। यह मेरा 11वां साल है। यह थर्ड टाइम है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि –

ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
हम लाए हैं, तूफान से किश्ती निकालकर,
इस देश को रखना मेरे भाइयो संभालकर॥

इस देश को बचाइए। देश कहां जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप इधर देखकर बोलिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्या यह देश सिर्फ जय राम, श्रीराम से ही बचेगा? क्या वन्दे मातरम् से ही बचेगा? तो दूसरे लोग कहां जाएंगे?…(व्यवधान) मैं यह कहा रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास आपने कहा, सबका विश्वास। मॉब लिन्चिंग की जो हालत शुरु हुई है, इस मिनिस्ट्री के आने के बाद, क्या सबका विकास, सबका साथ इसी का नाम है? क्या मोदी जी यही देना चाहते हैं? अगर यही है, तो क्या आप इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे? मैं बहुत से पुराने साथियों को देख रहा हूं जो दस साल और पांच साल से मेरे साथ थे। वे उस तरफ थे। जो आज नहीं हैं, जिन्हें मोदी जी ने टिकट भी नहीं दिया है, क्योंकि इन लोगों ने नफरत की हवाएं फैलाई थीं।

आज जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे मोदी जी से उम्मीद है कि आइन्दा उनको भी टिकट नहीं देंगे।...(व्यवधान) और मॉब लिन्चिंग वालों को इंसाफ मिलेगा...(व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात यह है कि मुसलमान मां-बहनों का मजाक उड़ाने के लिए तलाक का मसला उठाया जाता है।...(व्यवधान) इस्लाम खालिस मज़हब है, इसको कुरान के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए।...(व्यवधान)

1604 बजे

(श्रीमती रमा देवी, माननीय सभापति पीठासीन हुईं।)

महोदय, अगर इनके अंदर शर्म है, तो ये उन बच्चियों...(व्यवधान) तलाक का 68 प्रतिशत मसला हमारे हिन्दू भाइयों और हिन्दू बहनों में हैं। 24 प्रतिशत, 23 प्रतिशत मुसलमानों में और दूसरे जो लोग हैं, हमारी वे बहनें हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। आप ज़रा उनकी भी फिक्र करें।

(1605/GG/SAN)

वे बहने हैं, जिनको तलाक के बुरे कामों में छोड़ दिया जाता है, सैक्स वर्कर बना दिया जाता है। उनकी भी ज़रा चिंता करें। 777 लोगों पर तलाक का केस है, इतना बड़ा बावेला मचा दिया, यह मचाने की जरूरत नहीं है। इस मसले को बैठ कर हल करें। मुसलमानों का मसला ऐसा है, हम लोग अपने कुरान और हदीस की रोशनी में इसको हल करना जानते हैं। ...(व्यवधान) मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए नहीं, मैं स्पीकर साहब से बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो संजीदा लोग खड़े हों, उनके साथ संजीदा बात करें। ...(व्यवधान) इस देश को शहीद भगत सिंह ने आज़ाद कराया। इस देश को अशफ़ाकुल्लाह खाँ साहब ने आज़ाद कराया, राम प्रसाद बिस्मिल ने आज़ाद कराया, चन्द्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद कराया, सुभाष चन्द्र बोस ने आज़ाद कराया। आज का जो हाल है, ऐसा लगता है कि इस मुल्क को किसी ने आज़ाद ही नहीं कराया है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से अपने असम की बात पर आना चाहता हूँ। असम की मसाइल में जो कुछ आप देख रहे हैं, वहां इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। दो ही इंडस्ट्रीज़ थीं, वे हमको मिल नहीं रही हैं। दोनों इंडस्ट्री, पेपर मिल बंद कर दी गई हैं। मैडम, फ्लड और इरोज़न पूरे असम के लिए प्राब्लम बना हुआ है। उसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान देंगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

(इति)

1606 बजे

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनका जो वक्तव्य और भाषण था, उस भाषण में जो सारी बातें बताई गईं, उससे लगता है कि एक नया भारत हमें देखने को मिलेगा। जो विकास की योजनाएं हमें देखने को मिली, मैं समझता हूँ कि उनसे हमारे देश के काफी लोगों को फायदा होगा। यह जो हमारी सरकार आई है, मैं खास कर के प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ योजनाएं ऐसी इस सरकार ने लागू की हैं जिससे आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सुविधाएं हुई हैं।

महोदया, मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। जो योजनाएं हमने यहां पर देखी हैं, खास कर यह जो उज्ज्वला योजना है, उसके बाद 'आयुष्मान भारत' योजना है, उसके बाद प्रधान मंत्री आवास योजना है, जन-धन योजना है, इन सारी योजनाओं को हमने देखा। हमने यह महसूस किया कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, खास कर के उज्ज्वला योजना में जो हमारी बहनें, हमारी महिलाएं बहुत परेशान थीं। एक तरफ उन्हें लकड़ी मिलती नहीं थी तो खाना कैसे बनाएं, लेकिन जब से यह उज्ज्वला योजना आई, ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जितनी भी बहने हैं, महिलाएं हैं, उनको काफी फायदा हुआ, यह मैं समझ सकता हूँ। मैं प्रधान मंत्री जी को खास तौर पर 'आयुष्मान भारत' योजना के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, मैंने बताया कि मैं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। जब यह योजना नहीं थी तो हमने देखा कि हमारे कई आदिवासी भाई-बहनों की जानें चली जाती थीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं था और बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन जब से यह 'आयुष्मान भारत' योजना आई है, उसमें पांच लाख रुपये तक का प्रावधान रखा गया है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे सारे आदिवासी और सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस योजना से ज़बरदस्त फायदा

हुआ है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूँ कि हमारे आदिवासियों को एक नया जीवन इस योजना से मिला है। यह मैं आज कह सकता हूँ कि इससे काफी फायदा हुआ है। मैं प्रधान मंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरी तो छोटी टैरिटरी है – दादरा और नागर हवेली, यूनियन टैरेटरी है।

महोदया, मैं वहां से 7वीं बार यहां चुन कर आया हूँ और मैं निर्दलीय चुन कर आया हूँ। मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी छोटी टैरेटरी है, मेरे प्रदेश की आबादी चार लाख है। प्रधान मंत्री जी दो बार वहां आए, दो बार उन्होंने दौरा किया। उस क्षेत्र में हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम प्रधान मंत्री जी किया है। नर्सिंग कॉलेज देने का काम किया, यूनिवर्सिटी देने का काम किया।

(1610/KN/SM)

महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा।…(व्यवधान) एक मिनट, ठीक है। हम एक-एक मेडिकल सीट्स के लिए यहाँ पर झगड़ा करते थे हेल्थ मिनिस्ट्री में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें मिली थीं। प्रधान मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज देकर हमें 180 सीट्स दीं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में सोचा और इतनी कृपा दृष्टि रखी।

अंत में, जब आपने एक मिनट दिया है, तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक ही चीज़ यहाँ पर रखूँगा। हम यूनियन टेरिटरी से आते हैं। यूनियन टेरिटरीज से हमारे यहाँ सारे सदस्य हैं। यूनियन टेरिटरीज में आज प्रजातंत्र नहीं है। हमारे यहाँ असेम्बली नहीं है। सारा कंट्रोल होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी एपेक्स बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है व जिला पंचायत है, उनको अधिकृत किया जाए, उनको अधिकार दिए जाएं। यहाँ पर गृह मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि सारी योजनाएँ लागू करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो।…(व्यवधान)

(इति)

*श्री शंकर लालवानी (इन्दौर):

* Laid on the Table

1611 hours

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Sir, thank you so much for giving this opportunity to share my view on the Hon. President's Speech. I congratulate and appreciate our Hon. President for quoting the great saying of Sree Narayana Guru Ji.

"Jaati- Bhedam Mat-Dwesham Adumilladey Sarvrum
Sodar-tvain Vaadunn Matrukasthan Maanit"

This great saying of Sree Narayana Guru Ji is really a welcoming one. I am appreciating the President's Address. I am anticipating that this Government would follow this practically.

I would like to emphasise my point on simultaneous elections mentioned in the President's Address. I strongly oppose this proposal because this is not a problem of practicality. This is a problem of accountability. Every Government should be accountable to the people and to the Opposition. But this proposal, I feel, has some hidden agenda to bring Presidential form of Government in future.

Our revolutionary leader Dr. B. R. Ambedkar gave priority to the accountability of the Government, not practicality, not stability of the Government. In the Constituent Assembly, this argument had happened. Baba Saheb Ambedkar and other leaders already argued and discussed about the stability of the Government. So, we need not talk about the stability of the Government; we need only accountability of the Government. This Government

is planning to bring in a Presidential form of Government. It is totally against the Constitution and the people. So, kindly consider my requisition to avoid or drop this attempt of simultaneous elections.

Our Hon. President spoke many things about the Government Schemes. But there is no scheme about the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So kindly, include the schemes for the upliftment of Scheduled Castes

of the nation who are nearly about 25 per cent of the total population.

Our Hon. President spoke about the ideal State. He quoted the saying of Tagore Ji –

"Where the mind of the people is without fear and the head is held high."

It is the ideal State. But everyday, there is a threat to the minority people, Scheduled Castes and women. There is no safety and security to the women in our nation. …(*Interruptions*)

(1615/CS/AK)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : जामयांग त्सेरिंग नामग्याल जी, अब आप बोलिए।

माननीय सांसद, आपकी बात हो गई है। नामग्याल जी, अब आप बोलिए। आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। नामग्याल जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए।

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): So, I would request this Government to bring honour …(*Interruptions*)

(ends)

1615 बजे

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे जम्मू-कश्मीर प्रदेश के अत्यंत दुर्गम एवं बर्फीले क्षेत्र लद्दाख के प्रतिनिधि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द कहने का अवसर और अनुमति प्रदान की है।…(व्यवधान)

DR. THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Madam, kindly allow him to conclude his speech. …(*Interruptions*)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Madam, please allow me to conclude my speech. …(*Interruptions*) This is my first speech. …(*Interruptions*)

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदया, आज भारत की आम जनता खुशकिस्मत और गौरवान्वित है कि आजादी के इतने वर्षों बाद देश में एक आम लोगों की सरकार बनी है। जहाँ आम किसान, मजदूर, दबे-पिछड़े, गरीब, लाचार, युवक-युवतियाँ, छात्र, ठेले वाले, छोटे व्यापारी जैसे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को पहली बार अपनी सरकार में अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में देखने का अनुभव हो रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गर्व महसूस करता हूँ और अपने क्षेत्र के निवासियों के आशीर्वाद से एक युवा होने के बावजूद भी मुझे इस सदन में खड़ा होने का जो मौका दिया, यह केवल मोदी जी की लीडरशिप में ही मुमकिन हो पाया है, इसीलिए नारा लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरे जैसे लाखों युवा, युवतियों को भी अब समाज और देश सेवा से जुड़ने की प्रेरणा मिलने लगी है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ भाव से समाज और जनसेवा की जा सकती है। इसका अनुभव हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल हम युवाओं को सिखाया, बल्कि खुद करके भी दिखाया है।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ और एक ही समय पर दो सदस्य नहीं बोल सकते हैं। हाउस का एक डिकॉरम है। आपने मुझे अनुमति प्रदान की है और मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए। मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदया, मेरे बोलने के समय पर वे खड़े होकर बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ?…(व्यवधान)

Madam, this is my maiden speech. यह मेरी पहली स्पीच है और ये उसे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं।…(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संचालित अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी सूची नहीं पढ़ूँगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा। मुझे वह दिन याद है जब लद्दाख के चांगथंग जैसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के एक बुजुर्ग नागरिक का जन-धन योजना के तहत पहली बार बैंक में खाता खुला। जब उनके हाथ में एटीएम कार्ड दिया गया, तो वे खुशी से रोने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका भी कभी बैंक में खाता खुल पाएगा। अब आज तक उन्होंने सपने में क्यों नहीं सोचा, यह एक डिबेट का मुद्दा है।

पिछले 55 वर्ष इस भारत राष्ट्र पर जिन्होंने राज किया, उन्होंने लद्दाख को आज तक नहीं अपनाया। मैं इस सदन को आपके माध्यम से याद दिला दूँ कि वर्ष 1965 के युद्ध के बाद जब अक्साई चिन उस तरफ चला गया, तो किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, जिसने आज तक लद्दाख वालों को डीमोरलाइज करके रखा। उन्होंने कहा था कि वहाँ तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। वहाँ केवल घास का तिनका ही नहीं, बल्कि सब जानते हैं कि वहाँ पश्मीना का उत्पादन होता है, वहाँ सोलर एनर्जी का स्कोप है, वहाँ जियो-थर्मल प्रोजेक्ट का स्कोप है, वहाँ आजकल टूरिस्ट बूमिंग पर है, वहाँ यूरेनियम है।

(1620/RV/UB)

इन सारी ऑपोर्च्यूनिटीज़ को अगर किसी ने जानने की कोशिश की है तो केवल नरेन्द्र मोदी जी ने ही की है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं, जो अपने पाँच साल के कार्यकाल में लद्दाख जैसे क्षेत्र में चार बार आए हैं। मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति जी, राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार के द्वारा सैनिकों के मनोबल और आकांक्षाओं को ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। आतंकवाद पर ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति के तहत सुरक्षा बलों को इससे निपटने की पूरी छूट दी गयी है।

महोदया, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है। इसके परिणामस्वरूप कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए के साथ-साथ राष्ट्र विरोधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके कारण पत्थरबाजी की घटनाओं में निरन्तर कमी आ रही है।

महोदया, 'मोदी है तो मुमकिन है।' वैसे तो वर्तमान सरकार ने देश के सभी हिस्सों के विकास पर समान रूप से ध्यान दिया है। परन्तु, जम्मू एवं कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्य पर विशेष ध्यान दिया है। आतंकवादी गतिविधियों पर रोक के लिए जहां स्थानीय युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं आतंक और हिंसा का सहारा लेने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जा रहा है।

सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश के अन्दर और बाहर के दुश्मनों और आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय सांसद श्री लोरहो एस. फोज़।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): माननीय सभापति महोदया, प्लीज़, मैंने अभी अपने क्षेत्र का मुद्दा चुना है। आपकी अनुमति से मैं इसे थोड़ा-थोड़ा टच करना चाहूँगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

महोदया, शिक्षा को संस्कार के साथ जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। भारत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। लद्दाख में यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां के दूर-दराज के लोगों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हो गया, आप बैठ जाइए।

(इति)

माननीय सभापति : माननीय सांसद श्री लोरहो एस. फोज़, आप खड़े हो जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़, शांत रहिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : लोरहो एस. फोज़ जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

[*]श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू):

[*] Laid on the Table

1622 hours

SHRI LORHO S. PFOZE (OUTER MANIPUR): Madam, I want to thank the hon. President for his Speech. The hon. President has given us a vision for New India, a vision for Young India…(*Interruptions*). I want to say that this is a time when we look at India with a perspective of peace and development. Madam, in the President's Speech, the hon. President, to a great extent, has given us a vision of peace and prosperity in the country.

Madam, I belong to the Northeast India, the State of Manipur which has been reeling under an ethnic crisis, fighting for identity and land for a long, long time. During the period when the UPA ruled, when the Congress ruled in the State of Manipur, there was a lot of crisis, a lot of turmoil, but with the coming of the NDA, the BJP-ruled Government, in the State of Manipur, we have seen peace and prosperity slowly creeping in since the year 2017. The Indo-Naga Peace Talks have been initiated and the Government of India has engaged with the NSCN (IM).

(1625/KMR/MY)

In the last three years, since 2015 when the Framework Agreement has been signed, the people in Manipur, the Naga people and the people in the North-East India have been looking forward to this Government with great hope because the Government has been given a massive mandate. We hope that this Government will deliver and bring peace even to our land.

There are times when we talk about unity in diversity. Unity in diversity is required because India is a land filled with multiple ethnicities, multiple groups. There is social instability that is cropping up in our country. That we need to live together in peace in the midst of diversity is of paramount importance because without loving one another we cannot look at one another and say that we will accept one another and bring in peace.

In the midst of this, Madam, I would also like to pick up a point from the Presidential Speech. Much has been said about climate change and global warming. We have heard that even in India one per cent growth in forest cover has been witnessed. However, on the ground, the North-East India is faced with the problem of deforestation to a great extent. Deforestation has been going on and this has caused a lot of climate change even in our very front yards too.

Madam, at this point I want to say that environment has become an issue of paramount importance. With the introduction of Ujjwala Yojana by the hon. Prime Minister and giving of gas connections to the women of our country, now the people no longer need to go out and cut down the forests for firewood, particularly in the in the mountain States of India. There are 11 mountain States in the Sub Himalayan region. I would suggest that as we continue to take on reforestation in our land, allocations for Ujjwala Yojana should be enhanced so that the womenfolk in the kitchen will not have demand for wood and firewood and that they will preserve their forests so that we once again can live with goodness, and the water crisis would be addressed. Thank you very much.

(ends)

[*]SHRI VINOD LAKHAMSHI CHAVDA (KACHCHH): I Support the Motion of Thanks on the President's Address. I support all the views in regard to Foreign Policy, Education Policy, Agriculture Policy and Public Sector Policy.

(ends)

[*] Laid on the Table

[*]श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी):

[*] Laid on the Table

[*]श्री जनार्दन मिश्र (रीवा):

[*] Laid on the Table

1628 hours

SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Bhagwant Mann in Punjabi,
please see the Supplement.
(PP 499-A to 499-C)}

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): इन्होंने एनडीआरएफ की चर्चा की है, जो पूरे भारतवर्ष में राहत पहुंचाने का कार्य करती है। क्या उस पर चर्चा करना उचित है? इसको प्रोसीडिंग से बाहर किया जाए। एनडीआरएफ पर एक डिबेट...(व्यवधान) यह एक अच्छी फोर्स है, जो राहत पहुंचाने का काम पूरे भारतवर्ष में करती है। ...(व्यवधान)

*SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU NARSAPURAM):

* Laid on the Table

(1630/SNT/CP)

1632 hours

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Hon. Chairperson, on behalf of the Sikkimese people and the SKM Party that I belong to, I express my sincere gratitude to the hon. President of India. His enlightening speech has made it clear that our nation is growing to greater heights. It is also clear that our nation will reach even higher in the coming days.

In every sector – economy, education, agriculture, fishing, skill development, health, urban and rural development and all other sectors – India is making huge steps further.

It is overwhelming to know through his Address that the Government has approved a separate Pension Scheme for small shopkeepers and retail traders. It means those shopkeepers in the rural and scarcely populated regions like our State Sikkim will have a sense of security.

The increase in the National Defence Fund for the children of our brave soldiers is a noble act. Further, inclusion of Police personnel in the beneficiary list of NDF is another noble act and an empathetic gesture by the Government.

Water conservation is an international agenda. Water scarcity is not just an issue for northern and southern plains of India. It has emerged to be a major issue for us living in the hilly areas of the northern and north-eastern areas of this great nation. The creation of Ministry of Jal Shakti is indeed a decisive step, the implementation of which will help us resolve this issue.

The proposed establishment of National Research Foundation will help our nation become self-reliant in modern technology. It will help us create our own indigenous technology for growth and development. We look forward to have NRF as soon as possible.

The decision by the Government to expand Khelo India Programme is a welcome step. To hunt for more sports persons like Bhaichung Bhutia, Mary Kom, Jayanta Talukdar, Shiva Thapa, Tarundeep Rai, Nirmal Chettri, Sanju Pradhan and many more, accessibility of training is a necessity. With expansion of Khelo India Programme, we hope optimistically to develop our sports facilities to the world class and make it more accessible to the youths of every class.

Bharatmala Project is one of the most important of its kind to be implemented. North-eastern region is known for its natural beauty and abundance but it is also known for its very poor connectivity. So, we look forward to and hope that with this Bharatmala Project the connectivity of our north-eastern region will be made better than ever before.

I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for being elected for consecutive second time with such a decisive mandate. I would also like to thank the hon. Chairperson for this opportunity.

(ends)

(1635/SK/RK)

1635 बजे

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति जी, यहां अभी एक सांसद महोदय ने कहा कि 300 चुनकर आए हैं तो 300 मिनट लेंगे, आप चार चुनकर आए हैं तो चार मिनट लेंगे। मैं महाराष्ट्र से इंडीपेंडेंट चुनकर आई हूं तो क्या मुझे सिर्फ एक मिनट ही मिलेगा? हम यहां सरकार के सामने देश की और अपने राज्य की समस्या को लेकर बात करने आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में 14 लाख का टार्गेट दिया गया है, टार्गेट देकर तीन वर्षों में इसे पूरा करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 22 लाख का टार्गेट दिया है जो कि पूरा करना है। मैं महाराष्ट्र से बिलांग करती हूं, यहां महाराष्ट्र के एमपीज़ बैठे हैं, सिर्फ सात लाख का ही टार्गेट दिया गया है।

मैडम, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जैसे यूपी को 14 लाख और मध्य प्रदेश को 22 लाख का टार्गेट दिया गया है, महाराष्ट्र को भी 22-25 लाख घरों का टार्गेट प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलना चाहिए।

निराधार, श्रवण बाल योजना में केंद्र सरकार 200 रुपये की सहायता देती है और राज्य सरकार 400 रुपये सहायता देती है। मैडम, आप एक मां हैं, जिसका बेटा बोल नहीं सकता, जिसका बच्चा सुन नहीं सकता, जो व्यक्ति निराधार है, जो बुजुर्ग 65 साल पूरे कर चुका है, उसे केंद्र सरकार 200 रुपये देती है और राज्य सरकार 400 रुपए देती है। अगर 600 रुपये में वह एक महीने में गुजारा कर सकता है तो क्या हमें यहां बैठने की जरूरत है? अगर हम दिन में चाय की काउंटिंग करें तो 20 रुपये दिन के बनते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह चाय भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकती।

मैडम, माननीय प्रधानमंत्री किसी एक पक्ष के नहीं हैं, सभी पक्ष के हैं। हम सबके लिए हर मुद्दा बहुत महत्व रखता है। निराधार, श्रवण बाल में जितने भी लोग आते हैं, बेरोजगार, निराधार, डम्म, डैफ, विडोज़ को महीने में 2000 रुपये मिलें। मेरी इतनी विनती आप सबसे है।

इसके साथ ही मैं सभी सीनियर सांसदों से विनती करती हूं, हम सब यंग हैं, युवा पहली बार चुनकर आए हैं, आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा है। आप लोग अपनी ब्लैसिंग्स और एक्सपीरियंस हमारे साथ रखें, ताकि हम अपने क्षेत्र और राज्य का विकास कर सकें। हम इतनी ही अपेक्षा आप लोगों से करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद

(इति)

*SHRI BALASHOWRY VALLABBHANENI (MACHILIPATNAM):

* Laid on the Table

1638 बजे

श्री अरविंद धर्मापुरी (निजामाबाद): माननीय सभापति जी, यह मेरी पहली स्पीच है, थोड़ी दया कीजिए।

I am privileged to support the Motion of Thanks on the hon. President's Address moved by Shri Sarangi ji. Hon. President's Address has illuminated on India's progress attained in diverse fields in the past five years and challenges for the immediate future.

The House has witnessed scores of Addresses from Presidents of their respective times. Perhaps this is the only Address which reflected the true progress made by a Government rather than it being a bundle of papers chanting undelivered and impractical promises.

We stood tall on the global platform with indigenous strength. We have witnessed tangible output from every sector of the economy. It would be complete leap of faith if I say that these accomplishments have happened as simple as said. There was staged criticism, orchestrated protests, unconventional political amalgamations, selective campaigns, anti-national propaganda and every caustic exercise under the sun to derail the Government and hon. Prime Minister Modi ji in particular. These were there from every corner of the country but the Government battled every stage of this corrosive environment and evolved into productive mode which made us stand where we are now. But the propagandists, while performing these inappropriate stunts have not realised that the mighty common man is watching them with his eyes wide open.

(1640/PS/YSH)

What happened next? They had come out in large numbers like never before, stood under the scorching sun in long queues and wielded their weapon, that is, their votes. Women, as said by the hon. President, came out in numbers equal to men and clearly have given their mandate. I say this with utmost pride that my parliamentary segment has significantly more female voter turn-out than male voter turn-out. I am here today because of this reason. To be precise, it was about 1,10,000 more women voters who have casted their votes in my segment than men. The reason behind is this. The Pradhan Mantri Awas Yojana, aimed at providing houses for poor, is a marvel as it caters to the primitive need of every person to have a comfortable living space.

Women are worshipped in our country as deities. She is the spine of her family. To have her lead a life with self-respect and security, is our collective responsibility. We have witnessed as to how the phenomenal Swachh Bharat enriched the self-respect of daughters, sisters and mothers. But women of my State are denied of such self-respect when funds allotted under this scheme, are diverted to other flagship schemes of State Government, as per the C&AG report.

With ever rise in prices of land and construction materials, it has become impossible for the poor and the low-income groups to aspire for a house of their own. The Central Government has been performing this humungous task of building houses for the poor in the country with great vigil. I have recently come across from various credible news sources that the Government might consider,

if feasible, a new housing rental plan in crowded metros for the migrant workers having income below Rs. 3 lakh. Having lived in a metro for a long time, I have come across thousands of migrant workers sleeping on the footpaths, in public gardens and at railway stations in harsh climatic conditions. This kind of an understanding of every micro aspect of life and addressing its problems, has probably made our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, dear to people of this nation. Providing every poor person of this nation with a *pucca* house by 2022 is possible as addressed by the hon. President with collective efforts of States and Centre, unlike my State which is immune to the aspirations of people to have a house of their own.

Now, I come to Ayushman Bharat Scheme. The world's largest health insurance system is a boon to millions of families where medical expenses are costing life-long savings of individuals. Unfortunately, a few States, one being my State of Telangana, has not opted for this scheme. The reasons, like political hegemony issues, vested interests and of course, sedimented apathy towards the poor people's lives are apparent. I seriously cannot contemplate how parties prioritize ego; ego over people who trusted and elected them.

(ends)

1643 hours

SHRI PRAJWAL REVANNA (HASSAN): Hon. Chairman, I am thankful to you for giving me an opportunity to make my maiden speech. I want to bring in some issues of Karnataka which my mentor, Shri H.D. Deve Gowda, had also been presenting down the years.

Today, in more than 120 *talukas* or constituencies in Karnataka, we are facing drought situation. We are also dealing with the problem of providing drinking water. I do agree today that our Tamil Nadu friends, who are present in this House, are also asking the same question and are raising the same issue. I am not asking them or requesting them. On a humanitarian ground, I wish to bring it to the notice of this House that we are facing a real problem. The people of Mandya district have gone on a hunger strike. They are not able to repay the bank loans. That is the reason why a lot of farmers are committing suicides. From the same district, which I have just mentioned, around 1600 farmers have committed suicide in just a matter of a year. So, we should understand this problem.

The hon. Minister, Shri D.V. Sadananda Gowda, who is from my State, is also present here. Shri D.V. Sadananda Gowda Ji, you should also consider this matter and kindly allocate us 2 tmc of water in an immediate requisition in order to help the farmers and to provide drinking water to the people which is rightfully needed right now.

(1645/SNB/RPS)

Sir, I would like to bring these issues to the notice of this august House. I would like to specifically mention about my parliamentary constituency, namely, Hasan in Karnataka where presently we are drawing dead water for both drinking and usage by farmers. Today the farmers of my State are in pathetic situation. I would like to request all sections of the House to consider this issue as a humanitarian issue and there should be no politics in this matter.

I am a 28 years old boy who has got elected from Hasan district in Karnataka. I would like to mention here that if I have said anything wrong here then I am really sorry about it. I want to work as a good parliamentarian.

Sir, I would also like to mention here that let us not play dirty politics here by saying that Karnataka has the most corrupt Government in the State. Let us not mislead the House. I want to say this because one of the hon. Members here mentioned this. Let us not mislead the House. When the BJP Government was ruling the State from 2008-13, there were charges …(*Interruptions*) You have raised the issue here. The IMA was raised here by my colleague here. *… (Not recorded)* A senior most member of the Congress party …(*Interruptions*) Investigation in the matter is going on and we have already suspended the party member …(*Interruptions*) I would like to point out here that in 2009 Shri Santosh Hegde was the Lokyakuta of Karnataka and he gave a report that 14 Ministers including the CM …(*Interruptions*) Thank you.

HON. SPEAKER: Please calm down.

(ends)

*श्री भगीरथ चौधरी (अजमेर):

---

* Laid on the Table

1648 बजे

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

"तमाम चेहरों पर खौफ दिखाई देता है, एक चिराग अंधेरों पर भारी दिखाई देता है।"

अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण की शुरूआत में ही इस स्पष्ट बहुमत का उल्लेख किया – अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, यह जनादेश भी और यह विजय भी। इसी जनादेश और विजय के रहते, मैं भारत की जनता को, उनकी राजनैतिक सूझ-बूझ का, उनके राजनैतिक चातुर्य को प्रणाम करती हूं। उन्होंने प्रधान मंत्री जी के अंदर उस विराट नेतृत्व-शक्ति को पहचाना, जिसके लिए मैं भारत की जनता का आभार प्रकट करती हूं। यह जनादेश वस्तुत: सामूहिक स्वप्न और आकांक्षाओं की एक अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति से एक तरफ जहां हम सब को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी का भी आभास हुआ है और इस जिम्मेदारी के प्रति हम भलीभांति सचेत हैं। हम मानते हैं कि जनता जब आशीर्वाद देती है, वह आगे आपसे यह अपेक्षा रखती है कि आप उसके प्रति सेवा का भाव रखेंगे और अपनी सम्पूर्ण नेतृत्व-शक्ति को, क्षमताओं को, उनको समर्पित करेंगे।

(1650/RAJ/RU)

इस गरिमामयी सदन से मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी को उनके अतुलनीय नेतृत्व के लिए और अमित भाई को उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के लिए सभी लोग मिल कर बधाई दें।

I would like the august House to congratulate our illustrious Prime Minister for leading us from the front and Shri Amit Shah, as the Party President, who works so hard and is known for his organisational skills. We must congratulate them for leading us from the front and making this victory happen.

यह जीत पूर्णत: उनकी नीतियों की, उनके नेतृत्व की और उनकी व्यक्तिगत ऊर्जा की है, मुझे लगता है कि यह सदन मेरी बात से सहमत होगा।

अध्यक्ष जी, एक सौ तीस करोड़ लोगों को और उनकी आकांक्षाओं को अपने कंधे पर ढ़ो कर सबलतापूर्वक उसका निर्वहन करना कोई साधारण बात नहीं है!

नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है
नब्ज़ नब्ज में बिखरना कमाल होता है
बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं
बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।

जब हम सभी लोग प्रधान मंत्री जी का गुणगान करते हैं तो मुझे मालूम है कि कुछ हमारे विपक्ष के मित्र उससे बहुत चिढ़ जाते हैं। हम सभी यहां जनता द्वारा चुने हुए हैं और जनता की आकांक्षा है कि हम अपने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करें, इसलिए हम तो बोलेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी के विचारों से करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। 19वीं शताब्दी के एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स का कहना है कि "If your actions inspire others to dream more, to learn more and do more and become more, you are a leader."

ये सब नेतृत्व की क्षमताएं, आज पूरे भारतवर्ष को नहीं, बल्कि विश्व को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी में दिखाई देती है। उन्होंने दूसरों को अधिक सपने देखने की शुरुआत कराई। उनसे सीखने की, सपना देखने की, कुछ कर गुजरने की और कुछ बनने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व ने उन्हें अपना लीडर माना है। हम सभी लोग देश की दशा और दिशा बदलने के लिए समर्पण भाव से इस सभा में आए हैं और यह अवसर प्रदान करने के लिए उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरे भाई भगवंत मान जी चले गए। वह कह रहे थे कि किसी ने योगी का तो किसी ने कुछ की बात बताई है। मैं गीता पद पढ़ कर बताना चाहती हूं :

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।

इसका अर्थ है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सहज भाव से करो, सम्भाव से करो, बिना सफलता और असफलता का विचार किए और कर्म में ही रत रहो, यही योग है। योग आप सभी के सामने है। योग सिर्फ योग दिवस पर नहीं, बल्कि जीवन में योग कैसे किया जाता है, वह हमारे सामने एक उदाहरण है। प्रताप सारंगी जी ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री जी के प्रति जो भी भावना व्यक्त की, उनके उद्गारों पर बहुत लोगों को बहुत विपत्तियां हुई। थोड़ी देर में, मैं उस विषय पर आऊंगी। …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया था कि मेरा समय अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं उपलब्धियों का जिक्र नहीं करूंगी और मूल दर्शन का भी जिक्र नहीं करूंगी। राष्ट्रपति जी ने किन-किन विषयों पर बात की – कृषि में क्या उपलब्धि हुई, सड़कें कितनी बनी, 'सागरमाला' में क्या हुआ, 'मुद्रा' में क्या हुआ, इस देश के गरीबों का स्तर कैसे बढ़ा, मैं तमाम चीजों की बात नहीं करूंगी, लेकिन उनकी बात नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि वहां काम नहीं हुआ, बल्कि वे बात नहीं करने का मतलब है कि वे सब बातें पूरा देश और जनता जानती है। जब वे सब बातें जनता जानती है। …(व्यवधान) मैं आखिरी वक्ता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपके बाद भी बहुत बोलने वाले वक्ता हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): मेघवाल जी से मेरी बात हुई है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं चेयर पर हूं, मेघवाल जी चेयर पर नहीं हैं।

(1655/NKL/IND)

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): मैं आपको आंकड़ों से बोर नहीं कर रही हूं। उनके 55 साल और हमारे पांच साल हैं।…(व्यवधान) मैं ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन और साइकोफेंसी का जो अंतर है, वह जरूर बताना चाहूंगी। मैंने राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना और उतने ही ध्यान से मैंने अधीर रंजन जी का भाषण भी सुना। अधीर जी ने जब बात की, तो मुझे लगता है कि सोच, बुद्धि, तर्कशक्ति तब पथरा जाती है, यदि कोई चापलूसी करने पर बहुत मजबूर हो जाए।…(व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN):

* Laid on the Table

1656 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Presidential Address.

Sir, you may kindly see, I have already moved 40 amendments to the Motion moved by Shri Pratap Chandra Sarangi*ji.* I am not seeking division and also not speaking on the amendments. So, I may be permitted to speak for five to six minutes.

Sir, this is the first speech of the hon. President during the 17th Lok Sabha and also the first Presidential Speech of the NDA-II Government. The Presidential Speech always speaks about the policy initiatives and directives of the Government. What the policy initiatives and directives of the Government to be implemented during the coming five years are going to be, is the prime motto of the Presidential Speech in the Parliament. We were very eager to hear the Presidential Address but it is quite unfortunate and disappointing to note that the entire Presidential Speech was regarding the so-called achievements of the five years of NDA-I. There was no mention about the programmes and the policy directives which are to be pursued in the coming five years. This is totally disappointing. This is merely announcing the so-called achievements of the last five years of NDA Government, which is being repeated everyday by the hon. Prime Minister as well as the leaders of the BJP outside the House. It is only the repetition of the so-called achievements, that too against the ground realities and known facts.

Sir, I am confining my speech to Para 8 and Para 12 of the Address of the hon. President. In Para 8 of the Speech, the hon. President said and I quote – "In order to take the country out of a sense of gloom and instability, prevailing before 2014, the people have elected a new Government in 2014." In Para 12 of the Speech, the hon. President has gone to the extent of saying that "The foundation for the nation-building process was laid in the year 2014." Sir, this is really a strange and disappointing statement on the part of his Excellency, the President of India. That means, the NDA-II Government is ignoring all the achievements of the six years, that too during the last six years, of rule by the BJP Government led by Atal Bihari Vajpayee*ji.* It is totally being ignored.

Sir, from 1950 to 2014, if you examine, from Pandit Jawaharlal Nehru to Dr. Manmohan Singh via Vajpayee*ji* and Morarji Desai*ji,* have they done nothing for building up this nation? Was no stone laid for the nation building process? Absolutely, according to me, the statement of the hon. President *… (Not recorded)* is a disrespect to all our predecessors who were the architects of modern India.

Sir, when you talk about the journey of development which was started in 2014, what development do you talk of? The last five years have witnessed the largest number of farmers' suicides in the country. Two, the last five years have provided the lowest economic growth in recent years. Three, it is the period which has witnessed the highest unemployment rate of 6.1 per cent in the country, which is the highest in the last four and a half decades of independent India. Four, this is the period in which the judiciary has raised the concerns about the undermining of their independence. Five, this is the period in which the credibility of the Central Bank of the country, that is, the Reserve Bank of India, has suffered very badly.

(1700/KSP/VB)

My sixth point is that this was the period in which the independent investigating agencies were being misused recklessly to target the political opponents.

The last and the seventh point is that this was the period in which the minorities in the country had suffered very much. Their safety and security were under big threat. Is this the national building process? Is this the path of growth and development?

So, I would like to appeal to the Government to please have the courtesy of tolerance and accept others and their contribution in building the nation. I appeal to the Government to be nation-centric and not to be individual-centric.

(ends)

*SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR):

---

*Laid on the Table

1700 बजे

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आपकी नई जिम्मेवारी के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ भी देना चाहता हूँ।

आज मेरा सौभाग्य है कि मैं 17वीं लोक सभा में पहली बार बोल रहा हूँ। मैं इस अवसर के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विशेष रूप से हज़ारीबाग की जनता और हज़ारीबाग के कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर कुछ बातों को कहने का मौका दिया।

हम जितने भी माननीय सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक प्रतीक हैं। एक ऐतिहासिक जनादेश के हम प्रतीक हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यह जो ऐतिहासिक जनादेश है, उसके बारे में मैं संक्षेप में एक-दो आँकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

एक बात, जो हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए थी, वह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो वोट शेयर मिला, वह 31.3 पर्सेंट था। 2019 में हमें जो जनादेश मिला, उसमें हमारा वोट शेयर 37.4 पर्सेंट है। अगर हम एनडीए की तरफ देखें, तो एनडीए का वोट शेयर 2014 में 38 पर्सेंट था और इस बार 2019 में 45 पर्सेंट है। अगर हम इतिहास में जाते हैं और पूछते हैं कि कब कोई सरकार ऐसे एक ऐतिहासिक जनादेश के साथ वापस लौटी है, तो हमें 1971 में वापस जाना पड़ता है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं। उसके लगभग 50 साल के बाद एक सरकार को इस प्रकार का एक ऐतिहासिक जनादेश मिला है।

जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। हर बार जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जब वे विचार करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे देश में एंटी इनकम्बेंसी है। 50 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि इस देश में प्रो-इनकम्बेंसी है। इस

ऐतिहासिक जनादेश ने प्रो-इनकम्बेंसी करके दिखाया है। लेकिन ये आँकड़े हैं। अगर इन आँकड़ों को छोड़कर हम जमीनी हक़ीकत को समझने की कोशिश करें, तो हमें वोटर्स के पास जाना चाहिए। हमें वोटर्स से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमें वोट क्यों दिया।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि मैं हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ। यह एक ग्रामीण और पिछड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र है, झारखण्ड का संसदीय क्षेत्र है। जब मैं दौरा करता हूँ, तो हमें जंगलों और झाड़ों के बीच जाना पड़ता है। चुनाव के दौरान, मैं केरेडारी प्रखण्ड से पिपरवार जा रहा था। यह रास्ता जंगलों के बीच करीब 20 किलोमीटर का है। सड़क अच्छी है। हम लोगों ने बहुत अच्छी सड़क बना दी है। चकाचक सड़क है। लेकिन यह जंगल का रास्ता है। करीब 10 किलोमीटर जंगल के अंदर दूर में मुझे एक महुआ का पेड़ दिखाई दिया। महुआ के पेड़ के नीचे एक मूलवासी महुआ को चुन रही थी। ...(व्यवधान) मैं उनके पास गया क्योंकि मैं इन सब चीजों में या जो आर्थिक मामले हैं, उनमें मैं बड़ी रुचि रखता हूँ। मैंने उनसे पूछा- दीदी, आप महुआ चुन रही हैं, आप सुबह में कितने बजे से यहाँ पर महुआ चुनना शुरू किया? उन्होंने कहा- हम बड़ी भोरे आए हैं। चार बजे सुबह से हम महुआ चुन रहे हैं। हमने दो बोरी महुआ भर दिया है, इससे हमारी अच्छी कमाई होगी। फिर हमने कहा- दीदी, बताइए कि आप वोट केकरा देबो? दीदी ने बोला कि वोट तो मोदिया को देबो। वोट मोदिया के देबो और कोई नईखे बा।

जब हम आम जनता के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो जो जमीनी हक़ीकत है, जो जमीन पर काम किया गया है, वह हमें एहसास होता है, वह महसूस होता है।

(1705/PC/SRG)

अध्यक्ष महोदय, सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहुत लंबी चर्चा चली है। हमारे विपक्ष के कई साथियों ने कहा है कि उन्हें लगता है ज़मीन पर वास्तविकता में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं सबसे निवेदन करता हूं और निमंत्रण देता हूं कि आप हज़ारीबाग आइए। हज़ारीबाग और पूरे झारखंड में आपको नज़र आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने विकास को धरातल पर उतारा है। हमने विकास को धरातल पर उतारा है, जो अतुल्य, अद्भुत और अटूट विश्वास जनता और

माननीय प्रधान मंत्री जी के बीच बन गया है, उसी के कारण हमें यह ऐतिहासिक जनादेश मिला है, यह प्रो-इनकमबेंसी हुई है।

बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी है, वे प्रचार के दरमियान इस प्रो-इनकमबेंसी को छोड़कर नेगेटिव कैंपेनिंग में लगे हुए थे। मैं उन्हें रहीम का एक दोहा बताना चाहता हूं:

बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय॥

आप जब दूध को फाड़ देंगे, जब आप बिगड़ी हुई बात करेंगे, तो आपको कोई माखन नहीं मिलेगा। इस बार जो परिणाम आपको सहना पड़ा है, वही आपको मिला है, क्योंकि बिगड़ी हुई बातों से काम नहीं होता है, विकास से काम होता है। …(व्यवधान) इसलिए हम लोगों को यह ऐतिहासिक जनादेश मिला है। कल हमारे विपक्ष के साथी माननीय अधीर रंजन चौधरी ने कई बातें रखीं, उन्होंने अभद्र बातों का उपयोग किया। पूरे चुनाव के दरमियान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बहुत अभद्र बातें कीं। …(व्यवधान) उसका परिणाम उन्हें झेलना पड़ा। …(व्यवधान) इसलिए जो प्रो-इनकमबेंसी थी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन गालियों को गहना बनाकर सकारात्मक सोच से जो विकास किया, उस कारण हम लोगों को यह जनादेश मिला है। इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास' का जो हमारा मूल मंत्र था, वह मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' ही नहीं, 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' भी बन गया है। यह विश्वास हम लोगों ने इस जनादेश में देखा है। इस जनादेश के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम एक न्यू इंडिया को बनाना चाहते हैं।

मुझे बड़ा दुख हुआ, जब कल मैंने पढ़ा कि माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा है कि वे एक ओल्ड इंडिया चाहते हैं। …(व्यवधान) यह अखबारों में निकला था। …(व्यवधान) वे एक ओल्ड इंडिया चाहते हैं, इसी ओल्ड इंडिया में - माननीय सांसदगण आज 25 जून है - इमरजेंसी हुई थी, …(व्यवधान) इसी ओल्ड इंडिया में हज़ारों सिखों का कत्ल हुआ था, …(व्यवधान) इसी

ओल्ड इंडिया में भ्रष्टाचार हुआ था। …(व्यवधान) ये कौन सा ओल्ड इंडिया चाह रहे हैं? …(व्यवधान) हम एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। …(व्यवधान) जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था –

"Where the mind is led forward by Thee,
into ever widening thought and action;
Into that heaven of freedom, my Father,
let my country awake!"

That is the new India; that is the new India we are fashioning; that is the new India we are shaping; that is the new India the hon. Prime Minister and all of our senior leaders are building.

With these words I conclude.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी।

***श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महोदय ने अपने अभिभाषण में संपूर्ण राष्ट्र के समग्र वकिास के बारे में बिस्तार से वर्णन किया। एक ताकतवर राष्ट्र की मजबूत नींव रखने का काम पिछले पांच साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे हम युवा की बात करे, चाहे हम महिलाओं की बात करें। हर क्षेत्र से अबकी बार लोक सभा में चुन कर आए सांसद पूरे भारतवर्ष की जो तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है वो दर्शाता है कि भारत में विविधता में एकता है और ये संभव हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवासियों के मन में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाव घर कर गया। मैं हरियाणा की सिरसा लोक सभा से चुनी गई हूँ। लोगों के मनोभाव में एक ही बात थी कि क्या आपको वोट देने से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगें। आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री में जनता का विश्वास है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं को इतनी संख्या में प्रतिनिधित्व इसी सरकार में मिला। अंत्योदय के तहत आज अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आशा की दृष्टि से सरकार की ओर देखता है कि उसके जीवन में पिछले 5 साल में जो बहार आई है अगले पांच सालों में वो सुंदर मानसून का रूप ले लेगी। "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय:, सर्वे भद्राणि पश्चन्तु, मा कश्चति दुख भाग्भवेत।" आज ये मन:स्थिति समस्त भारतवर्ष के लोगों की बन रही है। पिछले 70 सालों में लोगों ने भ्रष्टाचार के विभिन्न-विभिन्न प्रकार रूपों को देखा पहली बार लोगों के मन में राजनीति और राजनेताओं के लिए आदर सम्मान की भावना इस कदर जाग्रत हुई है, जो कि पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। आज युवा पीढ़ी में, महिलाओं में भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इच्छा जाग्रत हुई है। प्रताप सारंगी जी ने हर भाषा में पूरे मनोभाव से सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की संस्तुति की। मैं सदन का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस ऑगस्त हाउस की सदस्या हूँ।

---

* Laid on the Table

मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि अपोजीशन को सद्बुधि प्रदान करे कि वो देश के विकास में सहयोग करें क्योंकि आफटर ऑल उनमें भी उस प्रभु का ही अंश है। जैसा श्री प्रताप सारंगी जी ने कहा- "या देवी प्रदानार्ति हरे, प्रसीद प्रसीद देवी, मार्तजगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी, याहि विश्वं तवमीश्वरी देवी चराचरस्य।" महोदय, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप पहली बार चुन कर आए सांसदों को भी भरपूर मौका संसद में अपनी बात रखने का देते हो। धन्यवाद।

(इति)

*SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): I would like to bring the following few lines on the Motion of Thanks on the Hon'ble President's Address in the Parliament for your kind perusal and consideration.

The Hon'ble President set the vision and action plan for the country for its overall development in all spheres by mentioning that "where the benefits of development reach every region and the last person standing in the queue" as the goal of development.

In this context, I would like to mention that post bifurcation, my State, Andhra Pradesh is crippling under severe agrarian and economic distress. The State of Andhra Pradesh is experiencing (i) lack of Infrastructure, (ii) is not having a full-fledged capital city, (iii) higher educational institutions have not been established in their full form and (iv) No new Industries, which generate economic growth and employment opportunities.

Our YSRCP Party Chief and the Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu time and again is appealing to the Government of India in various forums for sanctioning the "special category status". When we are talking about the development of the region this will be possible only when States like Andhra Pradesh get the result of promises made in the Parliament.

The Parliamentary Constituency which I am representing i.e. Anantapur is a drought prone area in the last 150 years. Anantapur District receives 2nd lowest rainfall in the country.

---

*Laid on the Table

Hundreds of farmers are committing suicide every year. It is painful to state that our District Anantapur is not in the list of 112 Aspirational Districts.

I thank the Hon'ble President for advising all the MPs to remember the fundamental Mantra/Talisman of Gandhi ji that our decisions should be guided by the poorest and weakest persons in the society.

I also request the Government of India to make decisions by taking the underdeveloped States and underdeveloped regions on priority while they are making decisions, and request them to remember the promises made by the Parliament to the State of Andhra Pradesh.

(ends)

***डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी):** महामहिम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण, का समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जनादेश देश की जनता ने दिया है। माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अनेक योजनाएं बनी। मेरे संसदीय क्षेत्र में उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी की उनके नेतृत्व में मेरी जैसी महिला आदिवासी क्षेत्र से पहली महिला सांसद बनी। इस बार महिला सांसद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 78 चुन कर आयी ये हमारे लिए महिलाआं के लिए गौरव की बात है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस वचन पर देश् विकसित हो रहा है। इस विकास यात्रा में काम करने के लिए सभी भारतीयों ने आर्शीवाद दिये और फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए विश्वास मिला। मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देती हूँ और मुझे अवसर देने पर आभार प्रदर्शित करती हूँ।

(इति)

---

*Laid on the table

*SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI):

*Laid on the Table

1709 बजे

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : माननीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोक सभा के गठन के बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, भारत के सामान्य मानवी की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किन चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, किन चीज़ों पर बल देना चाहते हैं, उसका एक खाका खींचने का प्रयास किया है।

(1710/SPS/KKD)

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, देश के सामान्य मानवी ने जिस आशा, आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है, उसकी एक प्रकार से प्रतिध्वनि है और इसलिए इस अभिभाषण का धन्यवाद एक प्रकार से देश के कोटि-कोटि जनों का भी धन्यवाद है। एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध, समावेशी, ऐसे राष्ट्र का सपना हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने देखा है। उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अधिक गति, अधिक तीव्रता के साथ हम सब को मिल-जुलकर आगे बढ़ना, यह समय की मांग है, देश की अपेक्षा है और आज के वैश्विक वातावरण में यह अवसर भारत को खोना नहीं चाहिए। उस मिजाज़ के साथ हम आगे बढ़ें, हम सभी मिलकर आगे बढ़ें। मैं समझता हूं देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में आने वाली हर चुनौती, हर बाधा को हम पार कर सकते हैं।

इस चर्चा में करीब 60 आदरणीय सांसदों ने हिस्सा लिया। जो पहली बार आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, चर्चा को सार्थक बनाने का प्रयास किया। जो अनुभवी हैं, उन्होंने भी अपने-अपने तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाया। श्रीमान् अधीर रंजन चौधरी जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री दयानिधि मारन जी, श्रीमान् सौगत राय जी, जयदेव जी, सुश्री महुआ मोइत्रा, पी.वी. मिधुन रेड्डी जी, विनायक बी. राउत, राजीव रंजन सिंह जी, पिनाकी मिश्रा, कुंवर दानिश अली, श्री नामा नागेश्वर राव, डॉ. अमोल रामसिंह, मोहम्मद आजम

खां, असादुद्दीन ओवैसी, श्री प्रताप चन्द्र सारंगी, डॉ. हिना गावित समेत अन्य सभी का इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए मैं ह्रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह बात सही है कि हम सब मनुष्य हैं। तीस दिन में जो मन पर छाप रहती है, प्रभाव रहता है, निकलना जरा कठिन होता है और उसके कारण चुनावी भाषणों का भी थोड़ा-बहुत असर नजर आता था। वही बातें यहां भी सुनने को मिल रहीं थीं। लेकिन शायद वह प्रकृति का नियम है और इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपको भी इस गरिमापूर्ण पद पर, जिस प्रकार से आपने इस सदन का संचालन किया, पूरी चर्चा को सबको विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ाया, आप इस पद पर नए हैं और जब आप नए होते हैं तो कुछ लोगों का मन भी करता है कि जरा आपकी शुरू में ही परेशानी बढ़ा दें। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद भी आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से इन सारी चीज़ों को चलाया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मैं सदन को भी नए स्पीकर महोदय को सहयोग देने के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं।

(1715/KDS/RP)

माननीय अध्यक्ष जी, कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है। एक सरकार को दोबारा चुनकर लाए हैं। पहले से अधिक शक्ति देकर लाए हैं। आज के सामान्य वातावरण में भारत जैसी वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी में हर भारतीय के लिए गौरव करने का विषय है कि हमारा मतदाता कितना जागरूक है। वह अपने से ज्यादा अपने देश को कितना प्यार करता है, अपने से ज्यादा अपने देश के लिए किस प्रकार से वह निर्णय करता है, इस चुनाव में साफ-साफ नज़र आया है और इसलिए देश के मतदाता अनेक-अनेक अभिनन्दन के अधिकारी हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी पूरी टीम को संतोष है कि 2014 में जबकि हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए भी हम अपरिचित थे, लेकिन उन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में कि 'चलो भई, जो भी है, इनसे तो बचेंगे' सोचकर हमें मौका दिया। लेकिन, 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद हर तराज़ू पर तोले जाने के बाद पल-पल को जनता-जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जाँचा है और उसी आधार पर समझा है। और तब जाकर दोबारा

बिठाया है। यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। चाहे जीतने वाला हो, चाहे हारने वाला हो, चाहे मैदान में था, या मैदान के बाहर था, हर किसी के लिए इस विजय को सरकार के 5 साल के कठोर परिश्रम, सरकार के 5 साल का जनता-जनार्दन की सुख-सुविधा के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीतियों को लागू करने का सफल प्रयास, उसको लोगों ने एक बार फिर से अपना अनुमोदन देकर देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है, जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है, वह आपके काम को अनुमोदित करती है। यह सिर्फ चुनाव की जीत और हार, आँकड़े का खेल नहीं है जी, यह जीवन की उन आस्था का खेल है, जहाँ कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता-जर्नादन के लिए जीना, जनता-जनार्दन के लिए जूझना, जनता-जनार्दन के लिए खपना यह क्या होता है, यह 5 साल की अखण्ड एकनिष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है, तो उसका संतोष एक अध्यात्म की अनुभूति कराता है और इसलिए कौन हारा, कौन जीता, इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरी सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है।

(1720/SJN/RCP)

मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं। इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के सपने, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा, मेरी नज़र में रहती है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में जब देश की जनता ने हमें अवसर दिया, मुझे पहली बार सेन्ट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था। सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज उन पांच सालों के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबाकर भी व्यक्त किया है।

जब चर्चा का प्रारंभ हुआ, पहली बार सदन में आए श्रीमान् प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत

किया और जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं कि उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं, तो भी बात पहुंच चुकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में मार्गदर्शन किया है, उन्होंने एक बात हमेशा कही है और वह अंत्योदय की कही है। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही है। चाहे पूज्य बापू हों, चाहे बाबासाहेब अंबेडकर हों, चाहे लोहिया जी हों या दीनदयाल जी हों, हर किसी ने इसी बात को कहा है। पिछले पांच सालों के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा कि जिसका कोई नहीं है, उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आज़ाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या उसको बढ़ाने में बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग 'हम' करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं। हमने जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया, जिसमें देश के सामान्य मानवी को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। क्या इस आज़ादी के लिए वह निकला था? क्या सामान्य मानवी उसके हक की चीज है? सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वह हकदार है, वह उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए और मिले या न मिले, वह शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि यह सब तो ऐसे ही चलता है। मैं जानता हूं कि इन चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है। राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है। 70 साल की बीमारियों को पांच साल में पूरा करना कठिन होता है, लेकिन मैं इस संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने वह दिशा पकड़ी है, कठिनाइयों के बावजूद भी, हमने उस दिशा को नहीं छोड़ा है। न डायवर्ट न डाइल्यूट। हम उस मकसद से चलते रहे और यह देश दूध का दूध, पानी का पानी भली भांति कर सकता है। उसने शौचालय को सिर्फ चार दीवार नहीं समझा।

(1725/KN/SMN)

घर में चूल्हा पहुँचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका, वह तो मैं नहीं समझा। उस हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकर यह क्यों कर रही है सरकार। मैंने तो चूल्हा माँगा

नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना ज़िन्दगी गुजार दी थी, वह क्यों कर रहे हैं? पहले प्रश्न उठाता था कि क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि यह क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते हैं से लेकर क्यों करते हैं, यह यात्रा बड़ी लम्बी थी, लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था, जिसने अपनेपन को जग-उजागर कर दिया और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करवा रहा है और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

यह बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेल्फेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जब जूझ रहा है तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हो, लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए। गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ-साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए, जहाँ एक तरफ वेल्फेयर को लेकर ध्यान केन्द्रित हो, सामान्य मानवी की ज़िन्दगी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरपूर प्रयास हो और दूसरी तरफ वह पटरी हो, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। देश को आधुनिक बनाने के लिए, योजनाओं को लागू करें और हमने उन दोनों तरफ बल दिया। हाइवेज हों या आई-वेज हों, वाटरवेज हों, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्ट-अप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर चन्द्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो, इन सारी चीज़ों को एक आधुनिक भारत, अनेक चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है।

यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गईं, कुछ तीखी बातें भी बताई गईं। ज़्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गईं। हर एक का अपना-अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया कि हमारी ऊँचाई को कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लम्बी करने के लिए ज़िन्दगी खपा देते हैं। आपकी ऊँचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊँचे चले गए हैं, इतने ऊँचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बन्द हो गया है। आप इतने ऊँचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊँचे चले गए हैं कि जो जमीन पर

है, वह आपको तुच्छ दिखता है और इसलिए आपका और ऊँचा होना, मेरे लिए अत्यन्त संतोष और आनन्द है। मेरी कामना है कि आप और ऊँचे बढ़ें। हमारी आपसे ऊँचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊँचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है, हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पाकर देश को और मजबूती देना, यह हमारा रास्ता है। इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएँ ही देते रहेंगे, और ऊँचे, और ऊँचे, और ऊँचे जाइए।

(1730/CS/MMN)

मैं देख रहा हूँ कि बार-बार चर्चा आती है, लेकिन thus far and no further एक बार पूरा हो जाना चाहिए। यह बात सही है कि कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए लगाव होता है। अगर उनका नाम नहीं आता है, तो उन्हें परेशानी हो जाती है। नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया, उन्हें ऐसा महसूस होता है। ऐसा हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं चुनौती देता हूँ कि 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़िए, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, उसे रखो। इतना ही नहीं, अभी के भाषण में भी एक बार डॉ. मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे हर्ष होता। वे बड़े-बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन लाल किले पर से शायद, वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधान मंत्री हूँ, जिसने दो बार यह कहा है कि आजादी से लेकर अब तक केन्द्र और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई हैं सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूँ, आज दोबारा कहता हूँ।

हम वो लोग नहीं हैं और इसलिए बार-बार यह कहना, हाँ उनकी अपेक्षा है कि वही नाम आए, वह एक अलग बात है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है? मैं जानकारी के लिए उदाहरण देता हूँ, तभी आपको समझने में

सुविधा होगी। सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्य मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए थे, "गोल्डन जुबली ईयर" था। उस "गोल्डन जुबली ईयर" के अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ। मैंने सरकार को सूचना की कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं, उन भाषणों को कम्पाइल करके उनका एक ग्रंथ निकाला जाए और वह हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम का उसमें लेखा-जोखा था। वे हमारे दल की सरकारें नहीं थीं, लेकिन यह हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है और वह पूर्णतया सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कम्पाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है। वह आज भी उपलब्ध है, उसे जाकर देखें। इसलिए यह कहना कि देश में पहले जो काम हुए हैं, उन्हें हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं और बार-बार हमें सुनाते रहना, यह सुनाने का उन्हीं को हक है, जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉ. मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है जी। यह हम हैं, हमारी सोच है।

प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं, उनका देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं।

(1735/RV/VR)

यह कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनन्द नहीं हो रहा है, लेकिन बार-बार हमें सुनाया जाता है तो फिर thus far and no further. आज मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि कृपा करके बार-बार ऐसा मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं हैं। जब

हम कहते हैं कि सवा सौ करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है तो सवा सौ करोड़ देशवासियों में सब कोई आते हैं। इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें।

माननीय अध्यक्ष जी, कल तो बड़े नारे बुलवा लिए गए, किसने किया, किसने किया, किसने किया! आज 25 जून है साहब! बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि 25 जून क्या है, अगल-बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात - देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिन्दुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था और सिर्फ, किसी की सत्ता चली न जाए, इसलिए। न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वह जीता-जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हमें लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपने समर्पण, अपने संकल्प को और ताकत के साथ समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने का पाप करना, इन चीज़ों को कोई भूल नहीं सकता है। उस समय जो-जो भी इस पाप के भागीदार थे, यह दाग कभी मिटने वाला नहीं है। इस दाग को बार-बार स्मरण करने की भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कोई ऐसा पैदा न हो, जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए इसे याद करना जरूरी है, किसी को भला-बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, यह समझाने के लिए भी, लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, यह स्मरण कराना जरूरी होता है, किसी को बुरा-भला कहने के लिए नहीं होता है। उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर किसी को लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनकी ताकत देखिए। जाति, पंथ, सम्प्रदाय, सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था, लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुन: प्रस्थापित किया था। यह मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार देश ने जाति, पंथ,

सम्प्रदाय, भाषा, सबसे परे उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए मतदान किया है।

(1740/MY/SAN)

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है। एक 'गांधी 150' और दूसरा 'आज़ादी 75' व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज़्बा पैदा करती है, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती है, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए समपर्ण के भाव से जोड़ देती हैं। भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। आज हमारे पास आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से बड़ी कोई यादें नहीं हैं। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका पुण्य स्मरण करते हुए, जिन्होंने यातानाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी माँ भारती के लिए न्योछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आज़ादी के लिए जन आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए, इन तारीखों का एक अवसर बना कर के हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं। यह सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, यह पूरे देश का एजेंडा होता है। इसमें दल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश होता है। राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है। हमारे लिए संकल्प की घड़ी है। चुनाव के मैदान में तू तू मैं मैं जो करना है, कर लीजिए, लेकिन एक अवसर है, इसको हम पकड़ें। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज 'आज़ादी 75' पर देश के लिए जीने का मिजाज़ पैदा करने का हमें अवसर मिला है।

मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, मैं देश के सभी सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमें जो आदेश दिया है, हम से जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आए और इन दो महत्वपूर्ण अवसरों

को नए भारत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, हम प्रयास करें।

हिन्दुस्तान की गुलामी का काल खंड लंबा रहा, लेकिन उस गुलामी के काल खंड में कोई भी काल ऐसा नहीं था कि किसी न किसी कोने में से आज़ादी की आवाज़ न उठी हो, त्याग-बलिदान की परंपरा न चली हो। 1857 में एक संगठित रूप प्रकट हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने देश के सामान्य मानवी को आज़ादी का सिपाही बना दिया। अगर वह झाड़ू लगाता है तो भी आजादी के लिए, वह बच्चों को शिक्षा देता है तो भी आज़ादी के लिए, वह खादी का वस्त्र पहनता है तो भी आज़ादी के लिए, यह पूज्य बापू ने पूरे हिन्दुस्तान में माहौल बना दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन-जन जुड़ गया। 1942-47 आज़ादी की जंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग प्वाइंट है। क्या हम गांधी -150 और आज़ादी - 75 को उस 1942 की स्पिरिट के साथ देश को संकटों से मुक्ति दिलाना, देश को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, अधिकार से ऊपर उठकर कर्त्तव्य पर बल देना, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश को प्रेरित करना, क्या हम इसके लिए आगे आ सकते हैं? मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखा है। लोगों को आश्चर्य होता था, जब आज़ादी की मांग हो रही थी, मजाक भी उड़ाया जाता था कि कैसे चलाओगे, क्या चलाओगे, लेकिन आज़ादी के दीवानों के अंदर एक ललक थी।

(1745/CP/SM)

आजादी के लिए मरने वालों का एक मिजाज था, आजाद भारत के लिए जीने वालों का मिजाज पैदा करना, इस नेतृत्व में क्षमता है। मैं चारों तरफ हाथ घुमा करके कह रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, न मैं इस तरफ कह रहा हूं। हम सब मिल कर इस बात को करें। स्वभावत: मुझे तत्कालीनता में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है, छोटा सोचना मुझे पसन्द नहीं है। इसलिए मुझे कभी लगता है कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है, तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं है।

"जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।"

इस मिजाज के साथ हम आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ आए। इस सरकार को अभी तो तीन सप्ताह हुए हैं, लेकिन हमारे यहां कहावत है कि पुत्र के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। किस प्रकार से तीन सप्ताह में, हमें भी मन करता था कि कहीं जाएं, मालाएं पहनें, जयकारा करें, लेकिन हमने वह रास्ता नहीं चुना। हमें भी लगता था कि इतने चुनाव, छ: महीने से दौड़ रहे थे, चलो कुछ दिन हम भी आराम कर लें, लेकिन वह रास्ता हमें पसन्द नहीं है। हमारा रास्ता वह नहीं है। हम तो देश के लिए जीने के लिए आए हैं। तीन सप्ताह के भीतर-भीतर कितने महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिए। एक गतिशील, समय का पल-पल उपयोग करते हुए देश को कैसे आगे लाया जाना - छोटे किसान हों, छोटे दुकानदार हों, खेत मजदूर हों, उनको साठ साल के बाद पेंशन वाला निर्णय कर लिया। पीएम किसान समृद्धि योजना, हमने वादा किया था कि सभी किसानों को उसके दायरे में लाकर उसका लाभ दिया जाएगा, दे दिया गया। सेना के जवानों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन साथ-साथ समाज की सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके बच्चों को भी वह बेनेफिट मिले, इसका एक बहुत बड़ा निर्णय किया।

मानव अधिकारों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून इस संसद के अंदर हमने लाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थीं, वे पूरी कर लीं। 2022 के सपनों को पूरा करना, मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी प्रेसीडेंट्स की मीटिंग बुलाना, हर चीज को, जितना भी तीन सप्ताह के भीतर-भीतर, सबको साथ लेकर चलने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, एक के बाद एक कामों को उठाया। मैं पूरी गिनती करूंगा तो शायद डेली के तीन काम निकल आएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमने उल्लेख किया है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। यहां चर्चा हो रही थी कि यह डैम बना, वह डैम बना,

ढिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई। अच्छा होता कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उल्लेख होता। हिंदुस्तान में पानी के सम्बन्ध में जितने भी इनीशिएटिव लिए गए थे, वह सारा काम बाबा साहब अंबेडकर के जिम्मे है। लेकिन, एक सीमा के बाहर, बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं है। बाबा साहब ने सेंट्रल वाटरवेज़, इरीगेशन, नेवीगेशन और बाबा साहब पानी के सम्बन्ध में कहते थे, मैं समझता हूं कि आज के लिए बाबा साहब का यह आदेश हम सब के लिए उपयोगी है। वे कहते थे, 'Man suffers more from lack of water than from excess of it.' मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी, उस चिंता को समझते हुए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।

(1750/SK/AK)

यहां पर अनेक डैम्स की बात हुई, उसमें सरदार सरोवर डैम की भी बात हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं, कभी क्या होता है कि ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। इनका ईको सिस्टम ऐसा है कि उसी को आगे बढ़ाने में मजा आता है। सत्य कभी उजागर नहीं करने देते। मेरे आज बोलने के बाद भी सत्य आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने कर्तव्य पालन का संतोष जरूर होगा। सरदार सरोवर डैम - 1961 में पंडित नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वह सपना था, लेकिन नींव रखी गई 1961 में। दशकों तक मंजूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मंजूरियां, और उस समय 6000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था। वह पूरा होते-होते 60,000-70,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। देश की क्या सेवा की आप देखिए? इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। 1986-87 में 6,000 करोड़ का खर्चा 62,000 करोड़ पहुंचा। हमने आकर इसे पूरा किया। मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, मुख्य मंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थीं, तब जाकर यह योजना हुई। अभी मैंने इसे पूरा किया, प्रधान मंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने सारी रुकावटें हटाने का काम किया था। आज करीब चार

करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है। सात महानगरों को, करीब 127 नगर पालिकाओं को और 9,000 गांवों को पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है।

पानी की तकलीफ क्या होती है, राजस्थान और गुजरात के लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए इस बार हमने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया। जल संकट को हमें गंभीरता से लेना होगा। इस सीज़न में भी हम जितना बल जल संचय पर दें, हमें देना चाहिए। मेरी सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना है, सभी एनजीओज़ से प्रार्थना है कि हम देश में पानी का महात्म्य बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करें और सरकारी दायरे से बाहर होकर करें। पानी बचाना है। इस काम को करके हम सामान्य मानवी की जिंदगी को बचाने में मदद कर सकते हैं। पानी का संकट, दो लोगों को सबसे ज्यादा संकट पैदा करता है। गरीब को और विशेषकर हमारी माताओं और बहनों को। हमारे समाजवादी मित्रों का क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोहिया जी बहुत आग्रह से कहते थे कि इस देश की महिलाओं को दो समस्याएं हैं – पानी और पाखाना। लोहिया जी लगातार कहते थे कि इन समस्याओं से माताओं और बहनों को मुक्त करो। पाखाने का संकट था, शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को इज्जत देने का लोहिया जी का सपना पूरा करने के लिए हमने जी जान से काम किया, और अब पानी पर ही इतना बल, और हर घर को जल - इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं कि यह कठिन काम है, बड़े काम हैं, हो सकता है कोई इसे तराजू में तोलकर हमें फेल भी कर देगा कि मोदी, तुम्हें 100 में से 70 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे। जो भी होगा, लेकिन किसी को तो इसे हाथ लगाना पड़ेगा। हमने लगाया है, जल शक्ति मंत्रालय की बात कही है।

जल संचय के साथ और दूसरी जिम्मेदारी जल सिंचन है। दुनिया में प्रूवन है कि शुगरकेन की खेती में माइक्रो इरीगेशन फायदा करता है, लेकिन अभी भी हम फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं। किसानों को कौन समझाएगा? माइक्रो इरीगेशन के लिए कौन समझाएगा? सरकार की योजना है, पैसे मिल सकते हैं। पानी बचाने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसी अनेक चीजें हैं, जिसकी ओर हमें बूंद-बूंद पानी बचाकर देश को कैसे ले जाना है।

एग्रीकल्चर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन पुराने तौर-तरीकों से हमें बाहर आना पड़ेगा। उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, जीरो बजटिंग खेती के जो प्रयोग चल रहे हैं, उसे सफलता मिल रही है। उत्पादन में कोई कटौती नहीं आती है, आज होलिस्टिक हैल्थ केयर के जमाने में क्वालिटी बढ़ रही है।

(1755/YSH/UB)

हम सब ने राजनीति से परे होकर किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना, यह देश के किसानों की भलाई के लिए है, हमें मिलकर के चलना होगा। हमें किसानों को हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। कॉरपोरेट वर्ल्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कोई इनवेस्टमेंट ही नहीं है। उनको हमें प्रेरित करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ नए नीति नियम बनाने पड़ेगे, वरना कोई ट्रेक्टर बना दे और वह मानता है कि उसने इनवेस्टमेंट कर दिया। हमें तो प्रत्यक्ष फूड प्रोसेसिंग में आज देश में वेयर हाउसेज बनाने में, कॉल्ड स्टोरेज बनाने में कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट समय की मांग है और उसको बल देने के लिए हमें काम करना चाहिए। किसानों को एपीओज के द्वारा अधिक से अधिक अवसर देकर के उनके लिए बीज से लेकर के बाजार तक की एक व्यवस्था खड़ी हो, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। उस क्षेत्र पर बल देना पड़ेगा।

पिछली बार जब 2014 में हमने देखा दाल के भाव, यही इश्यू बन गया था, लेकिन देश के किसान का मिजाज देखिए, जब मैंने सिम्पल रिक्वेस्ट की थी कि आप पल्सेज के लिए आगे आइए और मेरे देश के किसानों ने पल्सेज के लिए इस देश की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भरपूर काम किया। दलहन का हुआ, अब हमें देश के किसानों को तिलहन के लिए प्रेरित करना चाहिए और देश को एक बूंद भी एडिबल ऑयल इम्पोर्ट न करना पड़े। मैं समझता हूँ देश के किसानों को प्रेरित कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते है। इन चीजों को लेकर एक फ्यूचर विजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसान की ताकत और देश की रिक्वायरमेंट को हम जोड़कर के काम कर सकते हैं, उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है, आलोचना करने के लिए आँकड़ों का हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनन्द का विषय है, लेकिन किसी और के समय हो बहुत बुरा। इसी सदन में, जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नम्बर पर पहुंचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बैंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज को प्रदर्शित किया गया था। 11 या 13 पर पहुंचे थे। लेकिन जब 6 पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई। अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आना चाहिए। कब तक इतने ऊँचे रहेंगे कि नीचे दिखाई ही नहीं दे और इसलिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सब मिलकर देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है जी, सबका फायदा होने वाला है। मैं मानता हूँ कि इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए। एक सपना लेकर के चलना चाहिए और मुझे विश्वास है हमारे देश में मेक इन इंडिया, मजाक बहुत उड़ा लिया, लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मुझे करने के लिए बहुत काम हैं। लेकिन देश को कुछ चीजों की जानकारी देना जरूरी होता है। हमारे देश के पास करीब दो सौ, सवा दो सौ साल का आयुध बनाने का एक्सपीरियंस है। जब देश आजाद हुआ तब इस देश के पास 18 ऐसी फैक्ट्रीज़ थीं, जो आयुध का निर्माण करती थीं। देश जब आज़ाद हुआ उस समय चाइना आयुध के क्षेत्र में जीरो जगह पर था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था न कोई फैक्ट्री थी। आज चाइना दुनिया में अपने डिफेंस की चीजें एक्पोर्ट करता है और हम दुनिया के सबसे इम्पोर्टर हैं। इस सच्चाई से हमें देश को बाहर लाना है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाकर क्या करेंगे जी?

(1800/RPS/KMR)

हो सकता है कि रात को अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन देश का भला नहीं होगा। इसलिए इसे और अच्छा कैसे करें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी, एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यगण। छः बज गए हैं, अगर आपकी सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, सहमति है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र मोदी: अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मै सदन का भी आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

भारत दुनिया की पहली पांच इकोनॉमीज में कैसे प्रवेश करे, भारत में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें, मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा दें, स्टार्ट-अप की दुनिया में हमारे नौजवान बहुत कुछ कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। हम देश में इन चीजों को कैसे बल दें और हम अपने नौजवानों को रोजगार भी दें।

हमारे देश में टूरिज्म की बहुत संभावना है, लेकिन हमने ही अपने देश के विषय में इतना हीन भाव पैदा कर दिया है और उसके कारण विश्व के लोगों को हिन्दुस्तान के विषय में आकर्षित करने में गर्व हो, हम कम पड़ गए हैं। स्वच्छता के अभियान ने एक ताकत दी है। हम टूरिज्म पर बल दे सकते हैं, भारत में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और दुनिया में भारत की एक नई पहचान हम टूरिज्म के माध्यम से बना सकते हैं। हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना है।

आने वाले दिनों में देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना है। 100 लाख करोड़ रुपये भी कम पड़ जाएंगे, देश की इतनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतने बड़े सपनों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और दुनिया भर से हमें जो भी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करना है। इन सारी चीजों के पीछे हमारा सपना है – नया भारत। हमारा सपना है – आधुनिक भारत और हमारा सपना है – ईज़ ऑफ लिविंग, सामान्य मानवी की जिन्दगी में सुगमता। अपने सपनों को साकार करने के लिए सारे अवसर उसके पास उपलब्ध हों। इस प्रकार की

व्यवस्थाओं को विकसित करना और उन्हीं बातों को लेकर, चाहे गांव हो या शहर हो, हरेक के लिए समान अवसर को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

आज दुनिया में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। देश के पास युवा शक्ति है, लेकिन क्या विश्व की आवश्यकता के अनुसार हम अपने युवाओं को तैयार कर पा रहे हैं? हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो हमें उसके स्केल को भी बढाना पड़ेगा और हर स्कोप को हमें कैप्चर करना पड़ेगा। हम आधुनिकता की दिशा में कैसे ले जाएं, राष्ट्रपति जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है। सरकार ने एक मार्केट के लिए 'जेम' की व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि जहां आपकी भी राज्य सरकारें, जिस दल की हों, वे इस 'जेम' पोर्टल का उपयोग करें। बहुत बड़ी मात्रा में पैसे बच सकते हैं और बहुत से लोगों की मदद हो सकती है और छोटे से छोटे लोगों द्वारा भी अपना उत्पाद सरकार के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। उस दिशा में हमें काम करना चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं डाला। यह इमरजेन्सी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, यह लोकतंत्र है और यह काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं। अगर किसी को जमानत मिलती है तो एंज्वाय करे, उसमें क्या है। बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ईश्वर ने हमें जितनी भी बुद्धि और शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। देश ने हमें इतना दिया है कि हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में काम आ सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय में देश में मतभेद क्यों होना चाहिए? यह मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है और यह मानवता को चुनौती है। जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं, उन सब को इकट्ठा होकर, इस बात को लेकर लड़ना होगा।

(1805/RAJ/SNT)

हम महिला सशक्तिकरण की बात करें। कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, पर पता नहीं क्यों, वे इतने ऊंचे हैं कि कुछ चीजें दिखती नही, छूट जाती हैं। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिन्दू कोड बिल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला ली। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला – शाहबानो का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा-सा वातावरण बनने की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वह मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर आए हैं, इस देश के नारी के गौरव को बढ़ाएं।...(व्यवधान) इसको किसी भी संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेष कर से, एक बात जो उस समय शाहबानो का मसला चल रहा था। उस सारे कारोबार में जो मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, वह चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं है, मैंने जो सुना है, वह मैं बताता हूं। उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थीं, वह उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है, जब शाहबानो का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, "मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है।" देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। If they want to lie in the gutter, let them be. हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए...(व्यवधान) मिल जाएगा।...(व्यवधान) मिल जाएगा।...(व्यवधान) मैं आपको यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने 'गांधी 150' और 'आजादी 75' की बात कही है। हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही सारी बातें केन्द्रित रहीं। हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा। एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडाइम शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की

तरफ ले चलें और जनप्रतिनिधि का भी यह काम है – जनचेतना जगाना। जनप्रतिनिधि का काम है, ऐसे समय नेतृत्व करना और यह विषय ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं। हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, "Every right carries with it a corresponding duty." लोहिया जी कहते थे, "कर्तव्य निभाते समय, नफा-नुकसान नहीं देखा जाता।" मैं यह क्वोट जरा विस्तार से बताना चाहता हूं। हो सकता है कि इसके कारण सभी लोगों को इस राह पर आने में अच्छा रहेगा।

(1810/IND/RK)

बहुत पुरानी बात है। जो क्वोट है – 'दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख यह है कि यहां सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और इन्हीं कर्तव्यों से अधिकार निकलते हैं। आज के आधुनिक भौतिकवादी विश्व में जहां हर तरफ टकराव दिखाई पड़ते हैं, वहां हर कोई अपने अधिकारों और सुविधाओं की बात करता है। शायद ही कोई कर्तव्यों की बात करता है। यही टकराव की वजह है। ये वास्तविकता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अगर कर्तव्यों को भूल जाएं, तो ये अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएंगी।' मैं समझता हूं कि यह साफ-साफ दर्शन है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस महापुरुष ने यह बात कही है, उसके बाद उसको भूला दिया गया है। उस महापुरुष का पुन: स्मरण करते हुए हम इस बात को क्या आगे ले जा सकते हैं? वे महापुरुष थे, जिन्होंने 14 जुलाई, 1951 को कहा था, जब चुनाव से पहले कांग्रेस का पहला मैनिफेस्टो घोषित हो रहा था, उस घोषणा के समय यह पैराग्राफ पंडित नेहरू जी ने बोला था। मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू जी ने जो सपना वर्ष 1951 में देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए, देश को कर्तव्य की राह पर ले जाने के लिए पंडित जी की उसी इच्छा को समझकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हम सब मिलकर तय करें और हम आगे चलने का प्रयास करें। हमारे देश का अनुभव ऐसा है कि जब महात्मा गांधी ने देश के नौजवानों को कहा था कि किताबें छोड़ो और आजादी के लिए चलो, तो लोग निकल पड़े। गांधी जी ने कहा था कि विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, तब लोग चल पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि

एक टाइम खाना छोड़ दो, अन्न का उत्पादन करो, देश ने कर दिया। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति ने कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दी। मतलब कि देश तैयार है, देश तैयार है। आइए, हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए राजनीति की अपनी सीमाओं से भी ऊपर देश होता है, दल से बड़ा देश होता है। देश के करोड़ों लोगों की आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो दिशा-निर्देश दिये हैं, राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए हम सिर्फ उनके भाषण का धन्यवाद ही नहीं, उस भाषण की स्पिरिट को जी करके राष्ट्र हित में कुछ करके सच्चे अर्थ में धन्यवाद पारित करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं सभी इस चर्चा को समृद्ध बनाने वाले आदरणीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:-

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए":-
>
> > 'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 जून, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं"।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल बुधवार, दिनांक 26 जून 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1814 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>